

डो० जी० कसूलस



आत्माराम राण्ड संस

काश्मीरी गेट, दिल्ली

अनुवादक
वासुदेव भा

COPYRIGHT © BY D. G. Kousoulas

प्रकाशक

रामलाल पुरी, संचालक

आत्माराम एण्ड सम

काश्मोरो गेट, दिल्ली-६

मूल्य	: एक	रुपया
प्रथम संस्करण	: १ ६ ५ ६	
आवरण	: योगेन्द्रकुमार	लल्ला
मुद्रक	: मवीज प्रेस,	दिल्ली-६-

लेखक-परिचय

दिमित्रियोस जी० कसूलस फुलब्राइट छात्रवृत्ति लेकर सिराक्युस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए १९५१ में अमेरिका आये थे। इससे पूर्व वह यूनान की एथेन्स यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुके थे।

कसूलस खलकिस, यूनान के एबोआ द्वीप में पैदा हुए और अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने यूनान के एक दूसरे द्वीप क्रीट में बिताए। १९४३ में जर्मन सैन्य-अधिकारियों से कुछ भगड़ा हो जाने के कारण वह यूनान की मुख्य भूमि पर चले गए। १९४४ के दिसम्बर में कम्युनिस्ट क्रान्ति के दरम्यान उन्हें कम्युनिस्ट गुरिल्लों ने गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन उन्हें गोली मारी जानेवाली थी, उसके एक दिन पूर्व ही ब्रिटिश कमाण्डर जनरल स्कोफी और 'इलास' गुरिल्लो में समझौता हो गया और वह बाल-बाल बच गए। ब्राइड्स, १९४७-४९ के कम्युनिस्ट विद्रोह के समय, वह मेसिगेनिया में यूनानी सेना के साथ काम कर रहे थे।

सिराक्युस यूनिवर्सिटी से १९५३ में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एम. ए. किया। उनके सशोध-निबन्ध को उसी साल सिराक्युस यूनिवर्सिटी प्रेस ने 'दि प्राइस ऑफ फ्रीडम, ग्रीस इन वर्ल्ड अफेयर्स १९३९-५३' नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक का यूनानी अनुवाद १९५५ में प्रकाशित हुआ। अप्रैल, १९५५ से वह विश्व की घटनाओं का साप्ताहिक विश्लेषण प्रस्तुत करते रहे हैं, जो यूनान के छ दैनिक पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं।

१९५६ में सिराक्युस यूनिवर्सिटी ने श्री कसूलस को 'डॉक्टर ऑफ फिलासफी इन इण्टरनेशनल रिलेशंस' की उपाधि से विभूषित किया।

डॉ० कसूलस को अल्पविकसित देशों तथा अमेरिकी और सोवियत रूस की आर्थिक संस्थाओं और रिवाजों की अच्छी जानकारी है, उनकी यही जानकारी इस असाधारण और रोचक पुस्तक की अद्वितीय पृष्ठ-भूमि रही है।

प्रस्तावना

जन-जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य को लेकर संसार में आज स्पष्टतः दो महान दर्शन एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। एक दर्शन तो है अधिनायकवादी शासन-तंत्र का, जिसके अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था की सम्पूर्ण सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित होती है। व्यक्ति के पृथक् अस्तित्व का उतना महत्त्व नहीं होता और वह राज्य-सत्ता के इंगित पर चलनेवाला एक पुर्जा मात्र रह जाता है।

इसके विपरीत दूसरा दर्शन है लोकतंत्र का। इसके अन्तर्गत 'व्यक्ति के चरम विकास' को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है। इसमें वर्ग विशेष का अस्तित्व समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि मुख्य ध्येय यह होता है कि सभी वर्गों के सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समाज और राज द्वारा सुलभ सुविधाओं और अवसरों का लाभ समान रूप से मिल सके।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने इस दूसरे मार्ग पर ही चलने का निश्चय किया। हमारी पञ्चवर्षीय योजनाओं का प्रेरणा-स्रोत हमारा यही सकल्प है। कहना नहीं होगा कि, अभाव और कष्ट की इस अवस्था से लाखों-करोड़ों इन्सानो को मुक्ति दिलाना कोई आसान काम नहीं है। कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब हम इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए बाध्यता के मार्ग का अनुसरण न कर सबकी इच्छाओं को प्रश्रय देने के रास्ते पर चलना तय करते हैं—सर्वोदय का सकल्प सामने रखते हैं। यह बात नहीं कि, गरीबी और अभाव से लड़ाई केवल भारत में ही हो रही है, सम्पूर्ण संसार में यह आर्थिक संग्राम चल रहा है। हाँ, इसके रूप भिन्न-भिन्न हैं, रास्ते अलग-अलग हैं।

लोकतंत्री ढाँचे के अन्तर्गत रहते हुए भी जन-सामान्य का जीवन-स्तर उठाने की इस समस्या को सुलझाते हुए हम अमेरिकियों के अनुभवों

पर गौर कर सकते हैं। लोकतंत्री उद्योगवाद के मार्ग पर चक्कर अमेरिका ने आर्थिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति की है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अभाव, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी के उन्मूलन का एकमात्र मार्ग निरकुश अधिनायकवाद ही नहीं है, लोकतंत्री तरीकों से भी इन्हे मिटाया जा सकता है—आर्थिक उन्नयन के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह ठीक है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था 'पूँजीवादी' है, लेकिन यह पूँजीवाद उस पूँजीवाद से बिल्कुल भिन्न है जो मार्क्स को लन्दन के गन्दे और सकुचित कारखानों में दिखाई दिया था। तथापि यह नवीन प्रकार की पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था अब भी परीक्षण के दौर से गुजर रही है, और शायद कोई अमेरिकी भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनकी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था शत प्रतिशत सफल सिद्ध हुई है।

फिर भी, इस अर्थ-व्यवस्था ने कुछ चमत्कारी परिणाम दिखाये हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिका की जनसंख्या सप्ताह की कुल आबादी की लगभग १४ प्रतिशत है और सप्ताह के कुल प्राकृतिक साधन-स्रोतों का १७ प्रतिशत भाग अमेरिका में है। तथापि आज अमेरिका का उत्पादन संसार के कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत है। दुनिया भर के कारखानों में जितनी वस्तुओं का निर्माण होता है उनका लगभग एक तिहाई भाग अमेरिका में बनता है।

और, इस भारी सफलता का मूल मन्त्र है व्यापक उत्पादन, व्यापक खपत और व्यापक क्रय-शक्ति। यूनान के सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार डॉ० डी० जी० कसूलस ने अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की इस त्रिविध क्रियाशीलता का बड़े निकट से अध्ययन किया है। आशा है उनकी 'कीट इकोनॉमिक प्रोग्रेस' का यह हिन्दी रूपान्तर पाठकों को दिलचस्प लगेगा।

वासुदेव झा

वित्त वाणिज्य समीक्षक, 'नवभारत टाइम्स'

भूमिका

“...आज मानव और शासन के दो महान दर्शन चल रहे हैं और यह आज के जीवन का केन्द्रीय तथ्य है। ये दोनों ही दर्शन संसार के लोगों की मैत्री, श्रद्धा और समर्थन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं।”

इन शब्दों के साथ प्रेसिडेंट आइजन हावर ने मानवता के आज के व्यापारिक मर्म को छू लिया है। वास्तव में, हमारे युग का एक बुनियादी मसला यही है कि क्या लोग अपनी राजनीतिक और वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सर्वसत्ताधारी राज्य की बलिवेदी पर होम किए बिना भी आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? यह कोई कोरे वाद-विवाद का ही प्रश्न नहीं, मानवता का भविष्य बहुत कुछ इसी पर निर्भर होगा कि लोग इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं।

सम्य समाज के आरम्भ से ही, जिनमें राजनीतिक अथवा आर्थिक शक्ति लोगों पर हावी करने की सामर्थ्य थी वे ही नेतृत्व और निर्देश करने की स्थिति में थे। हमारी आज की दुनिया में, एक अधिनायकवादी राज्य राजनीतिक और आर्थिक, इन दोनों ही तत्वों को एक सर्वसत्ताधारी ढाँचे में संयोजित करता है, और इस ढाँचे का नियंत्रण एकमात्र राजनीतिक आर्थिक पिरामिड पर बैठे मुट्ठी भर लोग ही करते हैं। इसके विपरीत-आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति—चाहे उसका स्रोत राजनीतिक गति-विधियाँ हो अथवा आर्थिक—पृथक्, पर परस्पर निर्भर हजारों इकाइयों के सुपुर्द रहती है। क्योंकि ये इकाइयाँ समाज के प्रायः सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए कोई भी सुविधा-सम्पन्न दल या वर्ग सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे पर अपना एकच्छत्र नियंत्रण स्थापित कर नहीं सकता।

किसी भी उन्नत समाज की एक बुनियादी विशेषता है उसका आलोचक आधार। इस माने में, अमेरिका और सोवियत रूस में ए

समानता है : दोनों ही औद्योगिक राज्य हैं। लेकिन, यह समानता यहीं तक है। सोवियत रूस में औद्योगिक व्यवस्था सर्वसत्ताधिकारी राजनीतिक आर्थिक ढांचे का एक अंग है, जब कि अमेरिका की औद्योगिक व्यवस्था एक लोकतंत्री ढांचे के अन्तर्गत संचालित होती है। अमेरिकी लोकतन्त्र के इन्हीं सामान्य पहलुओं के आधार पर आज की अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत काम करनेवाले कुछ सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से निखारने के लिए इसे लोकतन्त्री उद्योगवाद का नाम दिया जा सकता है।

अमेरिका औद्योगिक व्यवस्था का लोकतन्त्रीय ढांचा है। अतः आज के मसलों के समाधान की खोज में भटकती दुनियाँ के लिए अमेरिकियों का अनुभव व्यावहारिक दृष्टि से अर्थपूर्ण है। वैयक्तिक जीवन-स्तर के रूप में लोकतन्त्री उद्योगवाद की अमेरिकी व्यवस्था की आश्चर्यजनक उन्नति और उपलब्धियाँ इस बात का उत्साहवर्द्धक प्रमाण हैं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि उस समाज में अधिक भली प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, जहाँ 'व्यक्ति' स्वतन्त्र है।

बहुत से लोग यह सोचते प्रतीत होते हैं मानो अमेरिका की प्रगति कहीं शून्य से ही आविर्भूत हुई है। वे उन तत्त्वों की उपेक्षा कर देते हैं, जिनके कारण यह प्रगति सम्भव हुई है। ये तत्त्व हैं राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था। कुछ लोग आर्थिक विकास की सर्वसत्ताधिकारी राज्य-व्यवस्था के अनुयायी होते हुए भी जानते हैं कि वे तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने को एक विचित्र स्थिति में पाते हैं। वे अमेरिकी उपलब्धियों को तो स्वीकार करते हैं; पर उस व्यवस्था, विशेषकर पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को मान्यता देने से कतराते हैं।

हमारे युग के अन्य अनेक शब्दों की तरह 'पूँजीवाद' शब्द के भी इतने अर्थ हो गये हैं कि 'पूँजीवाद' में अन्तर्निहित अर्थ का सही बोध नहीं हो पाता। कुछ लोगों की दृष्टि में तो यह एक बदनाम शब्द है। इसका सम्बन्ध अपने-आप उस स्थिति से हो जाता है, जिसमें बहुसंख्यक

नोग तो नितान्त गरीबी से ग्रस्त हो, और मुट्ठी भर लोग दूसरों को भड़काने वाली सम्पन्नता के अधिकारी हो। मैं स्वीकार करूँगा कि आज से ७ वर्ष पूर्व फुलब्राइट छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका जाने और वहाँ पूँजीवाद को नजदीक से देखने से पूर्व मेरे मन में भी ऐसी ही भ्रान्ति थी।

पूँजीवादी देश का जो नक्शा मेरे सामने आया उसे देखकर मैं चक्कर में पड़ गया—वहाँ के बहुमुख्यक न तो कंगाल थे और न ही मुट्ठी भर लोग सर्वशक्तिमान धनिक। पाँच वर्ष तक मैं इस विषय का बड़ी उत्सुकतापूर्वक अध्ययन करता रहा। अन्ततोगत्वा मुझे विश्वास हो गया कि एक ऐसा भी पूँजीवादी देश है, जिसने श्रेष्ठ प्रगतिशील समाजवादी चिन्तकों की सैद्धान्तिक मार्गों और आश्वासनों, विशेष रूप से राष्ट्रीय सम्पत्ति के उचित बँटवारा सम्बन्धी उनकी खोज को किसी न किसी तरह मूर्त रूप दे दिया है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, अमेरिका में पुराने प्रकार के पूँजीवाद का स्थान भिन्न सिद्धान्तों पर आधारित एक नयी अर्थ-व्यवस्था ने लिया है।

मैंने अनुभव किया कि, जो कुछ मैंने सीखा है, उसकी ओर यूनान के अन्य भाइयों का ध्यान आकृष्ट करूँ। कारण, कुछ समय पूर्व उनके मन में मेरी ही तरह अमेरिका की महानता के कारणों की गदली और अव्यावहारिक धारणा थी। मैंने आधुनिक अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचारों को १५ लेखों की एक माला के रूप में प्रस्तुत किया। ये सारे लेख यूनान के ६ दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुए थे। इसके अतिरिक्त अमेरिका तथा दुनिया की घटनाओं पर 'लेटर्स फ्रॉम वाशिंगटन' शीर्षक नियमित स्तम्भ के अन्तर्गत एक राजनीतिक समीक्षा भी प्रकाशित हुई। उन लेखों पर जो अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, उसने मुझे यह पुस्तक लिखने को प्रोत्साहित किया है। यह पुस्तक अंग्रेजी में इसलिए लिखी है ताकि दुनियाँ के अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें।

तथापि, यह अमेरिकी व्यवस्था कोई काल्पनिक रामवाण नहीं है,

जो दुनिया की सारी सामाजिक और आर्थिक दुराइयों को चुटकी बजाते ही दूर कर दे। वस्तुतः, अमेरिकी व्यवस्था के विकास के लिए पहले से कोई बना-बनाया खाका नहीं था, ये तो कुछ लचीले सिद्धान्त हैं, जो लोकतंत्र के ढाँचे के अन्तर्गत वर्षों का परीक्षण और गलतियों के परिणामस्वरूप निकले हैं। सबसे अर्थपूर्ण बात तो यह है कि यही सिद्धान्त वास्तविक अनुभवों की खरल में रगड़ खाने के बाद आर्थिक विकास के सम्बन्ध में मार्क्सवादी मान्यताओं की भ्रांतियों और गलतियों को प्रमाणित कर देते हैं।

संक्रमण और विलास की स्थितियों से निरन्तर गुजर रही इस दुनिया में कट्टरता और लीक पीटने की प्रवृत्ति प्रगति को रोकती है और समस्याओं के समाधान में इनसे बाधा पहुँचती है। क्योंकि अमेरिकी सिद्धान्तों को आवश्यकतानुसार तोड़ा-फोड़ा जा सकता है, इसलिए वे देश भी, जिनकी स्थिति अमेरिका से बिल्कुल भिन्न है, गरीबी और गंदगी से दूर उत्तम और समृद्ध भविष्य के मार्ग पर चलते हुए इन सिद्धान्तों को आपका निर्देश-स्तंभ बना सकते हैं।

परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के इस जंगल में लोगों को अपना मार्ग निर्धारित कर सकना चारों ओर व्याप्त भ्रान्तियों और जान-बूझकर फैलायी गई विद्रूपता के कारण मुश्किल हो रहा है। इन सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने के पीछे मेरी एकमात्र आशा यही रही है कि इससे छोटे पैमाने पर ही सही उन भ्रान्तियों और विद्रूपताओं के निवारण में, सहायता मिलेगी। एक कहावत भी है—“अधकार को कोसने से अच्छा है कि एक छोटा-सा दिया जला लो।”

—डी. जी. के.

क्रम

प्रथम भाग

१. क्या अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था सचमुच कोई भिन्न चीज है ? ... ३

अमेरिका की आर्थिक शक्ति के साधन

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी नयी बात

२. अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की कुछ बुनियादी विशेषताएँ ... १०

कम लाभ पर व्यापक उत्पादन

व्यापक क्रय-शक्ति

उपभोक्ता बाजार का द्विविध विस्तार

प्रतियोगिता के रूप

नये माल और उत्पादक तरीकों की निरन्तर खोज

व्यापार और शिक्षा

उत्पादन क्षमता और मानव सम्बन्ध

प्रतिभाशाली लोगों की तलाश

उद्योगगति के लिए नई चिन्तन धारा

विज्ञापन का महत्त्व

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था और मजदूर यूनियन

अमेरिकी शासन सन्तुलन-तत्त्व के रूप में

द्वितीय भाग

३. मुनाफा क्या है ?

... २३

बड़े मुनाफे का अर्थ शोषण है ?

मुनाफा पूँजी के स्रोत के रूप में

मुनाफे के अन्य कार्य

४. उत्पादन-क्षमता, मजदूरी और मूल्य ... ३०

व्यापक उत्पादन क्या संस्कृति का शत्रु है ?

अधिक मजदूरी और कम मूल्य

उत्पादन क्षमता कैसे बढ़नी है ?

उन्नत उत्पादन और वर्द्धमान जीवनस्तर

५. व्यापक उपभोक्ता बाजार ... ४३

व्यापक उपभोक्ता बाजार के लिए प्रारम्भिक बातें

व्यापार में आनेवाली मानवीय बाधाओं को दूर करना

परिवहन तथा संचार का योग

वैयक्तिक आय तथा उपभोक्ता बाजार

वैयक्तिक आयों का पुनःस्तरीकरण

उपभोक्ता ऋण तथा अमेरिकी बाजार

६. प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार ... ५५

एकाधिकार अथवा मूल्य-प्रतियोगिता

एकाधिकारवाले तरीकों का प्रतिरोध

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के कुछ रूप

७. व्यापार की दुनिया ... ७०

कार्पोरेशन

जन-पूँजीवाद

अनुसन्धान तथा विकास

व्यापार और शिक्षा

स्वतन्त्र व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था में विज्ञापन

प्रवृत्ति और उद्देश्य

८. संघटित मजदूर ... ८७

मजदूर यूनियनों के प्रमुख उद्देश्य

अमेरिका में श्रम-आन्दोलन का विकास

अधिकों द्वारा सन्तुलन

मजदूर यूनियन की प्रवृत्तियाँ

६. स्थायित्व की खोज

... ६६

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व

आर्थिक अस्थिरता के कारण

स्थायित्व की सुरक्षा के साधन

मुद्रा सम्बन्धी नीतियाँ

वित्तीय नीतियाँ

सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र, सरकार के लिए सहायक

परिशिष्ट

... १११

प्रथम भाग

क्या अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था सचमुच कोई भिन्न चीज है ?

शायद ही ऐसा कोई अमेरिकन होगा, जो इस बात का दावा करे कि उसकी अर्थ-व्यवस्था पूर्णता को प्राप्त हो गई है। मानव के अनुभवों से पैदा होनेवाली प्रायः सभी चीजों की अपनी त्रुटियाँ, अपनी कम-जोरियाँ हैं। इसी प्रकार अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था की अपनी कमियाँ और कमजोरियाँ हैं। यही नहीं, वह निरन्तर विकास की स्थिति से गुजर रही है, नई समस्याएँ और नई-नई आवश्यकताएँ निरन्तर पैदा होती रहती हैं।

पूर्णता का दावा करनेवाले किसी भी कट्टरपंथी को आलोचना के लिए अनेक त्रुटियाँ मिलेंगी। लेकिन, यह कोई रचनात्मक और यथार्थ-वादी दृष्टिकोण नहीं है। महत्त्व इस बात का है कि अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था की प्रक्रिया को समझा जाय और इसी से उसकी उपलब्धियों, सफलताओं का स्पष्टीकरण हो सकेगा क्योंकि तथ्य यह है कि इस धरती पर अमेरिकनो का जीवन-स्तर सबसे ऊँचा हो गया है और वह भी वैयक्तिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता का बलिदान किये बिना। दुनिया की कुल भूमि और आबादी का सिर्फ सात प्रतिशत अमेरिका में है; फिर भी दुनिया में कुल निर्मित माल का ५० प्रतिशत और दुनिया की समस्त जिन्सों और सेवाओं का पैंतीस प्रतिशत से अधिक अमेरिका में पैदा होता है। और, यद्यपि अमेरिकनों का काम का सप्ताह निरन्तर घटाया जा रहा है, तथापि आज उनमें से अधिकतर लोगो को जितना अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा और मनोरंजन के जितने अधिक साधन उपलब्ध हैं, उतने पहले कभी प्राप्त नहीं थे।

अमेरिका की आर्थिक शक्ति के साधन

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की आश्चर्यजनक उत्पादन-क्षमता को अमेरिकन और विदेशी, दोनों प्रायः ध्रुव सत्य मानते हैं। इसके कारण के भिन्न-भिन्न स्पष्टीकरण दिये जाते हैं, इनमें से कुछ तो अशत ठीक हैं और कुछ बिलकुल असम्भव। कुछ लोग इसका सारा श्रेय अमेरिका की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधनों को देते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका बड़ा धनी देश है, उसके पास उर्वर भूमि, विस्तृत वन-प्रदेश और कोयले, तेल, लोहे, तांबे और यूरेनियम की बड़ी-बड़ी खानें हैं। इस छोर से उस छोर तक बहनेवाली उसकी नदियाँ जल-परिवहन, पनबिजली और सिचाई-कार्य के लिए उपयुक्त हैं। उसकी जलवायु सब मिलाकर समशीतोष्ण है।

कुछ लोग यह भी कहेंगे कि अमेरिका को १७ करोड़ उपभोक्ताओं के विस्तृत बाजार का लाभ प्राप्त है। अमेरिका की औद्योगिक और कृषि-जन्य वस्तुएँ निर्वाह रूप में देश के एक तट से दूसरे तट तक जा-आ सकती हैं; ऐसी कोई कृत्रिम रुकावट नहीं है, जिससे उनका खर्चा बढ़े अथवा उनके प्रचार और प्रसार में बाधा पहुँचे। उदाहरणार्थ, एक साबुन-निर्माता यह आशा कर सकता है कि प्रति सप्ताह उसकी लाखों साबुन की टिकियाँ मेन से पनोरिडा तक और न्यूयार्क से कैलिफोर्निया तक बिक जायेंगी। इस प्रकार, एक साथ लाखों की सख्या में साबुन तैयार कर वह अपना उत्पादन-व्यय घटा सकता है और अपने साबुन को ऐसे भाव पर बेच सकता है, जो सबकी जेब के अनुकूल हो।

लेखक की राय में, उपर्युक्त विचारों से इसके कारण का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के पास महान् प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। फिर भी, अमेरिका ही ऐसा देश नहीं है, जिसके पास यह साधन विद्यमान हैं। बहुत से कच्चे माल के मामले में अमेरिका आत्मभरित नहीं है। उत्पादक यन्त्रों

के लिए दूसरे देशों से पर्याप्त कच्चा माल, जैसे सीसा, रंग, तांबा, मैगनीज की कच्ची धातु, निकल, जस्ता, रबर आदि भगाना पड़ता है।

अमेरिका की समृद्धि का कारण उसकी बड़ी आबादी को बताना क्या सन्तोषजनक माना जायेगा ? ऐसे देश हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और जिनके विकास की बड़ी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। फिर भी, उनकी बराबर यह गिनायत रहती है कि हम आवश्यकता से अधिक जनसंख्या के कारण परेशान हैं। वास्तव में, यदि बढ़ती हुई आबादी प्रमुख कारण होती, तो चीन अथवा भारत जैसे देश के लोगों का जीवन-स्तर आने आप ऊँचा हो जाता। वस्तुतः बात यह है कि यदि उत्पादन-वृद्धि की गति जनसंख्या-वृद्धि की रफ्तार से अधिक तेज न हुई, तो जीवन-स्तर गिरेगा, उठेगा नहीं।

एक और बात है, जिस पर हम आगे चलकर अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे, और वह यह कि आबादी आर्थिक प्रगति का एक तत्व तभी हो सकती है, जबकि वह आर्थिक जीवन में पूरी तरह भाग ले। दूसरे शब्दों में, किसी भी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत लाखों-करोड़ों लोगों का रहना ही पर्याप्त नहीं है। आबादी की उपयोगिता का निर्णय तो इसी बात से हो सकता है कि कितने लोग पूर्णतः उत्पादक के रूप में भाग लेते हैं। इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण तत्व यह होगा कि कितने लोग उपभोक्ता के रूप में उस अर्थ-व्यवस्था में शामिल हैं।

संक्षेप में, प्राकृतिक साधन और बढ़ती हुई आबादी अपने आप में समृद्धि और प्रगति के आधार नहीं हो सकते। इन दो चीजों की तुलना रासायनिक प्रक्रिया में आनेवाली प्रतिक्रियाशील तत्वों से की जा सकती है। ये प्रतिक्रियाशील तत्व तबतक निष्क्रिय रहते हैं, जबतक उन्हें दूसरे सम्मिश्रण में परिणत करने के लिए कोई अन्य उत्तेजक तत्व नहीं डाला जाता। अमेरिका के मामले में, यह उत्तेजक अथवा प्रेरक तत्व उसकी लोक-संघी उद्योगवाद की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है, जो विभिन्न तत्वों को प्रेरित कर उन्हें सबकी समृद्धि के रूप में परिणत कर देती है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी नयी बात

हम प्रायः सुना करते हैं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था कुछ भिन्न चीज है, वह मानव के अनुभवों में बहुत कुछ अभूतपूर्व, अद्वितीय है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की बहुत सी बातें अद्वितीय हैं और उन पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। इस पुस्तक के अधिकांश में उन्हीं बातों की चर्चा की जायेगी। उनमें से कुछ तो दूर से दिखाई देनेवाले उस हिमखण्ड के समान हैं, जो समुद्र की सतह से ऊपर सफेद-सफेद दिखाई देता है। लेकिन, अमेरिकी आर्थिक प्रणाली के अनोखेपन को समझने के लिए हमें उसके सभी सिद्धान्तों को देखना पड़ेगा—उस अंश को भी देखना पड़ेगा, जो सतह के नीचे छिपा हुआ रहता है और कुल व्यवस्था का पूरा हिस्सा है।

मार्क्स ने इस बात पर बल दिया है कि, 'पूँजीवादी' उत्पादन उस आर्थिक 'नियम' पर आधारित होता है, जिसके अन्तर्गत मजदूर एक जिन्स माना गया है और अन्य वस्तुओं की तरह उस जिन्स का भी एक बाजार भाव है। मार्क्स की परिभाषा के अनुसार श्रम का मूल्य वस्तुओं (माल और सेवाओं) के उस ढेर का योग है, जो 'श्रमजीवी वर्ग' के जीवित रहने और उसकी वशबेल चलाने के लिए आवश्यक है। मार्क्स का कहना है कि कोई पूँजीपति मजदूरों को उनकी मजदूरी के मूल्य से अधिक नहीं देगा, चाहे तकनीकी ईजादों और उच्चतर उत्पादन-क्षमता के फलस्वरूप उत्पादन कितना भी बढ़ जाये। इसी सैद्धान्तिक केन्द्र बिन्दु से अधिकतर मार्क्सवादी सिद्धान्त निकले हैं। 'मजदूरों का पूँजीवादी शोषण', यह नारा भी उक्त केन्द्रीय सिद्धान्त से ही निकला है।

मार्क्स के युग की अपनी परिस्थितियाँ थीं। मार्क्स ने उन्हें ही पूँजीवादी व्यवस्था के नमूने के रूप में सामने रखा। फलतः, 'श्रम के मूल्य' की परिभाषा करने में उसने कुछ हद तक गलती कर दी। यह ठीक है कि उसके जीवन-काल में मजदूर को एक जिन्स माना जाता था। वस्तुतः आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मजदूर को एक 'जिन्स'

माना जाता है और उसको मेहनताना उसी रूप में दिया जाता है । लेकिन अमेरिका ने इसमें एक नया तत्व जोड़ दिया है, जो बहुत ही अर्थपूर्ण है । मजदूर, अर्थात् जीविका के लिए श्रम करनेवाला प्रत्येक अमेरिकी अब किसी मूल्य विशेष की जिम्मेदारी नहीं रह गया है, बल्कि अब उसको संभाव्य उपभोक्ता माना जाता है । इसी क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के आधार पर कई नये कदम उठाये गये हैं, जिनका एक ही प्रमुख उद्देश्य है, और वह यह कि अमेरिका के जन-सामान्य की क्रय-शक्ति को सुरक्षित रखकर उसे और बढ़ाया जाये ।

यह जरूर है कि वैयक्तिक मेहनताने का निर्धारण व्यक्ति के काम के आर्थिक महत्व के आधार पर अपने आप होता है । क्षमता, शक्ति, शिक्षण और पहल करने की दृष्टि से आदमी आदमी में फर्क होता है । इसीलिए, किसी भी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पारिश्रमिक का मान भिन्न भिन्न होता है । लेकिन बुनियादी बात तो यह है अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूरों को, सभी श्रमजीवी अमेरिकियों को, उनकी मेहनत का मुआवजा इस प्रकार दिया जाता है कि उससे न केवल वे जीवित रहें और उनकी वशबेल जारी रहे, बल्कि उनकी क्रय-शक्ति भी बनी और बढ़ती रहे, क्योंकि व्यापक उत्पादन पर आधारित स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में जनता की क्रय-शक्ति को बनाये रखना जरूरी है ।

पुराने पूँजीवादी उत्पादन की व्यवस्था कुछ चुने हुए खास उप-भोक्ताओं को सन्तुष्ट करने के लिए ही की जाती थी—कुछ देशों में अब भी ऐसा होता है । मजदूरों का शोषण एक वास्तविक सम्भावना थी । लेकिन जब मजदूर और उपभोक्ता एक व्यक्ति में ही संवेष्टित हो गये, जब मजदूर उपभोक्ता अपने आप में एक मान्य एकक बन गया, तब पुरानी पूँजीवादी व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों में बुनियादी परिवर्तन हुए । अब 'पूँजीपति' मजदूर का शोषण नहीं कर सकता था, क्योंकि वही मजदूर अब प्रमुख उपभोक्ता भी होने जा रहा था । 'मजदूरों के शोषण' का सिद्धान्त उस निजी उद्योगों वाली अर्थ-व्यवस्था पर लागू नहीं होता,

जहाँ मेहनतकशों को प्रमुख उपभोक्ताओं के रूप में भी देखा जाता है ।

मजदूर उपभोक्ता की यह पहचान अमेरिकी व्यवस्था का एक बुनियादी ईजाद है । अमेरिका की आर्थिक विचारधारा पर इस सिद्धान्त का कितना प्रभाव पड़ा है, इसका स्पष्टीकरण स्वचालन की क्रांतिकारी प्रक्रिया पर अमेरिकी मजदूर यूनियनों की प्रतिक्रिया से ही हो जायेगा ।

स्वचालन प्रक्रिया अमेरिकी उद्योगों में एक वास्तविकता बन चुकी है । उत्पादन के इस उन्नत तरीके में मजदूर का स्थान स्वचालित नियंत्रण यन्त्र ले लेते हैं । दूसरे शब्दों में, स्वचालित नियन्त्रण यन्त्रों द्वारा पेचीदा मशीनें और सम्पूर्ण कारखाने तक चलाये जाते हैं । इस कार्य में मजदूरों का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं होता, वे केवल देख-भाल करनेवाले कारीगरों के रूप में खास-खास स्थानों पर रहते हैं । यह स्वचालन प्रक्रिया निर्माण कारखानों तक ही सीमित नहीं है, तथा-कथित 'बिजली के मस्तिष्क' आफिस क्लर्कों, एकाउण्टेंटों तथा अन्य सफेदपोश कर्मचारियों का स्थान भी लेते जा रहे हैं ।

इस स्वचालन प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी एक काम को, अथवा उससे भी बड़े काम को पूरा करने के लिए पहले से कम मजदूरी की आवश्यकता होती है । पुरानी पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मालिकों की दृष्टि में ऐसे मजदूरों का कोई 'मूल्य' नहीं रह जाता, जिनकी सेवाओं की जरूरत नहीं होती । यह सच है, लेकिन तभी जब हम मजदूर को सिर्फ एक जिनस के रूप में देखते हैं । परन्तु मजदूर अब तो उपभोक्ता भी है, जिसके कारण ही बड़े पैमाने पर उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभ-दायक हो पाता है । अपने आप चलनेवाली मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, कपड़े अथवा खाने की चीजें नहीं खरीद सकती । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यापक उत्पादन के साथ व्यापक बेरोजगारी चल नहीं सकती ।

कहने की जरूरत नहीं कि इस मजदूर उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बनाए रखना सरकार, व्यापार और मजदूर यूनियनों के लिए समान रूप से हितकारी है । यही कारण है कि, अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर

काँग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन्स के उपाध्यक्ष वाल्टर पी० रिडथर जैसे व्यक्ति को इस स्वचालन प्रक्रिया के आगमन से कोई भय नहीं है। वे इसका स्वागत ही कर रहे हैं। जैसा कि श्री रिडथर ने बताया है :

‘...यह आवश्यक नहीं रह गया है कि हम संसार की दुर्लभ वस्तुओं के विभाजन के लिए सघर्ष करने में जूझते रहे’ पूरा विश्वास है कि हमें इन मशीनों और तरीकों से भगड़ा करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम उनका उपयोग हर जगह के मानव को स्वास्थ्य और सुख, सुरक्षा और अवकाश तथा शान्ति और स्वतन्त्रता उपलब्ध करने के लिए करेंगे।’ (आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धी अमेरिकी कांग्रेस उपसमिति के सामने वयान १७ अक्टूबर, १९५५)।

यह विश्वास कोई अनुत्तरदायित्वपूर्ण आशावाद अथवा खोखला शब्द-जाल नहीं है। यह विश्वास इस जानकारी पर आधारित है कि स्वचालन प्रक्रिया के कारण बेकारी बढ़ना कोई जरूरी नहीं। इसके विपरीत यह आशा करना आर्थिक तौर पर अधिक वास्तविक होगा कि मजदूर उपभोक्ता की क्रय-शक्ति को बनाये रखने के प्रयास में उद्योग को नई चीजें बनाने और नये काम निकालने का समय मिलेगा। व्यक्तियों, यहाँ तक कि, सम्पूर्ण समुदायों की कठिनाइयों के समाधान के लिए दूरदर्शिता और बड़ी समझ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन, श्री रिडथर के शब्दों में, ‘यदि इस बार के व्यापक सामाजिक उथल-पुथल को रोकना है, तो इसमें निजी दलों और सरकार का सम्मिलित विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा।’ सामाजिक उथल-पुथल को रोकने और स्वचालन की क्रान्तिकारी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्याओं को सुलझाने के पीछे एक ही प्रेरक सिद्धान्त होगा और वह यह कि, व्यापक उत्पादन के लिए व्यापक खपत जरूरी है और इसी प्रकार व्यापक खपत का आधार व्यापक क्रय-शक्ति ही हो सकती है। अमेरिकी आर्थिक प्रणाली में सामान्य नागरिक के लिए उच्च जीवन-स्तर सिर्फ एक मानवीय परोपकार की बात नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की कुछ बुनियादी विशेषताएँ

व्यापक उत्पादन के लिये व्यापक खपत जरूरी है और व्यापक खपत व्यापक क्रय-शक्ति पर निर्भर है; इस बुनियादी सिद्धान्त से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की कई दिलचस्प विशेषतायें निकली हैं। इन से एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का दिग्दर्शन होता है जो उस 'पूँजीवाद' से जिसका नक्शा बहुत से लोगो के दिमाग में 'एकाधिकारी', 'शोषण' अथवा 'वर्ग-संघर्ष' की चर्चा करते समय रहा करता है।

कम लाभ पर व्यापक उत्पादन

मुनाफा कमाना निजी उद्योग का प्रमुख उद्देश्य रहा है। फिर भी, मुनाफा 'श्रमजीवी वर्ग' के शोषण का माप न होकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाटं अदा करता है। पैसे लगानेवाले को उसकी पूँजी पर उचित फायदा पहुँचाने के अतिरिक्त मुनाफा उत्पादक सम्पदा के नवीकरण और विस्तार के लिए पूँजी का प्रमुख स्रोत होता है। उदाहरणार्थ, १९५० में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को ३९१७ अरब डालर का सकुल लाभ हुआ। उसी वर्ष कम्पनियो को कर चुकाने के बाद २१ अरब डालर का शुद्ध लाभ रहा। इस राशि में से लगभग ११ अरब डालर लाभांश और ब्याज के रूप में लाखों दैनिक नियोजकों को मिला। शेष १० अरब डालर का उपयोग नवीकरण, विस्तार और अनुसंधान कार्यों पर हुआ।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इक्कीस अरब डालर एक बड़ी धनराशि है। फिर भी, यह ध्यान देने की बात है कि इतनी बड़ी राशि इस कारण नहीं आयी कि, प्रति इकाई कोई बड़ा लाभ कमाया

गया; बल्कि वह भारी पैमाने पर होनेवाली बिक्री का परिणाम ही थी। और इतनी अधिक राशि इसलिए संभव हुई कि उसके लिए एक विस्तृत उपभोक्ता बाजार मौजूद था। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता यह है कि अधिकतर निर्जा प्रतिष्ठान प्रति इकाई बहुत कम लाभ उठाते हैं। साबुन की लाखों टिकियो पर प्रति टिकी एक पेंनी लाभ के हिसाब से प्रति वर्ष लाखों डालर का लाभ बैठता है।

यदि प्रति इकाई अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का दाम बहुत ऊँचा कर दिया जाये, तो हो सकता है उपभोक्ता उसे खरीदने में असमर्थ हो जाये अथवा उसे खरीदना ही न चाहे। इसी कारण अमेरिकी उद्योगपति प्रति इकाई ज्यादा मुनाफा उठाने की कोशिश नहीं करता। उसका लक्ष्य यही रहता है कि उत्पादन के अच्छे तरीके अपनाकर उत्पादन-व्यय घटाया जाये। इसके लिए व्यापक उत्पादन, व्यापक खपत और प्रति इकाई कम लाभ, इन तीन बातों को एक साथ मिलाने का वह प्रयास करता है। पिछले बीस साल में अमेरिकी उद्योगपतियों ने जो औसत शुद्ध लाभ उठाया है, वह कुल बिक्री के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है।

व्यापक क्रय-शक्ति

प्रति इकाई कम लाभ पर व्यापक उत्पादन अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक विशिष्ट पहलू है। लेकिन, व्यापक उत्पादन तब तक बना नहीं रह सकता, जब तक उसे खपा लेने की आर्थिक सामर्थ्य जनता में न हो। आखिर, उत्पादन का आधारभूत औचित्य ही क्या है, यदि वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा न कर सके? फलतः व्यापक उत्पादन व्यापक क्रय-शक्ति पर निर्भर होता है, अर्थात् उत्पादन की मात्रा का निश्चय इस बात पर होता है कि मजदूरी और मूल्यों का सम्बन्ध क्या है और उससे अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक परिमाण में ज्यादा से ज्यादा वस्तुएँ खरीदने का अवसर मिलता है या नहीं।

व्यापक उत्पादन वाली अर्थ-व्यवस्था में यदि किसी खास उत्पादन के मामले में मूल्य बहुत ऊँचे रहे और मजदूरी बहुत कम रहे, तो वह अर्थ-व्यवस्था संकट में पड़ जायेगी। व्यापारियों, मजदूर यूनियनों और सरकार को अपनी अपनी कुशलता दिखाने की स्वतन्त्रता देकर इतना बढ़िया संतुलन रखा जाता है कि उपभोक्ताओं के विस्तृत बाजार पर कोई आच न आने पाये।

उपभोक्ता बाजार का द्विविध विस्तार

उपभोक्ता बाजार को स्थायी और प्रगति का एक तत्व बनाये रखने के लिए, इसका दुतरफा विस्तार होना जरूरी है। इसका एक विस्तार है क्षैतिज : उपभोक्ता बाजार देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला होना चाहिए। दूसरा विस्तार है उर्ध्वतन, अर्थात् ऊपर की ओर : सभी वर्गों के लोगों में इतनी आर्थिक सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे उपभोक्ताओं के रूप में आर्थिक चक्र के साथ चल सकें। इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यापक उपभोक्ता बाजार में उपभोग्य जिनस का अभाव अधिक समय तक नहीं रह सकता। 'धन का श्रृंगार' समझी जानेवाली वस्तुओं को भी जल्द से जल्द 'व्यापक खपत वाली चीजों' के रूप में बदल देना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अनुसंधान कार्यों पर तो निर्भर है ही, साथ ही साथ यहाँ इस बात का निरन्तर प्रयास किया जाता है कि सभी प्रकार की वस्तुएँ तैयार करने के अधिक अच्छे और कम-खर्च तरीके निकाले जायें।

प्रतियोगिता के रूप

सोवियत रूस जैसी बिल्कुल एकाधिकारवादी अर्थ व्यवस्था में उपभोक्ता के सामने पसंद-नापसंद का कोई सवाल नहीं होता। उसे एकाधिकारी राजकीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से ही संतोष करना पड़ता है। दूसरे, इस प्रकार के उद्योगों को पूरा इत्मीनान रहता है कि उनके उपभोक्ता बंधे बंधाये हैं, इसलिए उपभोक्ता क्या चाहता है और

क्या नहीं चाहता, इस पर विचार करना उनके लिए आवश्यक नहीं रह जाता।

स्वतंत्र उद्योगों वाली अर्थ-व्यवस्था की स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में तीन प्रकार की प्रतियोगिताएँ चलती हैं। एक तो बिलकुल 'प्रत्यक्ष' प्रतियोगिता है, जो एक ही प्रकार की वस्तुएँ बनानेवाले उद्योगों में चलती हैं। दूसरी प्रतियोगिता 'अप्रत्यक्ष' है, और वह उन उद्योगों में चलती है, जो प्रायः मिलती-जुलती वस्तुएँ अथवा सेवाएँ उपलब्ध करते हैं, अर्थात् विभिन्न प्रकार के परिवहन, जैसे बसें, ट्रक, विमान, रेल, नौकाएँ अथवा ईंधन, जैसे तेल, गैस, कोयला और बिजली। तीसरी प्रतियोगिता इन दोनों से भिन्न है। इसे समतोलक शक्तियों की आंतरिक रगड़ कहना ज्यादा ठीक रहेगा : खुदरा विक्रेता बनाम निर्माता, निर्मित माल उत्पादक बनाम बुनियादी माल उत्पादक, मजदूर यूनियन बनाम मालिक, उपभोक्ता बनाम उत्पादक और इन सबको बिखरे हुए, पर शक्तिशाली सार्वजनिक राय का सामना करना पड़ता है।

नये माल और उत्पादक तरीकों की निरंतर खोज

प्रतियोगितामूलक अर्थ-व्यवस्था में उदासीनता और राम नाम से ही सतोष कर लेने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। यदि आपके किसी प्रतिद्वन्द्वी ने एक अच्छी चूहेदानी—पहले से अच्छी चीज—बना ली, तो बाजार में आपकी स्थिति कमजोर हो जायेगी। अतः कारोबारियों को हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। किसी बात को वेद-वाक्य मानकर स्वीकार कर लेना, यह मान लेना कि 'सदा से यही परम्परा रही है', पुराने विचारों तथा तरीकों को पकड़े रहना स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत निजी उद्योग के लिए आत्मघातक है। 'जनरल इलैक्ट्रिक' कम्पनी के एक नारे के अनुसार 'प्रगति किसी भी स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण फल है'। प्रगति का क्रम न रुकने पाये, इसके लिए

अमेरिकी व्यापारियों को निरन्तर नयी और पहले से अच्छी चीज़ें बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है। नयी, अधिक कुशल, अधिक व्यवहार योग्य अथवा अधिक आकर्षक चीज़ों की खोज अब उन आविष्कारकों का एकांत प्रयास नहीं रह गयी है, जिन्हें लोग अक्सर गलत समझते रहे हैं, बल्कि अब वह एक जागरूक प्रक्रिया बन गयी है, जिसे व्यापारियों ने अपने एक प्रमुख कर्तव्य के रूप में अपना लिया है। सिर्फ १९५७ में अमेरिकी कार्पोरेशनों ने अनुसंधान और विकास पर ६ अरब डालर खर्च किया।

व्यापार और शिक्षा

वैज्ञानिक अनुसंधान आज अमेरिकी निजी उद्योग का प्रमुख कर्तव्य बन गया है। वैज्ञानिक, शिक्षक, विशेषज्ञ अब व्यापारिक दुनिया के लिए अजनबी नहीं रह गये हैं; और न ही आविष्कारक व्यापारी वह भद्रा आदमी रह गया है, जिसे कार्टून बनानेवाले अक्सर चित्रित करते रहे हैं। अक्सर उसके पास कालिज की डिग्रियाँ होती हैं और अब महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्पोरेशनों के उच्च पदों पर इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की नियुक्ति एक साधारण बात हो चली है। व्यापार और शिक्षा की पारस्परिक निर्भरता अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का दूसरा विशिष्ट पहलू है।

उत्पादन क्षमता और मानव सम्बन्ध

व्यापार के एक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी विज्ञान का प्रभाव है। वह क्षेत्र है मानव सम्बन्धों का। कर्मचारियों को अब सिर्फ 'हाथ' नहीं माना जाता। वे सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं। मनोविज्ञानवेत्ता आज अनेक कार्पोरेशनों का अनिवार्य स्टाफ सदस्य हो गया है। इसका परिणाम यह निकला है कि आज व्यवस्थापकों और मजदूरों के सम्बन्ध पहले से अधिक अच्छे हैं।

इसका उद्देश्य सिर्फ व्यवस्था विभाग के प्रति सद्भावना पैदा करना नहीं है। ये स्वस्थ सम्बन्ध वस्तुतः उच्चतर उत्पादन-क्षमता के लिए भी

जरूरी है। व्यापक उत्पादन वाली स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था में अच्छे मानव सम्बन्ध उन वैज्ञानिक तरीकों के अभिन्न अंग बन गये हैं जो आर्थिक प्रगति का क्रम जारी रखने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं।

प्रतिभाशाली लोगों की तलाश

प्रतियोगितामूलक अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रतिभा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पिता की प्रतिभा पुत्रों में भी रहे यह कोई जरूरी नहीं। इस कारण पुराने प्रकार के पारिवारिक व्यापार का स्थान धीरे-धीरे आधुनिक कार्पोरेशन ने ले लिया है।

इस प्रकार के व्यापारिक संगठन में एक नया व्यवसायी अग्रिम पक्ति में आता जा रहा है। वह है व्यापार व्यवस्थापक। उसके मूल, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और इसी प्रकार की अन्य बातों का उतना महत्व नहीं होता। प्रशासन की प्रतिभा, प्रखर बुद्धि, शिक्षा-दीक्षा, क्षमता—ये ही वे योग्यताएँ हैं, जिन्हें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। धनहीन प्रवासी अथवा एक खान मजदूर का बेटा भी 'यू० एस० स्टील' अथवा 'ट्वटिएथ सेचुरी फाक्स' जैसे बड़े कार्पोरेशन का अध्यक्ष बन सकता है। बेजामिन फेयरलेस अथवा स्पाइरस स्कूरस इसके उदाहरण हैं।

किसी उच्च अधिकारी के लड़के को अपने पिता के चरण-चिन्हों पर चलने का अवसर मिल सकता है, बशर्ते कि उसमें नेतृत्व और जिम्मेदारी सम्हालने की योग्यता हो। तथापि, एक प्रतियोगितावादी अर्थ-व्यवस्था में शायद ही कोई उद्योग अधिक समय तक सफेद हाथी बाँधने की जुरंत करेगा।

उद्योगपति के लिए नयी चिन्तन धारा

ये नये व्यावसायिक लोग—व्यापार व्यवस्थापक—एक समाज के नहीं होते, इन व्यापार जादूगरों का कोई मानक नहीं है। ये भी मनुष्य ही हैं। इनमें भी अन्य लोगों की तरह अपनी शक्ति और सीमाएँ होती हैं। वैयक्तिक रुचि और पृष्ठभूमि के अनुसार उनके प्रेरणा-तत्त्व भी भिन्न

होते हैं। तथापि, उनमें एक बात समान रूप से होती है : व्यापार के सामाजिक कर्त्तव्य के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण। वे दिन लद गये जब उद्योगपतियों के चिन्तन का श्रीगणेश और अन्त 'मुनाफा' से ही होता था।

आधुनिक व्यापार की पेचीदगी और समाज के सभी पहलुओं पर उसके प्रभाव को देखते हुए आज का व्यापार व्यवस्थापक सिर्फ मुनाफे, बाजारों और उत्पादन के उतार-चढ़ाव के चक्कर में नहीं रह सकता। उसे समाज के विस्तृत ढाँचे पर भी ध्यान देना पड़ता है, व्यापार जिसका मात्र एक अंग है। आधुनिक व्यापार व्यवस्थापक की प्रमुख दिलचस्पी इसमें होगी कि समृद्धि का क्रम निरन्तर बना रहे, जल्द से जल्द अनुत्तरदायित्व-पूर्ण ढंग से मुनाफा कमाने में वह रुचि नहीं लेगा। उदार शिक्षा-दीक्षा और अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी सिद्धान्तों की अच्छी समझदारी के फल-स्वरूप अधिक से अधिक व्यापार व्यवस्थापक रचनात्मक प्रवृत्ति वाले और समाज के प्रति जिम्मेदार होते जा रहे हैं। अमेरिकी उद्योग की बागडोर सम्हालने के लिए ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है।

विज्ञापन का महत्त्व

अमेरिका में विज्ञापन के सामाजिक तथा आर्थिक महत्त्व पर बल देने की जरूरत नहीं। यदा-कदा कथित गलत कामों के लिए कड़ी आलोचनाएँ होती रहती हैं, तथापि अमेरिका की प्रगति में विज्ञापन-उद्योग का प्रमुख हाथ रहा है। व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था को व्यापक प्रचार की जरूरत होती है, और यह काम विज्ञापन-उद्योग ही कर सकता है।

प्रतियोगितावादी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में विज्ञापन न केवल उन चीजों को जनता तक पहुँचाता है, जिनको जनता चाह रही होती है, बल्कि वह नयी चीजों के लिए भी लोगों में चाह पैदा करता है। यदि विज्ञापन न हो, तो नयी चीजों के लिए पर्याप्त ग्राहक शायद ही मिलें। यही

नहीं, क्योंकि विज्ञापनों द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति सामाजिक भेद को कम करने की ओर होती है। विज्ञापन न केवल जीवन की सुविधाओं को वाछनीय बनाता है, वह उनको कुछ ऐसा रूप देता है कि सामान्य अमेरिकी को भी यह भान हो कि वह अमूल्य वस्तु खरीदने की स्थिति में है। कभी-कभी विज्ञापन पर अश्लीलता, कुराचि और आवश्यकता से अधिक उत्तेजक होने तथा इसी प्रकार के अन्य आरोप आ सकते हैं; तथापि, अमेरिका में विशाल उपभोक्ता बाजार को बनाये रखने में विज्ञापन का बड़ा हाथ है।

स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था और मजदूर यूनियन

निजी उद्योग और जागरूक शासन के अतिरिक्त अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अपने कुशल संचालन के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली मजदूर यूनियन के अस्तित्व पर निर्भर करती है। मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा और लाभ दिलाने के लिए दबाव डाल-डालकर मजदूर यूनियन व्यापक उपभोक्ता बाजार के विकास और सुरक्षण में सक्रिय योगदान करती रही है।

अमेरिकी मजदूर यूनियन इस बीसवीं सदी में स्वतंत्र उद्योग-पद्धति के उसूलों को मानती हैं और राष्ट्र की आय का एक बड़ा हिस्सा अपने सदस्यों को दिलाने के लिए जोरदार प्रयास करती हैं। इस पर बहुत कुछ सेमुएल गोम्पर्स का प्रभाव है। सेमुएल गोम्पर्स बहुत समय तक 'ए० एफ० एल०' के अध्यक्ष रहे थे। अमेरिकी मजदूर का उन्नत जीवन-स्तर इस बात का प्रमाण है कि यह मार्ग चुनना कितना विवेकपूर्ण रहा।

जब मजदूर नेता सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करने हैं और मजदूर को सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे का ही एक अंग मानकर चलते हैं, तभी वे मजदूरों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करते हैं।

अमेरिकी शासन संतुलन-तत्त्व के रूप में

इस अर्थ-व्यवस्था में अमेरिकी शासन एक दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व है। इसके कार्य-क्षेत्र के विस्तार के बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के शासकीय दायित्वों के प्रश्न पर कोई गंभीर मत-भेद नहीं है।

निजी उद्योग पर आधारित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व इस बात पर निर्भर होता है कि, राष्ट्र की उत्पादन तथा उसकी खपत और बचत की क्षमता के बीच कितना संतुलन है। यह संतुलन उतना कड़ा पक्का नहीं है। वह सुरक्षा की विस्तृत सीमाओं के अन्दर चढ़-उतर सकता है। अमेरिकी शासन का एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह यह देखता रहे कि देश की अर्थ-व्यवस्था इन सीमाओं के अन्दर ही रहे; और इस प्रकार शासन उसे भयानक तेजी से भयानक मंदी तक गिरने और समृद्धि से गिरकर अवनति की ओर जाने से रोकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सघीय सरकार ऊपर से कोई कड़ा भार नहीं लादती। वह इस बात का निर्णय पहले से ही नहीं कर देती कि, लोगों को किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, उन्हें क्या पसंद होना चाहिए अथवा उनके पास क्या होना चाहिए। कड़ा नियंत्रण और नियमन आर्थिक स्थायित्व लाने के आदिम तरीके हैं। अमेरिकी शासन इसके लिए अधिक उन्नत तरीकों पर निर्भर करता है।

अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए शासन के पास कई आर्थिक और वित्तिक तरीके हैं। इसके साथ-साथ भविष्यवाणी और मूल्यांकन के विश्वसनीय वैज्ञानिक उपाय भी हैं। सापेक्ष स्थायित्व कायम रखने के लिए अमेरिकी शासन जिन उपायों से काम लेता है, उनमें से कुछ तो ये हैं : कर आरोप, सरकारी व्यय, सामाजिक विधि-विधान आदि-आदि।

×

×

×

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के उपर्युक्त सिद्धान्त और विशेषताएँ कोई

अमिट कानून नहीं, जिनका विश्वासपूर्वक पालन करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाये। ये सब सामान्य मान्यताएँ हैं, जिन पर परिस्थिति के अनुसार अमल होता है। वस्तुतः अमेरिका में भी इनमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं, जिन्होंने अभी तक पूर्णता नहीं प्राप्त की है और अमेरिकी व्यवस्था की कोई अनिवार्य विशेषता प्रकट नहीं करती; और न ही ये सिद्धान्त अपने आप में कोई पृथक् चीज हैं। किसी दूसरे प्रेक्षक को कुछ अन्य बातें भी चलती दिखायी दे सकती हैं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, जो इस वर्गीकरण को अधिक अथवा कम श्रणियों में पुनः संयोजित कर सकते हैं। लेकिन, इस पुस्तक का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप, जो कुछ अभी तक कहा गया है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित लोकतंत्री उद्योगवाद की सामान्य रूपरेखा का दिग्दर्शन कराता है। आगे के अध्यायों में हम इस रूपरेखा का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे।

द्वितीय भाग

मुनाफा क्या है ?

लोग अक्सर सुनते हैं कि “मुट्टी भर घन्ना सेठो द्वारा नियंत्रित अमेरिकी एकाधिकारवादी उद्योग बहुत अधिक लाभ कमाते हैं और मजदूरों से उनके परिश्रम का फल छीन लेते हैं।” यह आरोप प्रचारात्मक हो या नहीं, लेकिन इसकी बारीकी से जाच करना आवश्यक है।

बड़े मुनाफे का अर्थ शोषण है ?

किसी भी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन का एक ही प्रमुख उद्देश्य होता है—उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करना। अब, इस सिद्धान्त की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब हम एक प्रश्न का उत्तर देगे—उपभोक्ता कौन है ?

एक छोटे पैमाने की पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, जो अपेक्षाकृत थोड़ा उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करती है, उत्पादक बहुत ज्यादा दाम ले सकता है, जो उनके चुने हुए उपभोक्ताओं की जेब के अनुकूल हो सकता है। उत्पादक अपने मजदूरों को पारिश्रमिक बहुत थोड़ा दे सकता है, और प्रति इकाई ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठा सकता है। यह पुराने पूंजीवाद का निकृष्ट रूप है। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में मजदूरों का शोषण एक वास्तविक सम्भावना है।

पुराने प्रकार का पूंजीपति अपने मजदूरों का शोषण कर सकता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कौन मजदूर है और कौन ग्राहक। एक ही व्यक्ति मजदूर और ग्राहक दोनों हो इसकी सम्भावना बहुत कम थी। मजदूर अपने द्वारा निर्मित वस्तु खरीदने में समर्थ नहीं है, इसका मालिक कभी आय पर प्रभाव नहीं के बराबर था। वह अपने लाभ के लिए

ग्राहको से ऊँचे दाम लेता और जो लोग माल बनाते उन्हें बमुश्किल गुजर भर के लिए मजदूरी दे देता ।

स्वतन्त्र और व्यापक उत्पादन वाली अर्थ-व्यवस्था में यह बात आर्थिक दृष्टि से असम्भव है । क्यों ? क्योंकि, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में मजदूर और उपभोक्ता का भेद मिट जाता है । यहाँ मजदूर से मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम करने वालों से ही नहीं है । आर्थिक उद्देश्य से किया गया हर मानव का प्रयास 'श्रम' है । अत्यन्त कुशल कार्यकर्त्ता, कारीगर, संचालक, व्यवसायी, वैज्ञानिक, कार्यालय कर्मचारी, अपनी जीविका के लिए खटने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्र के श्रमिक समूह का सदस्य मानना चाहिए । अधिकतर वयस्क अमेरिकी, जिनकी संख्या साढ़े छ करोड़ से अधिक है, अपनी जीविका के लिए श्रम करते हैं । ये ही अमेरिकी अपने परिवारों के साथ उपभोक्ता समूह का रूप धारण करते हैं । इस प्रकार, अमेरिका में उपभोक्ताओं की संख्या आज बहुत बड़ी है । फलतः अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में मजदूर उपभोक्ता अपने आप में एक वास्तविकता बन गया है । उत्पादक अपने मजदूर को इसलिए नहीं लूट सकता, क्योंकि वह मजदूर उसका ग्राहक भी है । अगर श्रमजीवी लोगों में उद्योगों द्वारा उत्पादित माल और सेवाएँ खरीदने की आर्थिक सामर्थ्य न रही, तो इसका पहला वक्का उद्योगों को ही लगेगा, उनके माल का कोई खरीदार न रहेगा ।

बहुत से लोगों में यह धारणा पाई जाती है कि सब मिला कर देखा जाय तो मुनाफा निश्चित रूप से मजदूरों अथवा उपभोक्ताओं का शोषण ही है, क्योंकि सब मिलाकर मुनाफे की राशि बड़ी दिखाई देती है, इसलिए मजदूरी जरूर कम होगी अथवा चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा ऊँचे होंगे । यह वह भ्रान्ति है, जिसके कारण अमेरिकी व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकतर गलतफहमियाँ चल रही हैं । निकट से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि ऐसा कोई निश्चित कोष नहीं है, जिससे मजदूरी और मुनाफा निकलते हों । सुव्यवस्थित और सुदक्ष उद्योग

एक साथ अच्छी मजदूरी भी दे सकता है, चीजों की कीमतें भी नीचे रख सकता है और कुल मिलाकर देखा जाये तो भारी लाभ भी कमा सकता है।

यही बात सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर लागू होती है। अमेरिकी उद्योग का मुनाफा अमेरिकी जनता के जीवन स्तर के विकास के अनुपात से बढ़ा है। लाभ कई गुना बढ़ा, परन्तु, लोगों की वैयक्तिक आय भी मूल्यों की अपेक्षा अधिक तेज गति में बढ़ी। इसके साथ-साथ कुल मुनाफे का जहाँ विस्तार हुआ, वहीं प्रति इकाई लाभ में गिरावट आ गई। यह सब व्यापक उपभोक्ता बाजार के विकास की विशेषता और परिणाम था।

मुनाफा पूँजी के स्रोत के रूप में

बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को पूरा करने और सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए माल और सेवाओं का उत्पादन निरन्तर बढ़ाते रहना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के दो व्यावहारिक उपाय हैं। प्रथम तो यह कि, अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनशील सुविधाओं को बढ़ाया जाये, और, दूसरे, अच्छी मशीनों तथा उत्पादन के सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग कर प्रत्येक मजदूर की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जाये। यदि उत्पादनशील सुविधाओं के विस्तार के साथ मजदूरों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाये, तो सबसे उत्तम परिणाम की आशा की जा सकती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का विशाल उत्पादन और अमेरिकी जनता का उन्नत जीवन-स्तर वैयक्तिक उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन-क्षमता के विस्तार को मिलाने के लिए निरन्तर चल रहे प्रयास का ही परिणाम है।

हम सब जानते हैं कि, किसी निजी प्रतिष्ठान का विस्तार अतिरिक्त पूँजी नियोजन पर ही निर्भर करता है। यही बात देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर भी लागू होती है। पूँजी वस्तुतः भौतिक प्रगति की नींव है।

मूलतः, जो कुछ माल तैयार होता है, यदि उसका एक अंश बच रहे, तो वही पूँजी बन जाता है। औद्योगिक एकाधिकार वाली अर्थ-व्यवस्था

में खपत पर रोक राजनीतिक सत्ताधिकारियों के एक निश्चय मात्र से लग सकती है, लेकिन एक स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में अधिकांशतः व्यक्तियों के स्वैच्छिक प्रयास से ही खपत को सीमित किया जाता है।

निजी उद्योग वाली आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में पूंजी के वस्तुतः तीन प्रमुख स्रोत होते हैं, वैयक्तिक बचत, व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार की व्यवस्था और मुनाफा।

१९५५ में, अमेरिकी व्यापारी वर्ग ने नवीकरण और विस्तार पर सब मिलाकर २८ अरब डालर खर्च किया। १९५६ में नये संयन्त्र (प्लांट) लगाने और उत्पादन सुविधाओं के विस्तार पर खर्च ३५ अरब डालर तक पहुँच गया, नये कार्यालय भवनो, फर्नीचर, कर्मचारियों के लिए मनोरंजन सुविधाओं, आदि के विस्तार पर ६ अरब डालर खर्च हुआ सो अलग।

यदि मुनाफा न हो तो कारखानों के विस्तार के लिए रुपया उधार लेना पड़े अथवा अधिक निजी पूंजी लगानी पड़े। लेकिन, यदि उद्योगों से भविष्य में कोई मुनाफा न हुआ तो वह ऋण पटाने में असमर्थ रहेगा और यदि लाभांश के रूप में उचित लाभ की आशा न रहे, तो नई पूंजी मिलना मुश्किल हो जायेगा। निजी उद्योगों के विस्तार के लिए पूंजी आकर्षित करने में मुनाफा, अर्थात् मुनाफे की आशा का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योग रहता है।

तथापि, मुनाफे का एक प्रत्यक्ष पूंजीमूलक कार्य भी है। मुनाफा विकास-कोष का प्रमुख स्रोत होता है। वास्तव में कम्पनियों में फिर से नियोजित मुनाफा अमेरिका के आर्थिक विस्तार का सबसे अधिक विश्वसनीय तत्व रहा है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि, १९४७ से १९५५ तक की अवधि में मुनाफा अमेरिकी उद्योगों के विकास की रीढ़ था। नई मशीनो, संयन्त्र निर्माण और अनुसंधान पर उस काल में जो कुछ खर्च हुआ, उसका आधे से अधिक भाग कारपोरेशनों में पुनः नियोजित मुनाफा ही था।

मुनाफे के अन्य कार्य

आज के अमेरिकी व्यापारी की दिलचस्पी बड़ी बिक्री से होनेवाले बड़े मुनाफे में होती है। वह प्रति इकाई अधिक लाभ के चक्कर में नहीं रहता। इसके विपरीत वह इस बात को अधिक पसन्द करेगा कि, आर्थिक स्थायित्व के वातावरण में कारोबार की लम्बी अवधि में कम ही मुनाफे पर सही अधिक परिमाण में बिक्री हो। यह कोई परोपकार की बात नहीं। यह एक आर्थिक आवश्यकता है। प्रतियोगितामूलक व्यापक उत्पादन वाली अर्थ-व्यवस्था में सापेक्ष स्थायित्व को बनाये रखने के लिए व्यापारी वर्ग मजदूरी घटाकर या मूल्य बढ़ाकर—जैसा कि, पुराने प्रकार के पूँजीपति कर सकते थे और कुछ देशों में ऐसा अब भी करते हैं—अपना मुनाफा बढ़ा नहीं सकता।

यह ठीक है कि कोई कोई उद्योगपति अथवा किसी कम्पनी का प्रबन्ध वर्ग आर्थिक तथ्यों की उपेक्षा कर दे। लेकिन, अगर उसने मूल्य बहुत अधिक बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा उठाने की कोशिश की तो बहुत सम्भव है कि ऊँचे मूल्यों के कारण बाजार में उसके माल की पूछ ही न रहे और उसका कारोबार चौपट हो जाये। दूसरे, मजदूर यूनियनों, जो हमेशा राष्ट्रीय उत्पादन का बड़े-से-बड़ा हिस्सा अपने सदस्यों को दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं अधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरी घटाने की किसी भी कोशिश का निश्चित रूप से प्रतिरोध करेगी।

पूँजी के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में मुनाफे को विकसित करने में कार्पोरेशन व्यवस्था ने बहुत अधिक काम किया है। कार्पोरेशन के मैनेजर का मुख्य कर्तव्य यह देखना होता है कि उसकी कार्पोरेशन दीर्घ-काल तक विकास के मार्ग पर चलती रहे। उसकी मनोवृत्ति शुद्ध लाभ का अधिकांश, आवश्यकतानुसार उद्योग के विस्तार पर लगाने की ओर रहती है, हालांकि बहुत से भागीदार, कार्पोरेशन के वास्तविक स्वामी अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त करने के पक्ष में हो सकते हैं। शुद्ध लाभ का एक बड़ा भाग नियोजन के लिए रखकर धन को खपत से हटाकर

पूँजी की ओर ले जाने की प्रक्रिया का कार्पोरेशन एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व बन गयी है ।

मुनाफा और घाटे के माप का एक दूसरा कार्य भी है । इससे इस बात का भी पता चलता है कि किसी निजी उद्योग का प्रबन्ध कितना अच्छा है, और उसका संचालन कितने कुशल ढंग से हो रहा है । मुनाफे के तत्व के कारण ही व्यवस्था विभाग में बहुत योग्य व्यक्ति लिए जाते हैं । इसके साथ-साथ इससे यह पता भी चलता है कि उत्पादक तत्वों प्राकृतिक साधन, श्रम और पूँजी का ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं । यदि किसी कम्पनी को कोई मुनाफा नहीं हुआ है, तो उसे अपने ढाँचे और नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा । यह पता लगाना पड़ेगा कि वह अपना माल खर्चों से भी कम मूल्य पर तो नहीं बेच रहा, अथवा मूल्य इतने ऊँचे तो नहीं हैं कि खरीदार आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं उसका उत्पादन और वितरण का तरीका तो खराब नहीं । मुनाफा और हानि का सिद्धान्त वह सुरक्षा कुंजी है, जो निजी उद्योग को कुशल संचालन के लिए प्रेरित करती रहती है और आर्थिक प्रगति की गारण्टी का काम करती है । इसके बिना खर्चा बढ़ने और अपव्यय के कारण सम्पूर्ण समाज को हानि उठानी पड़ सकती है ।

न ही पूँजी लगाने की प्रेरणा और नया कारोबार शुरू करने में अथवा नवीकरण पर धन लगाने में जो जोखिम रहता है उसकी क्षति पूर्ति के रूप में मुनाफे का महत्व खत्म हुआ है । लाभांश अथवा ब्याज की आशा लोगों को इसके लिए प्रेरित करती है कि वे अपनी बचत को उपभोग्य सामग्रियों पर ही खर्च न कर उसे स्वेच्छा से राष्ट्र के उत्पादन-शील उद्योगों में लगायें ।

पूँजी लगानेवालों को आखिर कितना बड़ा पुरस्कार मिलता है ? यह सामान्यतः इस बात पर निर्भर होता है कि पूँजी नियोजक ने कितना जोखिम उठाया है । यदि कोई व्यक्ति ऐसे वित्तीय उद्योग में पैसा लगाता है, जिसका भविष्य निश्चित नहीं है, तो बहुत बड़ा लाभ उठा सकता है,

लेकिन इसके साथ उसकी पूँजी के डूब जाने का भी खतरा रहता है । तथापि, पूँजी लगानेवाला अपनी पूँजी पर ३ से ८ प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर सकता है—लाभ परिमाण इस बात पर निर्भर होगा कि पूँजी किस प्रकार के उद्योग में लगायी गई है, उसमें जोखिम कितना है ।

इस स्थल पर हम एक पूँजी नियोजक की औसत आय और ५,००० डालर वार्षिक कमाने वाले कुशल मजदूर की औसत मजदूरी की तुलना करेंगे । एक पूँजी नियोजक को साल में, ५,००० डालर कमाने के लिए १,००,००० डालर से भी अधिक 'पूँजी' लगानी पड़ेगी । लेकिन, यदि उसने अपनी बचत को शेयर आदि में लगा दिया है, तो यह निश्चित नहीं कि उसे साल में ५,००० डालर की प्राप्ति हो ही जायेगी । उल्टे ऐसा भी हो सकता है कि साल भर में उसे एक पाई भी न मिले । अमेरिका की आधी या एक तिहाई कार्पोरेशनें नियमित रूप से कोई लाभांश वितरित नहीं करती । अतः यह तो साफ है कि औसत पूँजी लगानेवाले को इतना लाभ नहीं मिलता कि उसे अनुचित अथवा बहुत अधिक कहा जाये ।

वस्तुतः, देखा जाये तो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत 'मजदूर' को ही सबसे अधिक तरजीह दी जाती है । लेकिन, आखिरकार साधारण उपभोक्ताओं में अधिक संख्या मजदूरों की ही तो है और इसके साथ लाखों मजदूर पूँजी नियोजक भी हैं । लगभग ६० लाख परिवारों के पास कार्पोरेशनों के शेयर और बांड हैं, जबकि इससे भी अधिक लोग बचत खातों, बीमा पालिसियों, आदि के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी लगाते रहते हैं । फिर भी, उनकी आय का अधिकांश उनकी मेहनत पर निर्भर है । फलतः वे कितना उपभोग कर सकते हैं, इस बात का निर्धारण भी उनकी मेहनत पर ही होगा । यही कारण है कि एक व्यक्ति को 'मजदूर' के रूप में जितना पारिश्रमिक मिलता है, उतना उसे पूँजी नियोजक के रूप में नहीं मिलता । लोकतन्त्री उद्योगवाद के सिद्धान्तों पर आधारित व्यापक उत्पादन वाली अर्थ-व्यवस्था में मजदूर-उपभोक्ता का केन्द्रीय महत्त्व रहता है ।

उत्पादन क्षमता, मजदूरी और मूल्य

अमेरिका के दिन-दिन बढ़ते हुए जीवन-स्तर का एक मुख्य कारण उन्नत उत्पादन-क्षमता है। १९२९ में ४५० लाख अमेरिकियों ने ११६ अरब घंटे काम किया, जबकि १९५४ में ६०० लाख अमेरिकियों ने १३० अरब घंटे काम किया, अर्थात् १६ प्रतिशत अधिक। फिर भी, कुल उत्पादन १९२९ की तुलना में दूना रहा। इस बढ़ोतरी के पीछे यांत्रिकी प्रगति का बड़ा हाथ है। और इस प्रगति का कारण है अमेरिका में ज्ञान, उपकरण और पद्धतियों के विकास के लिए चल रहा सतत प्रयत्न।

व्यापक उत्पादन क्या संस्कृति का शत्रु है ?

व्यापक उत्पादन का निद्वान्त हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। कुछ लोगो को भय है कि व्यापक उत्पादन 'सांस्कृतिक बर्बरता' का जनक है। उनका तर्क है कि, पुराने कारीगरों की कारीगरी और कार्य की प्रतिष्ठा मशीनों की स्वचालित और समान गति के सागर में डूब जायेगी। उनका दावा है कि व्यापक पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं में वैयक्तिक कुशलता का अभाव होता है और जो लोग उनका व्यवहार करते हैं, उनमें भी वैयक्तिक अभिरुचि का ह्रास होने लगता है।

जैसा कि, अक्सर आम मान्यताओं में होता है, इन तर्कों में जहाँ सचाई का कुछ अंश है, वही बहुत अधिक अतिशयोक्ति भी है। यह बात सच है कि अमेरिका में वैयक्तिक कारीगरों की संख्या बहुत कम हो गयी है, उनका स्थान कुशल मजदूरों और मिस्त्रियों ने ले लिया है। लेकिन, मजदूर अब मशीनों का गुलाम नहीं रहा, जैसा कि वह आरम्भिक उद्योगीकरण के दिनों में था। अब तो एक नया वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है,

जिसे मानव अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) कहते हैं। इसकी सहायता से अमेरिका में मशीन के साथ उसे चलानेवाले मनुष्यों की आवश्यकताओं का ताल-मेल बैठाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। वेदंगे नियंत्रण (कंट्रोल) को समाप्त करने तथा ऐसे कामों के रूटीन में, जिनमें बहुत ज्यादा झुकने-झुकाने या ढुलाई की जरूरत पड़ती है, आवश्यक हेर-फेर संभव करने के लिए कारखानों में नये-नये डिजाइन की मशीनें बनायी जाती हैं। जहाँ तक उत्पादन की एकरूपता का प्रश्न है, अमेरिकी उद्योग उन वस्तुओं पर कुछ वैयक्तिक छाप डालते हैं, जहाँ वैयक्तिक रूचि का सबसे अधिक महत्त्व होता है। निश्चय ही, कोई अमेरिकी महिला यह शिकायत नहीं कर सकती कि स्त्रियों की पोशाकों में इतनी ज्यादा एकरूपता है कि उसे देखकर मन बैठने लगता है।

इन सब बातों के अलावा, ऐसा लगता है कि, व्यापक उत्पादन के आलोचक इसके परिणामों को आँखों से ओझल कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्राचीन काल की महान कृतियाँ, संग्रहालयों और राज प्रासादों में जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, अतीत की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करतीं। उन वस्तुओं को हम ऊँची संस्कृति की देन मानते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि उन्हें अपने पास रखने की सामर्थ्य मुठ्ठी भर सम्पन्न व्यक्तियों में ही थी। वेनवेनुतो सेलिनी द्वारा बनाया गया चाँदी का कटोरा, निस्संदेह एक महान कृति कहा जायेगा, लेकिन उसका निर्माण किसी राजा महाराजा के लिए ही किया गया था, 'जन-साधारण' के लिए नहीं। बहुत समय तक संस्कृति 'विलास सामग्री' बनी रही; वह इने-गिने सम्पन्न लोगों के लिए ही सुरक्षित थी।

व्यापक उत्पादन का युग आने से पूर्व लोगों में मतभेद जरूर था। एक रईस अथवा धनाढ्य व्यापारी एक ऐसी भिन्न दुनिया में रहता था, जो 'निम्नवर्गीय' लोगों से बिलकुल अलग थी। आज से सौ वर्ष पहले भी किसी दूसरे ग्रह से कोई यात्री यहाँ आता, तो उसे एक रईस और भटियारे को पहचानने में कोई कठिनाई बही होती, क्योंकि उनके हाव

भाव और पहनावे में भारी अन्तर था ।

व्यापक उत्पादन ने अमेरिका में स्थिति बिलकुल बदल दी है । अधिक चीजें अधिकतर लोगो को उपलब्ध हो जाने के कारण संस्कृति का सामान्य स्तर ऊँचा हो गया है और विशेष रूप से स्पष्ट अन्तर बिलकुल मिट गये हैं । आप किसी रविवार को किसी अमेरिकी शहर में जाइए । यदि आप यह सोचें कि लोगो के कपड़े देखकर आप यह जान लेंगे कि वहाँ कौन सम्पन्न व्यापारी है और कौन मजदूर, मेयर की पत्नी कौन है और दरबान की बेटा कौन, तो आप को बड़ी परेशानी होगी ।

अमेरिकियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगो को अधिक में अधिक प्रकार की वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने की सहूलियत हो । अमेरिकी उद्योग का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आज की 'विलास की वस्तुएँ' यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में 'व्यापक खपत की वस्तुओं' में परिवर्तित हो जायें ।

फिर भी, इसका अभिप्राय यह नहीं कि अमेरिकियों को यह आशा है कि, 'विलास सामग्री' का अस्तित्व वे ममाप्त कर देंगे । प्रगति के अनेक प्रमाण होते हैं । उनमें से एक यह है कि कितनी ही नयी नयी वस्तुओं का विकास होता रहता है । अनिवार्यतः, इस प्रकार की नयी चीजें आरम्भ में दुष्प्राप्य रहती हैं और यह स्थिति तब तक बनी रहती है, जब तक कि, उनके व्यापक उत्पादन के तरीके निकल नहीं आते और जब तक एक वस्तु का व्यापक उत्पादन शुरू होता है, तब तक और कोई नयी चीज बन कर सामने आ जाती है । और यही प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है । जब तक हम प्रगति की एक अधिकतम सीमा निश्चित नहीं कर देते और जब तक नयी वस्तुओं के उत्पादन पर रोक नहीं लगा देते, तब तक ऐसा समय नहीं आ सकेगा, जब कि 'विलास वस्तुओं' का अस्तित्व न हो । कुछ आश्वासनों के बावजूद वह दिन अभी दूर दीखता है, जब "हर व्यक्ति को हर चीज अपनी आवश्यकतानुसार मिल सकेगी" यदि इससे हमारा अभिप्राय यह हो कि प्रत्येक व्यक्ति को 'विलास

सामग्री' भी आवश्यकता भर मिलने वाली है।

इसके साथ-साथ यात्रिकी विद्या और बढ़ती हुई उत्पादन-क्षमता के फलस्वरूप किसी नई वस्तु के विकास और उसके व्यापक उत्पादन तथा वितरण के बीच का अन्तर कुछ कम हों सकता है। अमेरिका का स्वतंत्र उद्योग उत्पादन के विभिन्न चरणों के बीच के समय का अन्तर निरन्तर घटाता रहा है।

अधिक मजदूरी और कम मूल्य

व्यापक उपभोक्ता बाजार को बनाये रखने के लिए मजदूरी और वेतन के साथ मूल्य का उपयुक्त सम्बन्ध कायम रखना आवश्यक है।

स्तुतः स्वभावतः 'सस्ता मूल्य' चाहेगा। तभी वह अपने पैसे से 5 वस्तुएँ खरीद सकेगा। इसके विपरीत, उत्पादक स्वभावतः अधिक और कम मजदूरी रखना चाहता है। इस प्रकार उसे प्रति इकाई के से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। प्राचीन पूँजीवादी व्यवस्था यही बुनियादी विचारधारा है। लेकिन, लोकतंत्री उद्योगवाद और उपक खपत के निकट सम्बन्ध को देखते हुए यह साफ है कि उत्पादक का दीर्घकालीन हित इस बात में नहीं है कि प्रति इकाई अधिक से अधिक और जल्द से जल्द मुनाफा कमाये, बल्कि उसका वास्तविक हित इस बात में है कि उसके लिए व्यापक उपभोक्ता बाजार हमेशा बना रहे। इस प्रकार का बाजार स्पष्टतः ऐसी मजदूरी और मूल्य पर निर्भर करेगा, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रकार की वस्तुएँ खरीदना संभव हो। इस तरह 'अधिक मजदूरी और सस्ता मूल्य' न केवल उपभोक्ता के हित में है, बल्कि इससे उत्पादक का भी हितसाधन होता है।

वस्तुतः 'अधिक मजदूरी और सस्ता मूल्य' से वास्तविक अर्थ का ठीक-ठीक बोध नहीं होता। वास्तविक महत्त्व इस बात का है कि मजदूरी और मूल्य का सम्बन्ध क्या है, इस बात का नहीं कि किसी खास समय मजदूरी और मूल्य का स्तर क्या था।

फिर भी पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि, यदि 'मजदूर-उपभोक्ता' और 'उत्पादक' के हित इतने मिले-जुले हैं, तो फिर अमेरिका में मजदूरों के झगड़े क्यों होते हैं ? मानवीय कमजोरियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कमजोरी अक्सर ठोस आर्थिक चिन्तनधारा पर हावी हो जाती है। फिर भी एक प्रमुख प्रश्न, जैसे, उत्पादन क्षमता को लेकर चलनेवाले ईमानदारी पूर्ण मतभेद इस प्रकार के झगड़ों के कारण हो सकते हैं। यदि मजदूरी बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, तो इससे मुद्रास्फीति पैदा हो जायेगी। लेकिन, हर प्रकार के काम में उत्पादन को ठीक-ठीक मापा नहीं जा सकता। जब तक उत्पादन को अधिक सही-सही मापने के तरीके नहीं निकाले जाते, तब तक मालिक-मजदूर झगड़े खड़े होते रहेगे। तथापि, अमेरिका में मालिक मजदूर झगड़ों में अब उतनी कटुता नहीं होती, जितनी पहले हुआ करती थी। अक्सर, ये विवाद मामूहिक सौदेबाजी द्वारा आपने सामने बैठकर ही हल कर लिये जाते हैं। अमेरिकी श्रम सूचना संगठन (ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स) द्वारा प्रस्तुत अनुमान के अनुसार १९४७ में २५ नये मालिक मजदूर ठेको में से २४ पर शांतिपूर्ण समझौता हो गया। १९४७ और १९५२ के बीच हड़तालों के कारण काम के समय की बर्बादी पहले की तुलना में १ प्रतिशत के आधे से कम रही। और १९५४ में हड़ताल के कारण समय की बर्बादी कुल काम के दिनों का केवल ०.२ प्रतिशत थी।

कभी-कभी वार्ता असें तक चलती रह जाती है और बहुसें भी गर्म हो जाती है; लेकिन, कोई न कोई समझौतापूर्ण समाधान निकल ही आता है। उदाहरण के लिए उस समझौते को ही ले, जिसके अन्तर्गत मोटर वाहन (आटोमोबाइल) मजदूरों को वार्षिक मजदूरी की गारंटी दी गयी है अथवा उस समझौते को देख सकते हैं, जिसके अनुसार हाल में खान मजदूरों की दैनिक मजदूरी में २॥ डालर प्रतिदिन की वृद्धि की गयी है। (देखिए अध्याय १०)। मूल्य और मजदूरी में ताल बैठाने का बुनियादी तत्त्व उत्पादन-क्षमता ही होती है।

उत्पादन-क्षमता कैसे बढ़ती है ?

पिछले ५० वर्ष में अमेरिकी उत्पादन प्रतिवर्ष औसतन २ प्रतिशत के हिसाब से निरन्तर बढ़ता रहा है। लेकिन, उत्पादन न तो अपने आप बढ़ता है और न ही इसके पीछे किसी प्रकृति का कोई करिश्मा है। इसके विपरीत अमेरिकी उद्योग और कृषि की उत्पादन-वृद्धि व्यावहारिक प्रोत्साहनों और कल्पनापूर्ण तरीकों का परिणाम है।

अब मुनाफे के लक्ष्य को ही लीजिए। मुनाफा कमाने के लक्ष्य के कारण प्रतियोगितामूलक निजी उद्योगवाली अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। मुनाफा बढ़ाने का ठोस तरीका यही है कि प्रति इकाई उत्पादन व्यय घटाया जाये और उत्पादन बढ़ाकर लाभ की मात्रा बढ़ायी जाये, अर्थात् पूँजी और श्रम का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जाये। और अमेरिकी उद्योग तथा कृषि ने बड़े जोर के साथ यही किया है।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अमेरिकी उद्योगों ने बड़ी हद तक वैज्ञानिक अनुसंधानों का सहारा लिया है और उत्पादन बढ़ाने के लिए यथासंभव जल्द से जल्द एक से एक नये तरीके अपनाये हैं। अमेरिका के आर्थिक विकास के हाल के एक अध्ययन (अमेरिकाज नीड्स एण्ड रिसोर्सेज : ए न्यू सर्वे, जे० फ्रेडरिक ड्यूहर्स्ट और उनके साथियों द्वारा संपादित) के अनुसार १९५० में वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन १८५० की तुलना में २५ गुना ज्यादा था, जबकि श्रम शक्ति में सिर्फ ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५० में काम के कम घण्टों को बाद देने के पश्चात् अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था ने १८५० की तुलना में ५ गुने से भी कम वास्तविक मानव शक्ति लगाकर कुल उत्पादन उस वर्ष की अपेक्षा २५ गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। दूसरे शब्दों में अमेरिकी मजदूरों की उत्पादन-क्षमता पिछले सौ साल की अवधि में ५ गुनी बढ़ गई है। १८५० में एक मजदूर प्रति सप्ताह ७० घण्टे काम करके ३

सप्ताह में जितना पैदा कर सकता था, आज एक मजदूर एक ही सप्ताह में ४० घण्टे काम करके औसतन उतना ही उत्पादन कर सकता है। यदि उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की यह रफ्तार बनी रहती, तो आज से सौ साल बाद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में एक दिन में ७ घण्टे काम करके उतना पैदा किया जा सकेगा, जितना आज एक सप्ताह में ४० घण्टे काम करके पैदा किया जाता है।

प्रति मजदूर उत्पादन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी आखिर कैसे सम्भव हुई? इतना तो निश्चित है कि यह शारीरिक बूते पर अधिक पैदा करने की औसत आदमी की सामर्थ्य का परिणाम नहीं है। उत्पादन कुछ हद तक ही मजदूरों की दक्षता का माप या परिणाम होता है। पिछली कई दशकद्वयो में इतनी तेजी से जो उत्पादन-वृद्धि हुई है, उसमें व्यवस्था की सुचारुता, मजदूर की वैयक्तिक कुशलता अथवा किसान की लगन का स्थान दूसरा ही रहा है। बहुत उत्साही और कुशल मोची अत्यन्त सुयोग्य निरीक्षक की देख-रेख में सौ साल पुराने औजार से बहुत घण्टे काम करके भी उतना उत्पादन नहीं कर सकता, जितना आज का वह अर्द्ध-निपुण मजदूर कर सकता है, जो कम घण्टे ही खटता है, पर बिजली चालित मशीनों से काम लेता है। अमेरिकी उत्पादन में जो कल्पनातीत वृद्धि हुई है, उसका कारण यह नहीं है कि अमेरिका के लोग आजकल अधिक मेहनत से अथवा कुशलता से काम करते हैं, यह तो उत्तरोत्तर अच्छे तरीके और अधिक संख्या में अच्छी से अच्छी मशीनें निकालने और उनका प्रयोग करने के लिए चल रहे सतत प्रयास का ही परिणाम है। अमेरिका ने निर्जीव शक्ति के जरिए मानव प्रयास की उत्पादन-क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है।

फिर भी उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति व्यक्ति की कुशलता, प्रयास और सहयोग का स्थान आज भी बना हुआ है। उनके अभाव से अच्छी मशीनों, कारखाने के सुनियोजित संगठन और प्रचुर शक्ति की क्षमता बिलकुल नष्ट नहीं होगी, 'तो कम से कम घट जरूर जायेगी। अमेरिकी

व्यापारी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और इसलिए वे उत्पादन में मानवीय तत्व पर विशेष ध्यान देते हैं। व्यवस्था विभाग में नियुक्त मनोविज्ञानवेत्ताओं ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उत्पादन बढ़ाने में मजदूरों की मनोदशा का बहुत महत्त्व है।

औद्योगिक मनोविज्ञान विज्ञान की एक नयी शाखा है, जिसका सम्बन्ध उत्पादन के मानवीय तत्व से है। इसका आरम्भ आज से कोई ३० वर्ष पहले प्रायः अचानक ही हो गया। वेस्टर्न इलैक्ट्रिक कम्पनी यह जानना चाहती थी कि जिस विभाग में टेलीफोन नैयार करने का काम लड़कियाँ करती हैं, यदि वहाँ रोशनी का अच्छा इन्तजाम कर दिया जाये, तो इसके फलस्वरूप उत्पादन किस हद तक बढ़ेगा। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि रोगनी का परीक्षण शुरू होने मात्र से उत्पादन बढ़ने लगा—रोशनी वस्तुतः बढ़ी या घटी, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था। उत्पादन उस हालत में भी बढ़ा, जब परीक्षण करनेवालों ने बहाना तो यह बनाया कि वे ज्यादा रोशनी के बलब लगा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उन्होंने पहले ही बलब फिर से लगा दिये।

वेस्टर्न इलैक्ट्रिक कम्पनी ने यह अनुभव किया कि यह कुछ विचित्र बात है। यह फर्म पाँच वर्ष तक इस उत्पादन-वृद्धि के वास्तविक कारण की छानबीन करती रही। अन्त में, अनुसंधान करनेवालों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि मजदूरों पर इस बात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है कि, उन पर लोग कितना ध्यान देते हैं। परीक्षण से ही मजदूरों को लगा कि कम्पनी उनमें दिलचस्पी लेती है, उन्हें लगा कि हम भी कुछ हैं और वे अधिक मेहनत से काम करने लगे।

इसके बाद से अन्य कई मनोवैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। उदाहरणार्थ, अनुसंधान करनेवाले इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि पुराने उद्योगपतियों का यह विश्वास बिल्कुल गलत है कि यदि मजदूर १० या १२ घण्टे तक काम पर लगाये रखे जायें, तो ज्यादा काम निकलेगा। वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि विश्राम से दक्षता बढ़ती है। फलतः

अमेरिकी व्यापार जगत में हर जगह बीच-बीच में 'काफी ब्रेक' की व्यवस्था रहती है, जब मजदूर काम छोड़कर कुछ देर विश्राम और गपशप करते हैं।

उनकी खोजों का—अंशतः ही सही—एक परिणाम यह निकला है कि आधुनिक अमेरिकी कारखाना औद्योगिक स्थापत्य का अनुपम नमूना होता है। ये नये कारखाने अक्सर खुशनुमा ग्रामीण प्रदेश में बनते हैं, इनकी तुलना कार्ल मार्क्स के 'पसीनो से लथपथ मजदूरों से भरे लदन के कारखाने से' नहीं की जा सकती। आज से कुछ समय पूर्व मैं 'इन्टर-नेशनल बिजनेस मशीन्स' के कारखाने के मजदूरों का क्लब देखने गया था। यह क्लब पोकीप्सी, न्यूयार्क में है। इसमें एक रंगशाला है, जिसका मंच बहुत बड़ा और चारों तरफ घूमनेवाला है, उद्यान पथ है, टेनिस कोर्ट हैं, चांदमारी दीर्घाएँ हैं, गोल्फ का मैदान है, पुस्तकालय है, तैरने का तालाब और लाउंज है।

२५,००० से भी अधिक कम्पनियों में कर्मचारियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था है। शिकागो के 'नेशनल इण्डस्ट्रियल रिक्रिएशनल एसोसिएशन' के अनुसार सिर्फ १९५६ में अमेरिकी उद्योग ने अपने कर्मचारियों के मनोरंजन पर १ अरब डालर रकम खर्च की थी। आज अधिकतर अमेरिकी व्यापार प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित औद्योगिक सम्पर्क कर्मचारी होते हैं। ये लोग कम्पनी और उसके कर्मचारियों में स्वस्थ सुन्दर सम्बन्ध बनाये रखने की कला के विशेषज्ञ होते हैं। इनके सामने एक ही प्रेरक सिद्धान्त होता है। और वह यह कि, अधिक उत्पादन के लिए मजदूरों की मनोदशा को उत्साहपूर्ण रखना अनिवार्य है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए चल रहा यह सतत प्रयास उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ा है। अमेरिकी किसान के पास अपनी जमीन होती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे अपने आपसे सबल प्रोत्साहन मिलता है। प्रति एकड़ अधिक पैदावार से उसके और उसके परिवार की आय बढ़ती है।

उद्योग के विकास और शहरी आबादी में बढ़ोतरी के साथ-साथ कृषि पदार्थों की माँग का भी विस्तार हुआ है। खेतिहर मजदूर खेत छोड़कर शहरी औद्योगिक श्रम केन्द्रों की ओर भागते जा रहे हैं, तथापि कृषि पदार्थों की माँग पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने का एक ही तरीका था और अब भी है और वह यह कि फार्मों पर प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ाया जाये।

मशीनें, उर्वरक और कृमिनाशक रसायन देकर उद्योग तथा विज्ञान ने किसान की सहायता की है। निरन्तर बढ़ती हुई माँग ने किसान के लिए जो अवसर उपलब्ध किया है, उसका लाभ उठाने में उसने इस सहायता का पूरा-पूरा उपयोग किया है। उन्नत कृषि उत्पादन अधिकांशतः आर्थिक प्रोत्साहन और उन्नत तरीकों तथा सुविधाओं के सम्मिलित प्रयोग का परिणाम है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विस्तार के पीछे प्रोत्साहनों का प्रमुख हाथ रहा है। आदमी कितना काम करे और कितना पैदा करे इसका निर्णय लाभमूलक प्रोत्साहन ही करता है। वैयक्तिक प्रतिष्ठा, अच्छी कार्य-स्थिति, सुकार्य भावना तथा आर्थिक प्रोत्साहन, ये सब बातें अधिक उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं। इसी ढाँचे में 'वर्ग-संघर्ष' का मार्क्सवादी सिद्धान्त (अर्थात् पूँजीपतियों द्वारा वर्ग विशेष का शोषण बनाम मजदूरों द्वारा वर्ग विशेष के प्रति विद्रोह) का कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः लोकतन्त्री उद्योगवाद से उस सिद्धान्त का कोई मेल नहीं है, क्योंकि उससे उत्पादन को बाधा पहुँचती है।

उन्नत उत्पादन और वर्द्धमान जीवन स्तर

लेनिन ने एक बार लिखा था : 'जन-सामान्य का जीवन स्तर उठाने के लिए अतिरिक्त पूँजी का उपयोग नहीं किया जायेगा। क्योंकि इसका अर्थ होगा पूँजीपतियों के मुनाफे में कमी।' अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के तत्त्वों को समझ लेने पर लेनिन का यह वक्तव्य बिल्कुल

असंगत लगता है। क्योंकि उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ जन-सामान्य का जीवन स्तर भी उन्नत होता रहा है। मजदूरी और मूल्यों का आनुपातिक सम्बन्ध देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है। आज का अमेरिकी मजदूर अधिक और अच्छी वस्तुएँ खरीद सकता है और वह भी इतना कम काम करके जितना कम उसने इतिहास में पहले कभी नहीं किया।

उत्पादन-वृद्धि के फलस्वरूप जितनी 'अतिरिक्त पूंजी' का निर्माण हुआ उसका उपयोग जन-सामान्य का जीवन स्तर उठाने के लिए निरन्तर किया जाता रहा है। और इसका भी कारण यही है कि व्यापक उत्पादन के लिए व्यापक खपत जरूरी है, और ये दोनों ही बातें व्यापक क्रय शक्ति पर निर्भर करती हैं।

आज के दो सबसे बड़े औद्योगिक देशों में उपयोग्य सामग्री खरीदने के लिए कितने समय तक काम करना जरूरी है इस पर विचार करने से व्यावहारिक परिणाम स्पष्ट हो जायेंगे। औसत अमेरिकी मजदूर को एक जोड़ा जूता खरीदने के लिए ८ से १० घण्टे तक काम करना पड़ेगा, जबकि उसी क्वालिटी का एक जोड़ा जूता खरीदने के लिए औसत रूसी मजदूर को ७० से १०० घण्टे तक काम करना पड़ेगा। एक सूट खरीदने के लिए एक अमेरिकी को २५ से ३० घण्टे तक काम करना पड़ेगा, रूसी मजदूर उसके लिए १२० से १४० घण्टे तक खटेगा। अपनी एक घण्टे की मजदूरी से अमेरिकी मजदूर एक किलो से भी अधिक मांस खरीद सकता है, जब कि एक रूसी मजदूर को उसके लिए तीन से चार घण्टे तक काम करना पड़ेगा। २० दिन में एक अमेरिकी इतना पैसा कमा लेगा कि एक आधुनिक रेफ्रिजरेटर अथवा बिजली का चूल्हा खरीद लें। लेकिन, इसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक रूसी को कम-से-कम दो महीने खटना पड़ेगा।

अमेरिकियों ने उत्पादन का पुरस्कार न केवल भौतिक पदार्थों के रूप में ही प्राप्त किया है, बल्कि विश्राम के समय और मनोरंजन के रूप में

भी उन्हें बड़े हुए उत्पादन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सब बढ़ते हुए उत्पादन की दैन है। १९०० के बाद से अब तक काम पर लगे अमेरिकियों की विश्राम की घड़ी लगभग दूनी हो गई है और ऐसा लगता है कि भविष्य में वह और बढ़ेगी। १९१० के बाद से जो आंकड़े सकलित किये गये हैं, उनके अनुसार अमेरिकियों ने कुल वृद्धि की दो-तिहाई तो माल और सेवाओं के रूप में ली है और शेष एक-तिहाई काम के घटे हुए घण्टे और बड़े हुए मनोरंजन के रूप में।

विश्राम की घड़ी में इसी वृद्धि के कारण लाखों करोड़ों डालर के कई नये उद्योगों की स्थापना सम्भव हुई है। ये नये उद्योग मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुएँ अथवा सेवाएँ उपलब्ध करते हैं। ये नये उद्योग अमेरिकियों के परिवर्तित एवं परिवर्तनशील सामाजिक रीति रिवाजों के लिए आवश्यक उपादानों का निर्माण करते हैं।

आज से पचास साल पूर्व किसी मजदूर का मछली का शिकार करने अथवा गोल्फ खेलने के लिए निकलना अपने आप में एक दृश्य बन जाता था। आज यह इतनी साधारण बात है कि मछली का शिकार करना अथवा गोल्फ खेलने जाते हुए मजदूर की ओर कोई देखेगा तक भी नहीं। विश्राम का समय और वैयक्तिक आय बढ़ने से जन-सामान्य के सांस्कृतिक उन्नयन को भी सहायता मिली है। अमेरिका में प्रचारात्मक कार्यों के लिए संस्कृति को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, फिर भी वहाँ आज लगभग २०० समस्वर वाद्यवृंद और २,००० नाटक मण्डलियाँ हैं, जब कि ५० करोड़ किताबें प्रति वर्ष बिक जाती हैं।

आजकल अमेरिकी लोग प्रति सप्ताह ५ दिन आठ घण्टे काम करते हैं। वर्तमान प्रवृत्तियों को देखकर लगता है कि भविष्य में काम का घण्टा और कम होगा और सवेतन छुट्टियाँ और बढ़ेगी। स्वचालन प्रणाली की प्रगति के साथ सप्ताह में काम के दिन और घट जायेंगे। बड़े हुए उत्पादन और रोजगारी को संतुलित करने के लिए ऐसा करना जरूरी

होगा। उन्नत तरीकों और नये प्रकार की शक्ति का उपयोग होने से मजदूरों की उत्पादन-क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन पहले से अधिक होगा। इस उत्पादन-वृद्धि को देखते हुए मूल्यो और मजदूरी के स्तरों में इस प्रकार परिवर्तन करना पड़ेगा कि लोग कम घण्टे काम करके अधिक और अच्छा माल खरीद सकेंगे। यह कोई थोथी भविष्यवाणी नहीं, यह अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अतीत और वर्तमान पर आधारित एक ठोस पूर्वाभास है।

व्यापक उपभोक्ता बाजार

‘पूँजीवाद’ की प्रायः यह कहकर आलोचना की गई है कि वह एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था है जिससे कुछ ही व्यक्तियों को लाभ होता है। यह विशेष महत्त्व की बात नहीं कि पुरानी पूँजीवादी व्यवस्था के विषय में यह आरोप सही रहा हो। विशेष महत्त्व की बात तो यह है कि ‘अनेक का लाभ’ ही अमेरिका के आज के ‘जन-पूँजीवाद’ का आधार है। उपभोग्य वस्तुओं का व्यापक उत्पादन बिना व्यापक उपभोक्ता बाजार के चल ही नहीं सकता।

व्यापक उपभोक्ता बाजार के लिए प्रारम्भिक बातें

केवल जनसंख्या विशाल होने से ही व्यापक उपभोक्ता बाजार की गारंटी नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता तो जिन देशों की जनसंख्या करोड़ों में है, उनके लोगों का जीवन स्तर स्वयं ऊँचा हो जाता। लेकिन आर्थिक दृष्टि से लोगों की गिनती तभी माने रखती है जब वे आर्थिक प्रक्रिया में पूरी तरह योग देते हो। इसलिए व्यापक उपभोक्ता बाजार की कुजी विशाल जनसंख्या नहीं है अपितु यह बात है कि कितने व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से उपभोक्ता बाजार में भाग लेने के योग्य हैं।

जो लोग केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की गुजर भर कर पाते हैं, व्यापक उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से प्रायः अस्तित्वहीन हैं। उनकी एक प्रकार से जमीन में गड़े सोने से उपमा दी जा सकती है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि (अध्याय ४) व्यापक उपभोक्ता बाजार का द्विविध विकास होना चाहिए, यह एक विशाल आर्थिक इकाई से दूसरी इकाई तक फैला हुआ होना चाहिए तथा सभी

प्रकार के व्यक्तियों द्वारा अधिकांश सख्या में इस आर्थिक प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के रूप में भाग लिया जाना चाहिए। बाजार में दोनों बातें, 'व्यापकता' तथा 'गहराई' होनी चाहिए। अनेक देशों में पहली चीज होती है तो दूसरी नहीं, अर्थात् बाजार 'उथला' रहता है। इन देशों की जनसंख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, उत्पादन तथा समृद्धि सीमित रहती आई हैं। उनके उपभोक्ता बाजारों में 'गहराई' का अभाव होता है।

अमेरिका में लगातार वर्षों तक दोनों ही बातों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया गया। पहले 'व्यापकता' पर बल दिया गया और अब 'गहराई' पर दिया जा रहा है।

पहला उद्देश्य तो स्वतन्त्र रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आनेवाली बाधाओं को दूर करके पूरा हो गया।

व्यापार में आनेवाली मानवीय बाधाओं को दूर करना

संघटन की धाराओं के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में मूल १३ अमेरिकी राज्यों का जो असतोषजनक अनुभव हुआ, उसका उन व्यक्तियों के विचारों पर प्रभाव पड़ा जिन्होंने १७८६ में सघीय संविधान बनाया। धारा १ अनुच्छेद १० में कहा गया 'कोई भी राज्य बिना कांग्रेस की अनुमति के आयात या निर्यात पर चुगी या शुल्क नहीं लगा सकेगा।' इससे अमेरिकी सीमाओं के भीतर व्यापार स्वतन्त्र हो गया।

साथ-ही-साथ संविधान ने कांग्रेस को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह राज्यों के बीच तथा विदेशों से व्यापार को नियमित करे।

नए राष्ट्र के इन प्रारम्भिक वर्षों में अधिकतर व्यापार जल मार्ग एटलांटिक महासागर या नदियों द्वारा होता था। सड़कें बहुत कम थीं तथा अच्छी नहीं थीं और स्थल मार्ग से माल भेजना मंहगा पड़ता था। इन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में जो पहला विशद कानून बना उसमें समुद्री तथा नदी मार्गों से नौवहन पर प्रकाश डाला

गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता की स्थिति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू में किए गए कुछ निर्णयों से और सुदृढ़ हो गई। १८२४ में न्यायालय ने फैसला दिया कि 'संविधान स्वीकार करने में अगर एक उद्देश्य अन्य सब बातों से ऊपर है तो वह राज्यों के बीच पारस्परिक व्यापार को समस्त वैयक्तिक तथा विशेष प्रतिबन्धों से मुक्त रखना है...।'

बाद के निर्णयों से यह सिद्ध हो गया कि संविधान ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में कांग्रेस को जो अधिकार प्रदान किए थे, वे संविधान पास करने के समय ज्ञात अथवा प्रयोग में आनेवाले तरीकों तक ही सीमित नहीं थे, अपितु उन्होंने देश की प्रगति का अनुसरण किया। १८६६ तक रेलों का विकास हो जाने के कारण कांग्रेस ने स्थल मार्ग से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में पहली बार सघीय कानून बनाए।

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इन सिद्धान्तों के विरोधी भी थे। कुछ विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसने कहा कि यह 'निर्विवाद है तथा निश्चित सिद्धान्त हो चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में अधिकार विभाजित नहीं हो सकते और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून ही सर्पोपरि हैं।' न्यायालय अपने इस निर्णय पर सदैव दृढ़ रहा कि 'जहाँ तक व्यापारिक कानूनों का प्रश्न है वे सभी अमेरिकियों पर समान रूप से लागू हैं तथा इस दृष्टि से अमेरिकियों में कोई भेद नहीं।'।

परिवहन तथा संचार का योग

अकेले कानून से ही देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बाजार की स्थापना नहीं की जा सकती। उत्पादनकर्त्ता के पास से माल बाजार में

आना चाहिए। बिना परिवहन के व्यापार बाजार नहीं हो सकता। ऐसा न होने पर उद्योगो अथवा कृषि का उत्पादन या तो बिकेगा ही नहीं या फिर वही आस-पास के उस क्षेत्र में बिकेगा जहाँ उत्पादन होता है। परिवहन व्यवस्था के पर्याप्त विकास के बिना व्यापार पर प्रतिबन्धों को दूर करने के लिए अमेरिकी कानूनों का कोई अर्थ ही नहीं होता।

१८६५ के गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ। अब बीसवीं सदी के मध्य में प्रमुख रेलवे लाइनों की लम्बाई लगभग २,४०,००० मील है तथा और सभी प्रकार की लाइनों की लम्बाई लगभग ४,००,००० मील है। यह कुल लम्बाई पृथ्वी की परिधि से २५ गुना से अधिक है। इन लाइनों पर ४३ हजार इंजन, बीस लाख माल डिब्बे तथा ४,४,००० यात्री डिब्बे और १२०,००० अन्य विशेष डिब्बे चलते हैं।

इसके अतिरिक्त अमेरिकी सड़कों पर ६० लाख ट्रक चलते हैं, ३०,००० अन्तर्राज्यीय तथा लम्बे सफरवाली बसें हैं, जो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चलती हैं। गत वर्ष ५३० लाख मोटरो ने—इसमें ४४० लाख निजी थी—५०० अरब मील की यात्रा की।

परिवहन के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक साधन जल-मार्ग थे। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उनका योग निरन्तर महत्त्वपूर्ण रहा है। घरेलू जलीय मार्गों में यातायात क्षमता का भारी विकास हो गया है। यह बाँधों आदि के निर्माण तथा विशेष प्रकार की डीजल इंजनों से चलनेवाली नावों को उपयोग में लाकर किया गया। जलीय मार्गों से जानेवाले सामान में अब भी कच्ची सामग्री, कृषि उत्पादन तथा ईंधन का बड़ा भाग होता है, लेकिन अर्द्ध तैयार तथा तैयार माल, जैसे लोहा और इस्पात की चीजे, पेट्रोल, रसायन तथा मशीनें भी नदियों, नहरों व झीलों के रास्ते अधिक मात्रा में ले जाये जा रहे हैं।

विमान यातायात के आश्चर्यजनक विकास के महत्त्व पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज प्रतिवर्ष अमेरिका के भीतर ढाई करोड़

व्यक्ति विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन तथा तार व्यवस्था भी इतनी प्वाप्त है कि अपेक्षाकृत दूर बसे क्षेत्रों को भी अच्छी तरह ये सेवाएँ मिल जाती हैं। सम्प्रति सम्पूर्ण अमेरिका में ५०० लाख से अधिक टेलीफोन प्रयोग में आ रहे हैं।

अगर हम अमेरिका का ऐसा मानचित्र देखें, जिसमें रेलवे लाइने, नहरें, नौवहन योग्य भीलें तथा नदियाँ, विमान मार्ग, सड़के तथा परिवहन के अन्य साधन दिखाए गए हो तो हमें वह परस्पर काटती लाइनों के भूल भुलैए का चित्र जान पड़ेगा। मानव शरीर की धमनियों की भाँति परिवहन तथा संचार के ये साधन भी देश के सूदूरस्थ क्षेत्रों तक अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की परिधि को फैलाये हुए हैं। वे क्षैतिज रूप से व्यापक बाजार को वास्तविकता का रूप देते हैं।

वैयक्तिक आय तथा उपभोक्ता बाजार

लेकिन अकेली 'व्यापकता' काफी नहीं है। एक व्यापक खपत बाजार में 'गहुराई' अर्थात् खपत की अधिकतम मात्रा भी होनी चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए सरकार, व्यापारी तथा श्रमिकों ने संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग वैयक्तिक आयों के पुनःस्तरीकरण के लिए प्रयास किया है। प्रायः सभी पार्टियाँ इस बात के प्रति सजग नहीं थी कि उनके प्रयासों का अन्तिम परिणाम व्यापक उपभोक्ता बाजार का विकास हो। उद्देश्य अलग-अलग थे। फिर भी इनके परिणामस्वरूप संयुक्त बाजार का विकास हुआ।

इस बाजार का मूल भाग मध्यम आय के परिवार हैं। आकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि यह आवश्यक नहीं कि वैयक्तिक आय में वृद्धि के साथ खपत में भी उसी अनुमान से वृद्धि हो। एक परिवार, जिसकी कुल आय १७०० डालर है, अपनी यह सारी राशि खर्च कर सकता है। दूसरी ओर एक परिवार है, जिसकी आय १५,००० डालर है अपनी आय में से ६ हजार डालर खर्च करके बाकी बचा लेता है। एक

परिवार की जिसकी आय बहुत अधिक है—मान लीजिए कर चुकाने के पश्चात् यह राशि ५० हजार डालर है—तो वह अपनी कुल आय का दो तिहाई भाग बचाकर नियोजन कार्य में लगा सकता है। 'स्पष्टतः' खपत में बढ़ती हुई आय के अनुपात से वृद्धि नहीं होती।

एक कम आयवाला परिवार अपनी सम्पूर्ण आय उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, फिर भी उसका कुल व्यय अल्प ही होगा। दूसरी ओर अधिक आयवाला परिवार उपभोक्ता वस्तुओं पर अपनी आय का थोड़ा-सा ही भाग खर्च कर शेष बचा सकता है। इस प्रकार व्यापक खपत बाजार न तो अधिक दरिद्रों पर और न कुछ थोड़े से धनियों पर निर्भर करता है। इसका स्वस्थ विकास बड़ी संख्या में ऐसे 'मध्यम आय' के परिवारों पर निर्भर करता है जिनकी आय उस स्तर के आस-पास हो जहाँ अर्थ-शास्त्रियों के कथनानुसार सतोषजनक 'व्यय की प्रवृत्ति' हो।

वैयक्तिक आयों का पुनःस्तरीकरण

'मध्यम आय' के आधार का विकास कट्टर सिद्धान्तों या विचारपूर्वक आयोजना का परिणाम या लक्ष्य तक नहीं रहा है। फिर भी सरकार, व्यापारियों तथा श्रमिकों ने अनेक प्रकार से इसके विकास में योग दिया है। अनेक बार मानवीय कारणों से श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए गए, लोकतन्त्री संस्थाओं ने पुरानी पूँजीवादी व्यवस्थाओं की असमानताओं को दूर करने का काम सम्भाला। जब ये कदम आर्थिक दृष्टि से मजबूत सिद्ध हुए तो ये नई व्यवस्था के अविभाज्य अंग बन गए।

अन्य परिवर्तन व्यावहारिक अनुभव तथा आर्थिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप हुए। १९१४ में हैनरी फोर्ड ने अपने मोटर कारखाने के एक मजदूर की प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी ५ डालर तक बढ़ा दी। उस समय उनका उद्देश्य अपने कारखाने में आने के लिए अधिक दक्ष कारीगरों को आकर्षित करना था ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, माल

को तैयार करने में होनेवाला व्यय कम किया जा सके और फिर उसे मस्ती कीमतों पर बेचा जा सके ताकि माल की बिक्री में वृद्धि हो। हैनरी फोर्ड ने अपने निर्णय की भारी उलझनों को शायद तब नहीं समझा हो, जिसे प्रायः व्यापक उत्पादन तथा खपत द्वारा समृद्धि की दिशा में नए दृष्टिकोण का प्रारम्भ कहा जाता है। फोर्ड को इन पेचीदगियों का ज्ञान हो या न हो लेकिन वह व्यवस्था के उन बुनियादी सिद्धान्तों से प्रेरित और बाध्य हुआ, जो उस समय ऐसी श्रम तथा मजदूरी सम्बन्धी नीति को अपनाने के लिए उभर आए थे, जिसका उद्देश्य अमेरिकी आर्थिक विचारधारा को व्यापक रूप से प्रभावित करना था।

जैसी आशा थी, फोर्ड की मजदूरी सम्बन्धी नीति का दूसरे व्यापारियों ने उत्साह के साथ स्वागत नहीं किया। यह नीति उनकी पुरानी पूँजीवादी धारणाओं के विरुद्ध थी। व्यापार की नई प्रवृत्तियों को जन्म देकर फोर्ड ने अधिकांश मार्गदर्शकों को भौति उपहास तथा विरोध का सामना किया। फोर्ड के साथियों तथा प्रतियोगियों ने इन नई प्रवृत्तियों की शुरूआत पर बुरा माना। वे स्वयं को अपनी पुरानी स्थिति में ही सुरक्षित समझते थे। कौन जानता था कि आगे क्या होनेवाला है ?

लेकिन समय तेजी से बदल रहा था। आज के अमेरिकी उद्योगपति 'व्यापक उत्पादन तथा प्रति वस्तु पर कम मुनाफा' और 'अधिक मजदूरी तथा कम कीमत' के सिद्धान्तों को आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। वे बड़ी सख्या में मध्यम आय के परिवारों के अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हैं।

मध्यम आय के परिवारों की निरन्तर वृद्धि का बहुत कुछ कारण मजदूर यूनियनों है, जिन्होंने वेतन वृद्धि तथा नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्न किया। औद्योगिक विज्ञान की प्रगति से यूनियनों के प्रयासों को बल मिला। इससे यह महसूस किया जाने लगा कि फैक्ट्रियों में अधिक शिक्षित तथा अधिक दक्ष कारीगर रखे जाएँ। अदक्ष कर्मचारियों के लिए नौकरियाँ कम हो गई हैं, श्रमिकों में कारीगर बनने

की प्रवृत्ति हो गई है जिससे अधिक वेतन की प्राप्ति होने पर जीवन-यापन का स्तर बदलता है। अधिक आय तथा जीवन-यापन का स्तर उन्नत होने से वह मध्यम आयवाले परिवारों में आ जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से अब वह वे वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त कर सकता है जो पहले उसकी पहुँच के बाहर थी।

आयों के पुनः स्तरीकरण में अमेरिकी सरकार ने भी मुख्यतः वित्तीय तथा कर सम्बन्धी नीतियों का प्रयोग कर महत्वपूर्व योग दिया है। संघीय आय कर विशेष महत्व का है। करो की दरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं जिससे बहुत अधिक आयों में भारी कटौती हो जाती है। इस प्रकार एक परिवार जिसकी आय ५००० डालर है, अगर ५३६ डालर या कुल का दस प्रतिशत अदा करता है तो १०,००० डालर की आयवाला परिवार २००० डालर या २० प्रतिशत राशि चुकाएगा। आय बढ़ने के साथ उसी के अनुक्रम कर बढ़ जाते हैं। जिस परिवार की वार्षिक आय ६० हजार डालर है, उसे आधी से अधिक आय या ४६,००० डालर आय करके रूप में देने होंगे।

स्तरों के समानीकरण में इस क्रमिक ऊर्ध्वमान कर प्रणाली का प्रभाव अत्यन्त रोचक है। दो सम्पन्न परिवारों का उदाहरण लीजिए। एक की वार्षिक आय १७ हजार डालर है तथा दूसरे की ४००,००० डालर। साधारण हिसाब से ही पता चलता है कि दूसरे परिवार की आय पहले से २५ गुनी है। लेकिन यह स्थिति करों की अदायगी से पूर्व की है। कर चुकाने के बाद पहले परिवार के पास १० हजार डालर बचते हैं तथा दूसरे के पास ६० हजार डालर। अब दूसरे परिवार की आय पहले परिवार की अपेक्षा केवल ६ गुनी रह जाती है।

संसार के समस्त भागों में लोगों ने अमेरिकी टेलीविजन के लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के बारे में सुना है। अत्यन्त कठिन प्रश्नों का, जो ज्योतिष विद्या से लेकर शेक्सपीयर तक सम्बन्धित हो सकते हैं, सही उत्तर देकर अगर कोई प्रतियोगी ६४,००० डालर की राशि जीत लेता है तो

इसका यह अर्थ नहीं कि यह सारी राशि उसकी हो जाएगी। घरेलू राजस्व का विभाग उसकी इस राशि का लगभग आधा भाग आय कर के रूप में ले लेगा। ६४,००० डालर की राशि प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगी को लगभग ५००,००० डालर जीतने चाहिए।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीतनेवाले को यह क्रमिक कर प्रणाली कठोर भले ही लगे, इसका उद्देश्य पूँजीवालों को कोई दंड देना नहीं है। इसके विपरीत अमेरिकी कर कानूनों में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य धनिकों की अधिक आय को अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लगाना है। यह कार्य नियोजन पूँजी के प्रति नरम रख अपनाने से सम्पन्न होता है।

कुल मिलाकर अमेरिकी कर प्रणाली निष्पक्ष है तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। आयों के अन्तर को दूर करके तथा मध्यम आयवाले परिवारों की स्थिति सद्बुद्ध करके इस प्रणाली ने व्यापक अमेरिकी उपभोक्ता बाजार के विकास में बड़ा योग दिया है।

उपभोक्ता ऋण तथा अमेरिकी बाजार

उपभोक्ता ऋण की कई कारणों से आलोचना की गयी है, फिर भी व्यापक अमेरिकी खपत बाजार के विकास तथा उसे बनाए रखने में इसने मुख्य भूमिका अदा की है। आओ हम देखे कि व्यवहार में उपभोक्ता ऋण किस प्रकार क्रियान्वित होता है।

उदाहरण के तौर पर एक युवा दम्पति है, जिनकी शादी को एक साल हुआ है और उनके बच्चा होनेवाला है। उनकी आय ५,००० डालर है। वह एक ऐसा मकान खरीदना चाहते हैं जो १५,००० डालर में बिक रहा है। उनकी आय तथा जीवन-यापन का तरीका ऐसा है कि वे साल में ८०० डालर या १,००० डालर तक बचा लेते हैं। इन परिस्थितियों में मकान खरीदने के लिए उन्हें १५ साल तक बचत करनी पड़ेगी। लेकिन तबतक उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा और अपने माँ-

बाप से अलग रहने की तैयारी में होगा। उस युवा दम्पति को तब उस मकान की जरूरत नहीं रहेगी और इस प्रकार मकानों के बाजार में एक खरीदार कम हो जाएगा।

ऐसे लाखों परिवार हैं, जिनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ हैं। अगर मकान की सारी कीमत खरीद के समय ही चुकानी पड़े तो मकानों की माँग तेजी से गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ऋण सहायक होता है। उक्त युवा दम्पति जिसकी आय ५,००० डालर सालाना है, १५,००० डालर की कीमत का मकान नहीं खरीद सकता। लेकिन २० साल में यह परिवार १००,००० डालर कमाएगा। अतः उपभोक्ता ऋण लेकर वे मकान तो अभी खरीद लेंगे जबकि वास्तव में उन्हें जरूरत है और थोड़ी थोड़ी करके उस मकान की कीमत चुकाने के साथ मकान का लाभ भी उठाते रहेंगे। 'अब खरीदो और बाद में चुकाओ' के सिद्धान्त ने अमेरिकी उपभोक्ताओं की आदतों को बहुत बदल दिया है। वे हर चीज उधार खरीद सकते हैं, चाहे वह कपड़ा हो, जूते हो, अगीठी हो या ट्रेक्टर। सैकड़ों हजारों स्त्रियाँ प्रतिदिन दुकानों पर जाती हैं और बड़ी मात्रा में उधार खाते में सामान खरीदती हैं। वे 'चार्ज खातों' का प्रयोग करती हैं, इसके अन्तर्गत ग्राहक को एक निश्चित अवधि तक माल की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। इसमें ग्राहक को उस मूल्य से अधिक नहीं चुकाना पड़ता जो वह अन्यथा साधारण खरीद के समय चुकाता।

दूसरे प्रकार की उधारी खरीद में जो 'किश्त योजना' के नाम से मशहूर है, किश्तों की कुल राशि कुछ अधिक होती है। उसमें मूल्य के साथ-साथ उधार माल देने पर भी कुछ शुल्क लिया जाता है। अगर श्रीमती जोन्स कपड़े धोने की एक नई मशीन खरीदना चाहती है, जिसकी कीमत १९९ डालर है, तो वह उसे 'आसान किश्तों' पर मूल्य अदायगी के आधार पर खरीद सकती है। वे पाँच डालर शुरू में देकर शेष राशि १२ महीनों में १७.५० डालर की किश्त के हिसाब से चुका सकती है। लेकिन यह कुल राशि १९९ डालर नहीं बैठेगी, बल्कि २१५ डालर हो

जाएगी। यह १६ डालर की अतिरिक्त राशि उधार देने का एक प्रकार का शुल्क होगा। यह राशि अधिक देने के बावजूद श्रीमती जोन्स ने नगद मूल्य देने की बजाय किश्तों में खरीदना पसन्द किया। क्योंकि यह सन्देह-जनक था कि श्रीमती जोन्स सारा मूल्य एक साथ चुका पाती। 'किश्त योजना' ने अनेक अमेरिकियों के लिए यह सम्भव बना दिया है कि वे अपनी इच्छित वस्तुओं को जरूरत के समय प्राप्त कर सकें।

एक अमेरिकी महिला 'अतिरिक्त शुल्क' का यह भार एक और कारण से बरदाश्त पसन्द कर सकती है। अगर उसके पास १६६ डालर है और वह कपड़े धोने की नयी मशीन लेना चाहती हैं तथा उसे इसका मूल्य नकद चुकाना पड़ता है तो अन्ततः उसके पास एक कपड़े धोने की मशीन ही आ पायेगी। लेकिन अगर वह अपने धन को 'छोटी अदायगियों' में बाँट देती है तो वह कई चीज़ें खरीद सकती है और उन सबकी कीमत बाद में थोड़ी-थोड़ी राशि की मासिक किश्तों के रूप में चुका सकती है।

इस प्रकार वह अपनी आवश्यकता और इच्छा की अनेक वस्तुओं का लाभ एक साथ उठा सकती है। शायद अमेरिकी पति यह पसन्द करेंगे कि उनकी 'पत्नियों' में खरीदारी के लिए इतना दुनिवार आकर्षण न हो। लेकिन किश्त योजना के विषय में पतियों की भी ऊँची धारणा है। वे एक नई कार खरीदने के लिए इसे एक उपाय समझती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता ऋण एक महत्वपूर्ण चीज़ है।

उपभोक्ता ऋण की आलोचनाओं में सभी पूर्णतः निराधार नहीं हैं। यह कहा जाता है कि उपभोक्ता आवश्यक पैसा बचाकर नकद मूल्य चुका कर सामान खरीद सकते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क की राशि नहीं देनी पड़ेगी। फिर भी मानव का यह स्वभाव है कि वह ऋण चुकाने के लिए धन बचा सकता है बजाय इसके कि बाद में सामान खरीदने के लिए धन अलग से इकट्ठा करे।

कुछ आलोचकों का कहना है कि उपभोक्ता-ऋण अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा करता है। यह आरोप सर्वथा असत्य तो नहीं,

लेकिन इससे यह कठोर परिणाम नहीं निकलना चाहिए कि ऋण पूरी तरह हानिकर है और इसलिए उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। व्यवहार में अमेरिकी उपभोक्ताओं ने ऋण करने में कोई ज्यादाती नहीं की है। उन्होंने अपनी कुल सम्पत्ति से कहीं कम कीमत का उधार सामान खरीदा है। १९५४ में अमेरिकियों पर मकान-रेहन-ऋण ७५ अरब डालर था, स्थायी खरीदों, 'चार्ज-खातों,' तथा वैयक्तिक ऋणों की राशि ३० अरब डालर थी तथा 'वित्तीय ऋण' अर्थात् बैंकों व फर्मों से लिए गए ऋणों की राशि १० अरब डालर थी। कुल मिलाकर उपभोक्ता ऋण लगभग ११५ अरब डालर था।

यह एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को दूसरी ओर ३८० अरब डालर वसूल भी करने थे। बड़े-बड़े व्यापारियों तथा सरकार पर उतना ऋण था। उपभोक्ताओं का काफी धन वित्तीय संस्थाओं के पास भी बीमा पालिसियों तथा बैंक निवेशों के रूप में था। कुल मिलाकर अमेरिकियों ने अपनी कुल आय से कम खर्च किया।

×

×

×

विशेष आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में अनेक प्रोत्साहन तथा तरीके विकसित हो गए हैं। सघीय सरकार ने व्यापारिक, सामाजिक तथा वित्तीय कानूनों द्वारा व्यापारियों के उत्पादन बढ़ाकर, उपभोक्ता ऋण तथा श्रमिकों के लिए लाभदायक करारों द्वारा और मजदूर यूनियनों ने मजदूरी की माँग द्वारा एक व्यापक उपभोक्ता बाजार के विकास में मिलकर सहायता की है।

अधिकांश मध्यम आयवाले परिवारों के सुदृढ़ आधार पर स्थित अमेरिकी उपभोक्ता-बाजार ने उल्लेखनीय 'व्यापकता' तथा 'गहराई' प्राप्त की है। बिना किसी प्रकार की कृत्रिम बाधा के यह एक तट से दूसरे तट तक व्याप्त है और सभी प्रकार के उपभोक्ता इस आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह व्यापक उपभोक्ता बाजार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सभी के लिए आर्थिक सम्पन्नता एक स्वतन्त्र समाज में ही सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। यह 'सर्वहारा श्रमिकों' के पूँजीवादी शोषण के प्रचार के नारे का जबरदस्त उत्तर है।

प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार

मार्क्स सिद्धान्त की एक प्रमुख बात यह है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत धन अन्ततः कुछ बड़े-बड़े उद्योगों के हाथ में इकट्ठा हो जाता है और इनके मालिक फिर खुलकर सर्वहारा श्रमजीवियों का शोषण करते हैं। धन और शक्ति बड़े एकाधिकारवाले उद्योगों के हाथ में आ जाने से परिश्रम का लाभ तो कुछ बड़े आदमी भोगते हैं और मजदूरों के लिए केवल गुजारे भर के लिए ही कुछ बच रहता है। यह दलील प्रायः सुनने में आती है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था ऐसे ही एकाधिकारवाले उद्योगों एवं व्यक्तियों के हाथ में है और वास्तव में वे ही राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का नियंत्रण करते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध यह सिद्ध करने के लिए हमारे पास प्रमाण है कि 'व्यापक उत्पादन, व्यापक खपत तथा व्यापक क्रय शक्ति' पर आधारित व्यवस्था में अन्धाधुन्ध शोषण आर्थिक दृष्टि से असंभव है। अमेरिकियों का दावा है कि उनकी अर्थ-व्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बारीकी से विचार की आवश्यकता है।

एकाधिकार अथवा मूल्य प्रतियोगिता

यह याद दिलाना लाभदायक होगा कि 'एकाधिकार' का अर्थ है प्रतियोगिता का पूर्णतः अभाव। एकाधिकारवादी अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता के सामने सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होता कि वह इन एकाधिकारवाले उद्योगों द्वारा तैयार माल को ही खरीदे। क्योंकि माल की सप्लाई करनेवाला और होता ही नहीं। एकाधिकार का यही सार है। व्यावहारिक दृष्टि से एकाधिकारवाले उद्योग ग्राहक को बन्दी सा

बना कर रखते हैं।

इस प्रकार बन्दी किये गये उपभोक्ताओं के साथ कारोबार में ये एकाधिकारी उद्योग मनमाने ढंग में अपने माल की किस्म और कीमत निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग यह भी कर सकते हैं कि उत्पादन सीमित कर दें, मुनाफे की मात्रा बढ़ा दे, खरीदने में विभेदात्मक नीति अपनाये तथा मजदूरों को कम वेतन दे, क्योंकि इन मजदूरों को कहीं दूसरी जगह काम करने का अवसर नहीं है। निरंकुश एकाधिकारी उद्योग इस प्रकार आर्थिक जगत में अत्याचारी एवं जनता के शोषक बन सकते हैं। क्या इस प्रकार के पूर्ण एकाधिकारी उद्योग अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान हैं? इस प्रश्न का उत्तर है 'बिल्कुल नहीं।' वहाँ इस प्रकार के उद्योग हो ही नहीं सकते, क्योंकि, अगर और कोई कारण न भी हो, तो पूर्ण निरंकुश एकाधिकारी उद्योग, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन एवं खपत में कृत्रिम कमी होती है, स्वतन्त्र व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था से मेल नहीं खाते।

यह आवश्यक नहीं कि 'एकाधिकार' व्यवस्था हानिकारक ही हो। कुछ विशेष स्थितियों में मितव्ययिता की दृष्टि से यह वाछनीय भी हो सकती है। उदाहरणतः, एक शहर में बिजली की सप्लाई एक कम्पनी करती है, इसी प्रकार गैस सप्लाई, पानी सप्लाई, यातायात के लिए बस व्यवस्था आदि की बात है। ये सब एकाधिकार संस्थाएँ हैं। इन्हें इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि जनता यह समझती है कि इन विशेष कार्यों को कम खर्च और कुशलता से चलाने के लिए एक अकेली कम्पनी का होना अधिक अच्छा है।

अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एकाधिकारवाले उद्योग लोक-प्राधिकारी द्वारा की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत काम करते हैं। कीमतेँ, उत्पादित माल की किस्म, सेवाएँ, मुनाफा संचालन-विधि, पोषण, सुधार, सुविधाओं के विस्तार आदि कार्य सार्वजनिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत रहते हैं। इन शर्तों के साथ एकाधिकार आपत्तिजनक नहीं

है। अमेरिकियों ने पूर्ण एकाधिकार को रोकने की कोशिश की है क्योंकि पूर्ण एकाधिकार उद्योग बाजार को अपना गुलाम बना लेता है और फिर बहुआ उपभोक्ताओं का शोषण करता है।

दूसरी ओर व्यापक उत्पादन तथा व्यापक वितरण पर आधारित मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-प्रतियोगिता सदैव संभव या वांछनीय भी नहीं है। मूल्य-प्रतियोगिता ऐसी हालत में निश्चित रूप से संभव है जब दो समान कार्यवाले या उत्पादक, उदाहरणतः आइसक्रीम या सब्जी विक्रेता, गाँव के बाजार में इसलिए अपनी कीमतों में कटौती करते हैं कि वे एक दूसरे के ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकें। लेकिन ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था अधिक जटिल तथा सुसंगठित होती जाती है मूल्य प्रतियोगिता उतनी ही कम संभव होती जाती है। एक प्रकार के सारे उद्योग में उत्पादन व्यय प्रायः समान होता जाता है, कच्ची सामग्री के मूल्यों में मामूली-सा अन्तर होता है, समान उद्योगों में मुनाफे की मात्रा लगभग बराबर रहती है, मजदूर सघों के साथ वेतन सबंधी जो समझौते किए जाते हैं वे एक विशेष उद्योग के कर्मचारियों के लिए न होकर संपूर्ण उद्योग के मजदूरों के लिए होते हैं। इन कारणों से 'स्वच्छंद' पूंजीवाद की विशुद्ध मूल्य प्रतियोगिता की बात अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के केवल एक छोटे से क्षेत्र में लागू होती है।

बहुत से मामलों में अनियन्त्रित मूल्य प्रतियोगिता वांछनीय नहीं है। जैसे-जैसे लागत और अन्ततः विक्रय कीमत एक समान होती जाती है, विरोधी उत्पादकों के लिए कीमतों में कटौती की स्पर्धा संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से लाभदायक नहीं हो सकती। इससे मुनाफे में भारी कमी तथा उद्योग के विस्तार एवं नवीकरण के लिए कोष में भारी कमी पड़ सकती है। कुछ उद्योग असफलता देख माल का स्तर गिराने के उपाय पर उतर आ सकते हैं। दूसरे घाटे की पूर्ति के लिए अगर वेतनों में कमी की गयी तो मजदूर सघ उसका विरोध करेंगे, जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। संक्षेप में अनियन्त्रित मूल्य प्रतियोगिता

अगर सब स्थानों पर सदैव लागू की गयी तो उससे व्यवस्था का आधार ही कमजोर हो सकता है ।

एकाधिकारवाले तरीकों का प्रतिरोध

निरंकुश एकाधिकार के प्रति अमेरिकी जनता में जबरदस्त विरोध की भावना कोई नयी बात नहीं है । निरंकुश एकाधिकार तथा आपत्ति-जनक व्यावसायिक संयोजनों के प्रति विरोधी भावना उस समय से चली आ रही है जब अमेरिका एक उपनिवेश था । अमेरिकी क्रांति का एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योग-पतियों ने इस बात का प्रयत्न किया कि उन्हें उपनिवेशों में तैयार माल के आयात पर कानून द्वारा एकाधिकार सत्ता प्राप्त हो जाए । ब्रिटिश पूंजीपतियों ने इन उपनिवेशों के निर्माताओं पर रोक लगा कच्चे सामान के लिए इंग्लैंड को ही एकमात्र बाजार बनाने का भी यत्न किया ।

सारा इतिहास देख डाले, अमेरिकी जनता का सदैव यह सिद्धान्त रहा है कि व्यक्तियों को अपने व्यवसाय संबंधी निर्णय के लिए स्वतंत्रता रहनी चाहिए । अमेरिकियों का विश्वास है कि माल का स्तर ऊँचा उठाने, अदक्षता दूर करने तथा उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए व्यक्तियों तथा उद्योगों में खुलकर प्रतियोगिता होनी चाहिए । उनका यह भी विचार है कि स्वतंत्र उद्योग का लक्ष्य मुनाफा कमाना होना चाहिए क्योंकि लाभ की संभावना से नए उद्योगों के लिए आकर्षण पैदा होता है और विकास की ओर अग्रसर अर्थ-व्यवस्था में नयी पूंजी लगती है । ये धारणाएँ इस मूल विश्वास से पैदा हुई हैं कि लोकतंत्री समाज में एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय करने और अपने परिश्रम का फल भोगने का अधिकार है । इस बुनियादी सिद्धान्तों के कारण ही एक शताब्दी पूर्व का अविक्सित अमेरिका आज उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन सका है ।

स्वतंत्र रूप से व्यवसाय के चुनाव तथा कार्य करने की धारणा

अमेरिका में इस विश्वास के कारण कुछ प्रभावित हुई है कि जनता के प्रति सरकार के कुछ उत्तरदायित्व है, सरकार को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कार्य की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई इसकी आड़ में जनता को हानि पहुँचाए। यूरोप के आर्थिक क्षेत्र में 'स्वच्छंद' पूँजीवाद का परिणाम जबकि प्रायः अराजकता तथा निर्बलों एवं असफलता का शोषण रहा, अमेरिकियों ने कानून के मातहत आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया है।

गृह युद्ध के पश्चात् अमेरिका में उद्योगों का काफी विस्तार हुआ। शक्तिशाली कार्पोरेशनों (निगमों) की स्थापना हुई। अनेक कार्पोरेशनों ने प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने प्रभुत्व में लाने का यत्न किया तथा बहुतों को इसमें सफलता मिली। एक सबसे अधिक सफल उपाय था ट्रस्टों (न्यासों) का बनाना। संबद्ध कंपनियों के हिस्सेदार अपना हिस्सा ट्रस्टियों के एक बोर्ड के नाम कर देते और बदले में 'ट्रस्ट प्रमाणपत्र' ले लेते। इस प्रकार ट्रस्टियों का कई संबद्ध कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता था और कभी-कभी तो बाजार पर काफ़ी हद तक आधिपत्य प्राप्त हो जाता था जो प्रायः एकाधिकार ही होता था। शीघ्र ही 'ट्रस्ट' शब्द ऐसे सभी प्रकार के बड़े व्यावसायिक-संयोजनों के लिए लोकप्रिय—अथवा बदनाम—हो गया जिनका उद्देश्य प्रतियोगिता को समाप्त करना था।

जनता में रोष की भावना तब और भड़क उठी जब यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के एकाधिकारवाले संयोजनों के विरुद्ध कानून में उचित व्यवस्था नहीं है। जनता के दबाव पर १८८० में दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मंच से ऐसे तरीकों की निन्दा की, जिनके द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टियों के शब्दों में 'ऐसे कुछ व्यक्ति अनुचित रूप से धनवान होते जा रहे हैं, जो जनता को स्वाभाविक प्रतियोगिता के लाभों से वंचित कर व्यवसायों का संयोजन कर लूट रहे हैं।' दस वर्ष बाद १८९० में एकाधिकार के विरोध में जनता की भावना के कारण सरकार

ने शरमन ट्रस्ट विरोधी कानून बनाया। इसमें यह व्यवस्था की गयी कि 'प्रत्येक करार, ट्रस्ट या अन्य रूप में, संयोजन या कुछ राज्यों के बीच अथवा विदेशी राष्ट्रों से मिलकर व्यापार एवं वाणिज्य में बाधा का षड्यंत्र...गैर-कानूनी है।'

शरमन कानून को पास करना इस दिशा में पहला कदम था। इससे समस्या एकदम सुलभ नहीं गयी। एक तो इस कानून की शब्दावली इतनी लचीली थी कि उससे ट्रस्टों और व्यावसायिक संयोजनों के बनने के काम को रोका नहीं जा सका। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बड़े व्यावसायिक संयोजनों की चालों से बहुतों को तो यह विश्वास हो गया कि स्वतंत्र व्यवसाय के आधार के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। प्रेजीडेंट थ्योडोर रूजवैल्ट ने, जो 'विधिवत व्यापार' में विश्वास करते थे, इन ट्रस्टों के खिलाफ आन्दोलन छेड़ा। परिणाम यद्यपि जनता की आशा के अनुकूल नहीं रहा तथापि कानून के मातहत आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रूजवैल्ट का आन्दोलन एक नाटकीय कदम था।

लेकिन अभी और कानूनी कार्रवाई आवश्यक थी। वुडरो विल्सन ने अपने प्रथम प्रशासन में कानून के अन्तर्गत 'नयी स्वतंत्रता' (न्यू फ्रीडम) की स्थापना का यत्न किया। शरमन कानून को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने १९१४ में क्लेटन कानून पास किया। इसमें बरीयता प्राप्त उपभोक्ताओं के पक्ष में भेदभाव करने, विभिन्न बस्तियों के बीच मूल्यों में अन्तर करने, कम्पनियाँ रखने, विभागों को परस्पर मिलाने या ऐसे अन्य सब कार्यों के लिए निषेध है जिनका लक्ष्य प्रतियोगिता को कम या समाप्त करना है। दूसरी ओर क्लेटन कानून ने मजदूर संघों को मजबूत किया। उसने व्यवस्था की कि 'ट्रस्ट विरोधी कानूनों की किसी भी बात का इस प्रकार अर्थ न निकाला जाय कि मजदूर संघों के अस्तित्व तथा कार्य पर रोक लगे।'

क्लेटन कानून के पालन की निगरानी और 'प्रतियोगिता के अनुचित तरीकों' को रोकने के लिए प्रशासकीय एजेंसी की स्थापना की गयी।

इसका नाम 'फैडरल ट्रेड कमीशन' (संघीय व्यापार आयोग) रखा गया। कमीशन ने प्रतियोगिता के अनुचित तरीको, का पता लगाने के लिए व्यापक आधार रखा। कानून के उल्लंघन का जरा सा भी संदेह होने पर कमीशन को उसके विरुद्ध मुनवाई करने तथा कार्य रोकने की आज्ञा जारी करने का अधिकार था। अगर कोई उद्योग उस आदेश का पालन नहीं करता था तो कमीशन को अधिकार था कि वह मामला संघीय अदालत में पेश कर दे।

कमीशन यद्यपि उसके संस्थापको की बड़ी-बड़ी आशाएँ तो पूरी नहीं कर सका फिर भी वह अनुचित और हानिकारक व्यापारिक हल-चलों की ओर ध्यान आकृष्ट करके तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करके अर्थ-व्यवस्था को बचाए रखने में महत्वपूर्ण कारण रहा है।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् व्यापारी वर्ग में एकाधिकार उद्योग-संयोजनो की नयी लहर आयी। इनमे से कुछ तो व्यापक उत्पादन के परिणाम थे, क्योंकि उनके लिए बड़ी आर्थिक इकाइयो की आवश्यकता पड़ी। और दूसरो का उद्देश्य प्रतियोगिता को रोकना और बाजार पर एकाधिकार करना था। फ्रैंकलिन डी० रूजवैल्ट की सरकार ने ट्रस्ट विरोधी कानूनों की पुनः व्याख्या करके और उन्हें लागू करके इन एकाधिकारवादी संयोजनो के विरुद्ध कदम उठाया। काँग्रेस द्वारा १९३६ में नियुक्त अस्थायी आर्थिक समिति का उद्देश्य ट्रस्ट विरोधी कानूनों का उल्लंघन करनेवालो पर मुकद्दमा चलाने के लिए आधार तैयार करना था। १९३६ में छोटे उद्योगो की रक्षा के लिए राबिन्सन पैटमैन कानून भी बनाया गया। इसके द्वारा विभिन्न बस्तियों में या व्यक्तियों को भेदभावपूर्ण कीमतो पर अथवा निर्बल प्रतिस्पर्द्धी को नष्ट करने के लिए अनुचित रूप से कम कीमतो पर माल की बिक्री गैर कानूनी करार दी गयी। इस कानून की कई बार उसे पेचीदा और निरर्थक बताकर, आलोचना की गयी पर अन्ततः वह काफी लाभदायक सिद्ध हुआ।

अगस्त १९३७ में शरमन कानून में मिलर्ड टाईडिंग संशोधन द्वारा

न्याययुक्त व्यापार की भावना से व्यापक उत्पादन तथा व्यापक वितरण की आवश्यकताओं को संयुक्त करने का प्रयत्न किया गया। इसमें, जैसा कि मैकवायर कानून १९५२ में किया गया, व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था की विचित्रताओं को स्वीकार किया गया तथा व्यापार चिन्हों से अंकित माल को निश्चिन कीमतों पर बेचने के लिए खुदरा व्यापारियों के साथ समझौता करने की छूट दी गयी। व्यापारिक चिन्हों से अंकित माल के लिए लक्स साबुन, जनरल इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर या एलिगेटर का उदाहरण दिया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य उन 'न्याय-युक्त व्यापार' कानूनों को स्वीकृति प्रदान करना था जो कई राज्यों द्वारा बनाए गए थे। इन कानूनों ने खुदरा व्यापारियों के हाथ बाँध दिए और वे स्वेच्छा से किसी वस्तु की कीमत नहीं घटा सकते थे यहाँ तक कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे घाटे से भी माल नहीं बेच सकते थे। स्पष्टतः ऐसे तरीकों से एक विशेष माल के उत्पादनकर्ता को प्रत्यक्ष आर्थिक हानि के बिना भी नुकसान था क्योंकि इनसे उसके माल की प्रतिष्ठा घटती थी। इन तमाम विभिन्न कानूनों का व्यवहार में प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय उनकी किस प्रकार व्याख्या करते हैं। उदाहरणतः, शरमन कानून ऐसे 'हर' करार, संयोजन या षड्यंत्र की निन्दा करता है जो व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने १९११ में स्टैंडर्ड आयल मुकदमे में कानून की व्याख्या करते हुए केवल उन करारों या समझौतों की निन्दा की जो व्यापार में 'अनुचित प्रतिबंध' लगाते हैं। इसे 'औचित्य के नियम' का सिद्धान्त कहा जाता है। इसमें व्यापारिक समूहों के मामलों पर विचार के लिए अदालतों को व्यापक आधार दिया गया। हाल में ही यद्यपि यह सिद्धान्त 'स्वयं उल्लंघन' की धारणा के साथ संयुक्त कर दिया है। 'स्वयं उल्लंघन' से तात्पर्य उन तरीकों से है जो खुद व खुद हानिकारक हैं जैसे कीमतें निश्चित करना, बहिष्कार, बाजारों का विभाजन, उपभोक्ताओं को बाँट लेना, तथा अनुचित रूप से कीमत

घटाकर प्रतियोगिता समाप्त करना। 'स्वयं उल्लंघन' तरीकों की सूची निरन्तर बढ़ रही है और इस प्रकार प्रतियोगितावाली अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के चुनाव के लिए उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता का आश्वासन मिला है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता

इनमें कोई मदेह नहीं कि अधिकांश अमेरिकी प्रतियोगिता से होने-वाले लाभों में विश्वास करते हैं। उनके विचार में प्रतियोगिता मानवीय सफलता, आर्थिक सम्पन्नता तथा सामान्य प्रगति की ओर ले जानेवाली एक प्रेरक शक्ति है। लेकिन 'प्रतियोगिता' से उनका तात्पर्य अर्थ-शास्त्रियों की 'मूल्य प्रतियोगिता' से नहीं। प्रतियोगिता से उनका अभिप्राय यह है कि ऐसी कीमतों पर अच्छा माल और अच्छी सेवाएँ प्रदान करके ग्राहकों को आकर्षित किया जाय जो अधिकांश जनता दे सकती हो। उनका विश्वास है कि किसी भी हालत में ग्राहक बढ़ी न बन जाए और उसके सामने वस्तुओं के चुनाव का अवसर बना रहे। कुछ सार्वजनिक लाभ और सेवा के उद्योगों को छोड़कर, जो अच्छी तरह सार्वजनिक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत होते हैं, अमेरिकी उपभोक्ता के सामने स्वतंत्र प्रतियोगितावाले व्यापारों की लाइन सी लगी रहती है।

एक निष्पक्ष प्रेक्षक यह स्वीकार करेगा कि अमेरिकी उद्योग निरन्तर अपने उत्पादन एवं वितरण के तरीकों के साथ-साथ माल के स्तर को उन्नत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपायों एवं साधनों में प्रगति अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक प्रधान लक्ष्य है।

एकाधिकारवाले उद्योगों के दृष्टिकोण से इस प्रकार का प्रयत्न विरोधी एवं अनावश्यक है। एकाधिकारवाले उद्योग नये उत्पादन, अच्छी सेवाओं और उन्नत सुविधाओं के विकास के लिए क्यों प्रयत्न करें जबकि वे इस बारे में आश्वस्त हैं कि बाजार उनका बढ़ी है।

एकाधिकार में प्रयत्न के लिए कोई प्रेरणा नहीं।

अगर अमेरिकी कार्पोरेशने (निगमे) हर साल अरबों डालर इन्ही उद्देश्यों के लिए खर्च करे जैसा कि वे करती हैं तो निश्चय ही वे एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से बहुत परे हैं।

अकेले एक वर्ष (१९५६) में अमेरिकी उद्योगों ने अपने माल के विज्ञापन पर लगभग दस अरब डालर खर्च किए। स्पष्टतः इस विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर यह असर डालना है कि 'अ' कम्पनी का माल 'ब' कम्पनी के माल से अच्छा है। विज्ञापन में इसी प्रकार समान प्रकार के उत्पादनों में तुलना निहित है।

जब उद्योग पर एकाधिकार हो जाता है तो इस प्रकार की तुलना के लिए कोई अवसर नहीं रहता। फिर भी अमेरिका में अल्प संचार के कम से कम दो प्रमुख माध्यमों—रेडियो तथा टेलिविजन—की आय विज्ञापनों से ही होती है। अमेरिकी जनता रेडियो तथा टेलिविजन से मिलनेवाली सूचना एवं मनोरंजन के लिए प्रत्यक्ष पैसा नहीं देती लेकिन कालान्तर में इनके द्वारा विज्ञापित विभिन्न वस्तुओं को खरीदते समय उनके मूल्य में ही वह पैसा अदा हो जाता है। यहाँ अदायगी के तरीके की बात प्रमुख नहीं, विशेष बात यह है कि अमेरिकी कार्पोरेशने अपने माल के प्रसार के लिए विज्ञापन करना आवश्यक समझती हैं क्योंकि उन्हें अपने माल के लिए प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अन्यथा उनका व्यय एक बेहूदा बात होगी।

इसी प्रकार, उत्पादित वस्तुओं में सुधार पर खर्च करना व्यर्थ की बात होगी। फिर भी अमेरिकी फर्म अनुसन्धान एवं विकास कार्यों पर बहुत पैसा खर्च करती हैं और अमेरिकी बाजार को निरन्तर नया अथवा उन्नत किस्म का ऐसा माल मिलता रहता है जो वर्षों तक प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान कार्यों तथा उत्पादन की दिशा में प्रयत्नों का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के लगभग एक तिहाई कर्मचारी इस समय ऐसी चीजों के उत्पादन में व्यस्त हैं,

जिन्हे १९३६ में कम्पनी तैयार नहीं करती थी। कार्निंग ग्लास कम्पनी का अनुमान है कि १९५५ में उसकी दो तिहाई आय उन वस्तुओं से हुई जिनका विकास उन्होंने १९४० से किया था। इयूपोट कम्पनी की वार्षिक बिक्री का आधा भाग उन वस्तुओं का है जो पिछले २० सालों में ही उपयोग में आनी शुरू हुई है। इसी प्रकार जनरल फूड्स कार्पोरेशन ने १९५३ में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसकी बिक्री का १६ प्रतिशत भाग उन वस्तुओं का था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विकसित की गयी थी। ऐसा अनुमान है कि सभी अमेरिकी उद्योगों की इस समय होनेवाली कुल बिक्री में से पाँचवाँ हिस्सा ऐसी चीजों का है जो १५ वर्ष पूर्व नहीं थी।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में अगर गैर-एकाधिकार व्यवस्था के और उदाहरणों की आवश्यकता है तो इन्हे प्रस्तुत किया जा सकता है। अमेरिकी उद्योगों ने १९५५ तथा १९५६ में अपने कारखानों, मशीनों कार्यालयों तथा अन्य सुविधाओं के नवीकरण, विस्तार, तथा सुधार पर ७२ अरब डालर खर्च किए। १९५७ में यह अनुमानित व्यय ३६ अरब डालर था। न्यू इंग्लैंड में तुलना में छोटी 'नार्थ ईस्ट एअर लाइन्स' को नए प्रकार के यात्री वायुयानों पर १ करोड़, ७० लाख डालर खर्च करने थे। उत्तरी कैलिफोर्निया में कन्टेनर कार्पोरेशन 'लाक्हीड' तथा 'डग्लस एअर क्राफ्ट' में से प्रत्येक को अनुसन्धान एवं सुधार के कार्यों पर करोड़ों डालर खर्च करने थे। हर क्षेत्र में अमेरिकी फर्में 'परस्पर प्रतियोगिता द्वारा' अच्छी सेवा एवं अच्छे उत्पादन के लिए प्रयत्न में लगी हैं।

प्रतियोगिता के कुछ रूप

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का निकट से अध्ययन करने से कई प्रकार की प्रतियोगिताओं के होने का पता चलता है। सबसे पहला प्रकार तो वह है जिसे 'प्रत्यक्ष' प्रतियोगिता कहा जा सकता है। यह समान प्रकार का उत्पादन और सेवाओं वाले उद्योगों में होता है। अमेरिका में इस

समय ४,२५०,००० छोटे बड़े व्यापारिक घघे हैं, जिनमें चार करोड़ से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। अनेक एक ही जैसा व्यापार करते हैं और परस्पर प्रतियोगिता द्वारा अपने ग्राहको की संख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं। कुछ स्थानीय क्षेत्रों में प्रतियोगिता करते हैं और दूसरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर। ग्राहको को आकर्षित करने के लिए वे कम कीमतों का लालच दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर वे माल की श्रेष्ठता, अच्छी सेवा, उत्पादन को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने, प्रभावशाली विज्ञापन, विक्रय की श्रेष्ठ योग्यता तथा जनता में व्यापक मन्त्रों में विश्वास करते हैं।

अमेरिका की भाँति अत्यन्त सुसंगठित अर्थ-व्यवस्था में दो विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित रेफ्रिजरेटो की कीमतों में बहुत मामूली सा ही अन्तर हो सकता है। ग्राहक इसके बाद अब दोनों में से एक की ओर तभी आकर्षित होगा जब कुछ अतिरिक्त उपयोगी बातें उसे दिखाई पड़ेगी। जैसे कम्पनी का नाम, पैसा लगाने की अच्छी शर्तें या माल की श्रेष्ठता। यह एक नये प्रकार की प्रतियोगिता है, जो पुरानी मूल्य प्रतियोगिता से कोई मेल नहीं खाती। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को यह निश्चय हो गया है कि उन्हें निरन्तर उन्नत और विभिन्न किस्म का माल मिलता रहेगा।

एक दूसरे प्रकार की प्रतियोगिता होती है जो 'परोक्ष' प्रतियोगिता कहलाती है। यह समान उत्पादन अथवा सेवाएँ करनेवाली कम्पनियों में होती है। एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर के लिए विमान, बस, रेल या जहाज किसी से यात्रा कर सकता है। सामान ट्रको, रेलो या नदियों के रास्ते बड़ी नावों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया जा सकता है। एक ही प्रकार के व्यवसायवाली कम्पनियों में ग्राहको को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता होती है। इसमें उनकी सम्बन्धित कीमतों (किरायो) का अवश्य महत्वपूर्ण कार्य होता है लेकिन कार्य दक्षता, गति, सुरक्षा और विश्वस्तता का भी अत्यन्त महत्व होता है। 'परोक्ष' प्रतियोगिता का एक और उदाहरण अल्मूनियम में देखने में

आता है। अमेरिका में इस समय प्रारम्भिक अल्मूनियम उत्पादन करने वाली केवल तीन बड़ी कम्पनियाँ हैं। एक दम देखने से इन कम्पनियों की स्थिति एकाधिकारवाली जैसी लगती है। लेकिन वास्तव में उन्हें न केवल परस्पर प्रतियोगिता करनी होती है बल्कि इस्पात, सीसा, जस्त या प्लास्टिक की 'अप्रत्यक्ष' प्रतियोगिता से भी टक्कर लेनी होती है क्योंकि इन चीजों का और भी अनेक कामों में उतनी ही अच्छी तरह उपयोग हो सकता है। शायद ही ऐसा कोई उद्योग होगा जो 'अप्रत्यक्ष' प्रतियोगिता का मुकाबला किए बिना अपनी सेवाएँ या उत्पादन प्रदान करता हो।

बाजार में एक तीसरी चीज भी कार्य-रत है, जो बहुत अगो में प्रतियोगिता से मिलनी-जुलती है। इसे हम 'समतोलन कारणों की पारस्परिक क्रिया' कह सकते हैं। इन कारणों के प्रभाव को एक उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकेगा। मोटर बनानेवाले बड़े उद्योग बड़े-बड़े इस्पात विक्रेताओं के महत्त्वपूर्ण ग्राहक होते हैं। अगर इस्पात की कीमतें बढ़ती हैं या उसकी किस्म खराब होती है तो मोटर बनाने वाले उद्योग इस पर आपत्ति उठाएँगे और कीमतों तथा किस्म को उचित स्तर पर लाने की माँग करेंगे। अन्यथा वे उपभोक्ताओं को उन कीमतों पर कारों की सप्लाई नहीं कर सकते जो कीमतें वे देने को तैयार हैं। इस्पात-उत्पादकों को, जो मोटर कारखानों पर उनके प्रमुख ग्राहक होने के नाते निर्भर करते हैं, इन आपत्तियों पर गौर करना जरूरी है। मोटर कारखानों के दिवालियापन से इस्पात कार्पोरेशनों का हित नहीं होगा। एक प्रकार से इन बड़े कारखानों की भाँति उद्योग प्रतिदिन एक दूसरे की समस्याओं का सामना करते हुए एक-दूसरे की क्षमता में समतोलन स्थिति बनाए रखते हैं।

एक और उदाहरण खुदरा सामान की दुकानों का दिया जा सकता है। इसके प्रबन्धकों की मुख्य दिलचस्पी इसमें है कि ग्राहकों को उचित दामों पर अच्छी किस्म का माल मिले। अगर उन्हें माल सप्लाई करने

वाले स्वेच्छा से कीमतों में परिवर्तन कर लें तो निश्चय ही वे उसका विरोध करेंगे। अपने विरोध को वे उस भगडा करनेवाले उत्पादक का सामान बेचने के लिए लेने से इनकार करके और मजबूत कर सकते हैं। उनका यह कदम उस उत्पादक को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम यह है कि उपभोक्ता उचित मूल्य पर अच्छा माल खरीद सकता है।

प्रकृति का एक आधारभूत नियम यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसा जान पड़ता है कि अर्थ-व्यवस्था के एक भाग में प्रगति से दूसरे भाग में भी वैसा ही प्रयत्न होता है और अवरोध तथा समतोलन के कारण पैदा होते हैं।

उत्पादन को केन्द्रित करने का कारण कार्यक्षमता और अधिक उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन एक कार्पोरेशन या उद्योग की प्रगति का जिन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वे फौरन ही उस प्रभाव को बराबर करने के लिए अपनी शक्ति केन्द्रित कर लेते हैं। विशाल खरीदारों को विशाल विक्रेताओं का सामना करना पड़ता है, कच्चे माल का उत्पादनकर्ता तैयार माल के निर्माता का सामना करता है, उपभोक्ता दृष्टुओं का निर्माता खुदरा दुकानदारों और खुदरा दुकानदार उपभोक्ताओं का सामना करता है, बड़े खाद्यान्न व्यापारियों को अनेक वितरकों से सौदा करना पड़ता है, व्यापारिक फर्मों के प्रबन्धकों को मजदूर संघों से समझौता करना होता है, यहाँ तक कि सरकार भी प्रति-दिन उद्योग का ग्राहक या मालिक के रूप में सामना करती है।

अमेरिका जैसी मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में बड़े-बड़े उद्योगों में कभी-कभी वैसी प्रतियोगिता नहीं होती जैसी एक सिद्धान्तवादी चाहता है। वे अपने साधनों और शक्ति को केन्द्रित करना अधिक लाभदायक समझते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के व्यापारिक संगठन सामान्य व्यापार के लिए खतरनाक दिखाई देते हैं, अर्थात् वे उपभोक्ताओं को अपना बंदी ग्राहक बनाने का यत्न करते हैं, तो तुरन्त ही जनता के दबाव पर सरकार हस्तक्षेप कर उनके विरुद्ध कदम उठाएगी। इस प्रकार

समतोलन के लिए जनता की राय और एक शक्ति हो जाती है । एक लोकतन्त्री समाज में एकाधिकार विरोधी कानून इस प्रकार की समतोलन शक्ति का ठोस उदाहरण है । यद्यपि यह सदैव उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना कि बहुत से अमेरिकी चाहेंगे, फिर भी इसके कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पूर्ण एकाधिकार से मुक्त रही है ।

व्यापारिक फर्मों में भी मजदूरों को आकर्षित करने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए । अमेरिका में प्रत्येक मजदूर इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह एक नौकरी छोड़कर दूसरी अच्छी नौकरी कर ले । इसलिए एक उद्योग को अपने मजदूर को कम-से-कम उतनी मजदूरी देनी ही चाहिए जितनी उसे अन्यत्र मिल सकती है । अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था 'मजदूरों को वदी' बनाने के विचार की भी उतनी ही विरोधी है जितनी वह 'वदी उपभोक्ताओं' की धारणा के विरुद्ध है ।

अन्त में निजी उद्योग पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं । चूँकि लाखों व्यक्ति मुख्यतः कार्पोरेशनों का रिकार्ड देखकर ही पूंजी लगाते हैं, इसलिए प्रत्येक फर्म के लिए निरन्तर प्रगति दिखाना लाभदायक है ।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था बहुमुखी प्रतियोगिता पर आधारित है । अमेरिका में प्रतियोगिता सप्लाई और माँग की क्रिया द्वारा केवल मूल्य स्थिर करनेवाली शक्ति ही नहीं है अपितु अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ानेवाली एक प्रमुख शक्ति है ।

व्यापार की दुनिया

लोकतन्त्रीय अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण तथा सेवा का काम मुख्यतः निजी उद्योग ही करते हैं लेकिन इससे सरकार पर उद्योगों के विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं लग जाता। किसी योजना की विशालता या उसके महत्त्व के कारण अगर उसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना होता है तो वैसा किया जाता है।

फिर भी अमेरिका में आज चालीस लाख निजी उद्योग-धन्धे हैं। इनमें एक ओर जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कार्पोरेशन है तो दूसरी ओर किसी कोने में स्थित एक पंसारी की दुकान। १९५६ में इनका वार्षिक उत्पादन तीन खरब डालर आंका गया था।

कार्पोरेशन

अन्य विभिन्न व्यापारिक धन्धों में निर्माण व्यवसाय से सबसे अधिक आय होती है तथा इनमें ही सबसे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। १९५६ में हुई राष्ट्रीय आय में से ३० प्रतिशत से अधिक भाग इन्हीं निर्माण उद्योगों का था। एक शताब्दी पूर्व यह श्रेय कृषि को प्राप्त था। आज कुल राष्ट्रीय आय में उससे छः प्रतिशत से कुछ ही अधिक आय होती है। राष्ट्रीय आय का लगभग १८ प्रतिशत भाग खुदरा तथा थोक व्यापारों से आता है, जो वित्त निगमों, बीमा, जमीन जायदाद, खान तथा निर्माण कार्यों की संयुक्त आय से अधिक है।

अमेरिकी राष्ट्रीय आय का ५५ प्रतिशत से अधिक भाग लगभग ६००,००० 'कृत्रिम स्रोतों' से उपलब्ध होता है। ये स्रोत अदृश्य, अस्पृश्य तथा केवल कानून की भीड़ना के अन्तर्गत ही विद्यमान हैं जैसा कि

सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रधान न्यायाधीश जान मार्शल ने कहा था। ये 'कार्पोरेशन' बड़े-बड़े ऐसे विशाल उद्योगों से लेकर, जिनमें हजारों हिस्सेदार तथा कर्मचारी होते हैं तथा अरबों डालर की सम्पत्ति होती है, थोड़े से कर्मचारियों वाले छोटे उद्योग-धन्धों तक होते हैं। कार्पोरेशनों के ये 'कृत्रिम स्रोत' आज की अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं।

कार्पोरेशन एक ऐसा सघ होता है जो व्यक्तियों द्वारा कानून की विशेष धाराओं के अन्तर्गत विशेष उद्देश्यों को लेकर सगठित किया जाता है। इस प्रकार जनरल मोटर्स कार्पोरेशन लगभग ६००,००० हिस्सेदारों का ऐसा सघ है जो डेलावेयर राज्य के कानूनों के मातहत मोटर उद्योग तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए सगठित किया गया है।

कार्पोरेशन एक कानूनी इकाई समझी जाती है, वह उन व्यक्तियों से भिन्न होती है जो उसके मालिक होने ह तथा उसका संचालन करते हैं। इसलिए कार्पोरेशन का कोई भी हिस्सेदार बिना अन्य हिस्सेदारों या कार्पोरेशन की स्वीकृति के ही अपना हिस्सा दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है। उदाहरणतः, अगर जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के डार्ड लाख हिस्सेदारों में से वह एक हिस्सेदार है तो वह किसी दलाल को यह सूचना देकर कि वह अपना हिस्सा बेचना चाहता है, अपने शेयर बेचकर पैसा वापस प्राप्त कर सकता है।

इस सुविधा के कारण, कि एक हिस्सेदार आसानी के साथ अपने कार्पोरेशन के शेयर बेच सकता है, लोगों को ऐसे व्यवसायों में पूंजी लगाने के लिए प्रेरणा मिलती है।

एक बार शेयर जारी हो जाने के बाद, व्यक्तिगत हिस्सेदार की मृत्यु या दुर्भाग्य का अथवा कम्पनी के शेयरों की खरीदोफरोख्त का उस कम्पनी के अस्तित्व पर सीधा असर नहीं पड़ता। पुनः बेचने का एकमात्र परिणाम यह होता है कि नए हिस्सेदारों को वोट देने का अधिकार तथा डिविडेंड (लाभांश) की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती है जो इससे पूर्व पहले के हिस्सेदार को प्राप्त थी।

चूँकि शेयरो के स्थानान्तरण का कार्पोरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, अतः उसे एक स्थाई आर्थिक संगठन समझा जाता है। अलबत्ता एक कार्पोरेशन अपने आपको उस हालत में भग कर सकता है जब उसके अधिकार-पत्र की अवधि समाप्त हो जाए या हिस्सेदार उसे समाप्त करना तथा पूँजी बेबाक करना चाहे या फिर कम्पनी फेल हो जाए।

नियमतः कार्पोरेशनों का प्रबन्ध मालिक हिस्सेदारों द्वारा सीधा नहीं किया जाता। व्यावहारिक उद्देश्य से स्वामित्व तथा प्रबन्ध का काम अलग-अलग हाथों में होता है हालांकि कार्पोरेशन प्रबन्धकों के अपनी फर्मों में बहुत से हिस्से होते हैं।

स्वामित्व को प्रबन्ध कार्य से अलग रखने का एक विशेष लाभ यह होता है कि प्रबन्धकों की मुख्य दिलचस्पी फर्म की निरन्तर उन्नति में रही आती है, केवल तुरन्त लाभ कमाने की ओर नहीं। हिस्सेदार यह चाहेंगे कि उन्हें लाभांश (डिविडेण्ड) अधिक और शीघ्र मिले, लेकिन फिर भी प्रबन्धक यह निर्णय कर सकते हैं कि फर्म की दीर्घकालीन उन्नति के विचार से माल को कम मुनाफा लेकर नीची कीमतों पर बेचने में हित है। वे इसी ख्याल से शुद्ध लाभ में से बड़ी राशि को फर्म के नवीकरण तथा विस्तार के लिए 'पुनः व्यवसाय में लगाने' का भी निर्णय कर सकते हैं।

हिस्सेदार डायरेक्टरों का एक बोर्ड (संचालक मण्डल) चुनते हैं। यह एक प्रकार की व्यवस्थापक समिति होती है जो नीति सम्बन्धी निर्णय करती है। डायरेक्टर प्रमुख नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार के अतिरिक्त और भी कामों की देख-रेख करते हैं, वे प्रबन्धकों के कार्य-कलापों की निगरानी और उन पर नियन्त्रण भी रखते हैं। साथ-ही-साथ उद्योग की प्रगति तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए करोड़ों डालरों की योजनाओं से लेकर कार्यालय के स्वागत-कक्ष की दीवार पर रोगन सम्बन्धी साधारण मामलों पर भी विचार करते हैं।

उनके निर्णयों को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने का दायित्व

एक नए प्रकार के व्यावसायिक हाथों में सौंपा जाता है जिन्हें व्यापार-प्रबन्धक कहते हैं। फर्म को चलाने और नीति को क्रियान्वित करने का वास्तविक काम यही व्यापार-प्रबन्धक करता है। एक उच्च व्यापार-प्रबन्धक का जीवन प्रायः अत्यन्त थका देनेवाला तथा मरण का सा लगता है। लेकिन फिर भी इन पदों के कारण जो भौतिक समृद्धि, प्रतिष्ठा अधिकार एवं सम्मान प्राप्त होता है उसे देखते हुए अनेक अमेरिकी इस भारी उत्तरदायित्व के प्रति भी आकर्षित होते हैं। इन कठोर परिश्रमी व्यक्तियों ने अमेरिका के औद्योगिक विकास में बहुत योग दिया है और ऐसा उन्होंने हमेशा स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं किया।

जिस प्रकार नीति सम्बन्धी निर्णय नियुक्त अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, हिस्सेदारों द्वारा नहीं, उसी प्रकार कार्पोरेशन की जो सम्पत्ति होती है, जैसे मकान, मशीनें तथा धन, उसकी मालिक कार्पोरेशन होती है, हिस्सेदार उसके मालिक नहीं होते।

इसी प्रकार ऋणों के सम्बन्ध में करार कार्पोरेशन द्वारा किए जाते हैं, हिस्सेदारों द्वारा नहीं। कार्पोरेशन सम्पत्ति की मालिक होती है तथा ऋण लेती है। बिना चुकते ऋणों के लिए व्यक्तिगत हिस्सेदार उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए किसी कार्पोरेशन को ऋण देनेवाले अपने पैसे की अदायगी के लिए किसी व्यक्तिगत हिस्सेदार से नहीं कह सकते।

उदाहरण के तौर पर हम यह मान ले कि श्री जोन्स ने, जो एक मकान के मालिक है तथा फर्स्ट ट्रस्ट बैंक में जिनका बचत खाता (सेविंग्स खाता) है, टिटन कार्पोरेशन के १०० शेयर पाँच डालर प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। अगर टिटन कार्पोरेशन का दिवाला निकल जाय और उस पर कई हजार डालर का ऋण बाकी रह गया है, तो कार्पोरेशन को ऋण देनेवाले श्री जोन्स के घर या बचत खाते की रकम को जब्त नहीं कर लेंगे। श्री जोन्स की हानि कुल ५०० डालरों तक सीमित रहेगी जो उन्होंने १०० शेयरों के मूल्य के रूप में दिए थे।

इस प्रकार के सीमित दायित्व से व्यक्तिगत पूंजी-नियोजको को बहुत सरक्षण मिलता है। और इसलिए कार्पोरेशन व्यक्तिगत पूंजी को आकर्षित करने के लिए बड़ी अच्छी स्थिति में है।

जन-पूंजीवाद

अमेरिका के औद्योगिक विकास में व्यापक पूंजी नियोजन कार्य अनिवार्य रहा है। इसके परिणामस्वरूप जनता का जीवन निर्वाह का स्तर ऊँचा उठा है। व्यापक पूंजी नियोजन के लिए भी कार्पोरेशन पद्धति ने जितना योग दिया है उतना और किसी ने नहीं।

व्यापक खपत की भाँति व्यापक पूंजी नियोजन का काम भी अधिकांश मध्यम आय के परिवारों द्वारा ही किया जा सकता है। दरिद्री पूंजी नहीं लगा सकते। उनकी तो सम्पूर्ण आय की जो थोड़ी ही होती है, खाना मकान व अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरत रहती है।

अमेरिका में इन मध्यम आयवाले परिवारों के विकास ने साथ ही साथ व्यापक पूंजी नियोजन भी पैदा कर दिए हैं। इन परिवारों को अपनी बचत की पूंजी लगाने के लिए कार्पोरेशन मिल गई हैं।

व्यापक पूंजी नियोजन के विकास के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। एक तो यह कि अधिकांश लोगों के पास इतना पैसा अवश्य होना चाहिए कि वे अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर सकें और उसके बाद कुछ पूंजी बचा सकें। दूसरे लोगों में फालतू पैसे को यूँ ही उड़ाने खाने की बजाय या जमीन में गाड़ने की बजाय बचाने की इच्छा होनी चाहिए।

धन बचाने और नियोजन की इच्छा बहुत कुछ व्यावहारिक आकर्षणों पर निर्भर करती है, जैसी पूंजी के सुरक्षित रहने के साथ-साथ भौतिक लाभों की आशा। पूंजी नियोजन के लिए भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो सेविंग्स खाता खोलता है अपने धन पर ब्याज की आशा करता है, और साथ-ही-साथ 'संकट काल' के लिए बचत भी

करता है। एक बीमा करनेवाला अप्रत्याशित सकट से अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, एक हिस्सेदार डिविडेण्ड (लाभांश) की आशा करता है, सरकारी या कम्पनियों के बौंडो के मालिक पूर्ण घोषित ब्याज की आशा करते हैं। अन्य पूँजी नियोजकों का मुख्य उद्देश्य उन कम्पनियों की दीर्घकालीन उन्नति हो सकती है जिनमें वे पूँजी लगाते हैं। एक प्राइवेट सस्था, ब्रुकिंग इस्टीमेट में अनुसंधान करनेवालों के अनुसार पूँजी लगानेवाली अधिकांश जनता इस आशा से सीक्युरिटियाँ खरीदती है कि कालान्तर में उनकी बाजार में कीमत बढ़ जाएगी।

अमेरिका में मध्यम आय के परिवारों की संख्या बहुत हो गई है और इसके साथ-साथ इन परिवारों के लिए पूँजी नियोजन के अनेक आकर्षण भी पैदा हो गए हैं। इसका परिणाम यह है कि आज अमेरिका में प्रायः सभी स्तर के व्यक्ति धन बचाते हैं और उसका नियोजन करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कार्पोरेशनों के शेयरों व बौंडो के मालिक ८६ लाख परिवारों में से ५६ प्रतिशत, मध्यम आय के परिवारों में से हैं। उनकी वार्षिक आय ४००० डालर से १० हजार डालर तक है। शेयरों तथा बौंडो के व्यक्तिगत मालिकों की कुल संख्या में अधिकांशतः कारीगर, अर्द्ध कारीगर, क्लर्क तथा घरेलू स्त्रियाँ आदि हैं। इनकी संख्या ५१.५ प्रतिशत है।

११ करोड़ ३० लाख से अधिक अमेरिकियों ने किसी न किसी प्रकार का अपना बीमा कराया हुआ है। ३ करोड़ से अधिक परिवारों के बचत खाते हैं जबकि २ करोड़ १० लाख परिवारों के पास सरकारी बौंड तथा सीक्युरिटियाँ हैं।

सीक्युरिटी तथा एक्सचेंज कमीशन के (विनिमय आयोग) अनुमान के अनुसार १९५६ में बचत खातों में अमेरिकी जनता के ३७ अरब डालर जमा थे, ८८.८ अरब डालर की पूँजी सभी प्रकार के सरकारी बौंडों में लगी हुई थी, १०६.६ अरब डालर निजी बीमा व्यवसाय में लगे थे, तथा ३३५ अरब डालर की पूँजी कार्पोरेशनों के शेयरों तथा बौंडो

मे लगी थी। नीचे इन आंकड़ों की प्रतिशत के हिसाब से सक्षिप्त तालिका दी जा रही है।

पूँजी नियोजन का स्वरूप	एक या अधिक स्वामियों वाली कुल पारिवारिक इकाइयाँ प्रतिशत में
जीवन बीमा	८२.३ प्रतिशत
बचत खाते	५२.८ "
अमेरिकी (ई) बौड	४१.६ "
वार्षिक वेतन व पेशे	२०.६ "
सार्वजनिक शेयर	१४.० "
व्यक्तिगत शेयर	४.६ "
सम्पत्ति रहन तथा बौड	२.७ "
कार्पोरेशनों के बौड	१.३ "

कुल मिलाकर अमेरिका में ६०.७ प्रतिशत परिवारों ने किसी न किसी रूप में अपनी पूँजी लगाई हुई है। 'जन-पूँजीवाद' का शायद यही सार है।

पूँजी नियोजन के नए तरीकों में एक नया तरीका परस्पर पूँजी नियोजन कोष है। यह तरीका उन देशों के लिए विशेष रुचि का है जहाँ पूँजी नियोजन के लिए अत्यन्त विकसित व्यवस्था तथा सीधे पूँजी नियोजन की दृढ़ परम्परा नहीं है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका में इस प्रकार के कोषों की तेजी से वृद्धि हुई है। 'पारस्परिक पूँजी नियोजन कोष' के अन्तर्गत व्यवस्था इस प्रकार होती है कि यह कोष भिन्न-भिन्न कार्पोरेशनों के शेयर खरीद लेता है तथा फिर अपने शेयर जारी कर देता है। अब अगले कोई व्यक्ति इस कोष के शेयर को

खरीदता है तो वह एक तरह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पूंजी विभिन्न उद्योगों में लगा देता है। इस प्रकार उसकी पूंजी अनेक उद्योगों में लग जाती है तथा उसका खतरा कम हो जाता है।

दिसम्बर १९४० में अमेरिका में ऐसे कोपो के २९६,००० शेयर होल्डर थे। सितम्बर १९५६ में यह सख्या बढ़कर २,४०२,००० हो गई। इसके साथ-साथ प्रति हिस्सेदार की औसत पूंजी १,५१३ डालर से बढ़कर १,५४० डालर हो गई। नवम्बर १९५६ में १३५ पारस्परिक पूंजी नियोजन कोपो की कुल पूंजी लगभग ९ अरब डालर थी।

इन कोषों की वृद्धि के जबरदस्त कारण हैं। व्यक्तिगत पूंजी नियोजकों, विशेषकर थोड़ा पैसा लगानेवालों को, प्रायः इस बात का अनुभव और विशेष ज्ञान नहीं होता कि किन कम्पनियों में बचन की पूंजी लगाई जाय। लेकिन उक्त कोष के डायरेक्टरों में ये दोनों ही बातें होती हैं। पूंजी लगाना ही उनका व्यवसाय है। इस प्रकार वे पूंजी नियोजकों की गम्भीर गलतियों से रक्षा करने के साथ-साथ उनका पैसा प्रगतिशील उद्योगों में लगा सकते हैं।

पूंजी नियोजन के नए उत्साहवर्द्धक तरीकों और मध्यम आयवालों की उन्नति से अनेक देशों को व्यापक पूंजी नियोजन का क्षेत्र तैयार करने तथा जन पूंजीवाद लाने में सहायता मिलेगी जैसा अमेरिका में पाया जाता है।

९० प्रतिशत से अधिक जनता का अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में पैसा लगा होने के साथ अमेरिकियों के लिए उनके जन पूंजीवाद का विशेष सामाजिक महत्त्व है। इससे उन्हें अपने राष्ट्र तथा उसकी अर्थ-व्यवस्था की रक्षा के लिए और उन्नत तथा विस्तारवादी अर्थ-व्यवस्था के लिए सीधा तथा व्यक्तिगत कारण मिल जाता है।

‘वाल स्ट्रीट एकाधिकार’ जैसे नारे केवल उन लोगों के लिए ही हैं जो या तो अज्ञानी हैं, या जिनको वास्तविकता की जानकारी नहीं है। करोड़ों अमेरिकी पूंजी नियोजकों के सामने धनी से धनी व्यक्ति भी

लाचार है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था इन बहुसंख्यको पर ही आश्रित है। अमेरिकी जनता वास्तव में अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की मालिक है।

अनुसंधान तथा विकास

एक वास्तविक प्रतियोगितावादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापार के प्रबन्ध के लिए अदक्षता, अव्यय अवरोध तथा तानाशाही की प्रवृत्ति घातक हैं। अमेरिकी निजी उद्योगपति इस तथ्य को भली प्रकार समझते हैं। नई उत्पादित वस्तुओं तथा उपायों की खोज का काम अब केवल आविष्कारक का ही नहीं रह गया है। इस उत्तरदायित्व को अब उद्योग अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ पूरा करते हैं। इसे वे आर्थिक अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग मानते हैं। पिछले १५ वर्षों में विशेष रूप से यह विचारधारा पनपी है। औद्योगिक प्रयोगशाला बड़े पैमाने पर काम करती हैं, उन्हें 'प्रगति का मार्ग प्रशस्त' करना ही चाहिए। आधुनिक अमेरिका के निर्माण में वैज्ञानिक खोजों का उतना ही हाथ है जितना और किसी चीज का। प्रयोगशालाओं में परीक्षण करनेवाले व्यक्तियों को निरन्तर नए उत्पादनों व सामानों की बाढ़ लाने, सम्पूर्ण रूप में उद्योगों के विकास तथा नए रोजगारों के लिए व्यापक अवसर प्रदान करने का श्रेय है।

आर्थिक प्रगति तथा स्थायित्व के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्ता तथा यथार्थता द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् मालूम पड़ी जब फौजी सामान बनाने के लिए दिए गये बड़े-बड़े आर्डरों को रद्द कर देने से प्रतिरक्षा उद्योगों पर असर पड़ा और दूसरी ओर उपभोक्ता उद्योग के सामने जनता की दबी हुई माँगों को पूरा करने की समस्या आ गई। वैज्ञानिक खोज ने दोनों ही समस्याएँ हल कर दी। इससे अमेरिकी उद्योगों को नए क्षेत्रों में काम करने में सहायता मिली, जिससे लाखों अमेरिकियों को नई नौकरियाँ मिली, इसने नए माल तथा उत्पादन तरीकों का विकास किया जिससे उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई माँग को

शीघ्र सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा सका । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ प्रेक्षकों द्वारा जो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि युद्ध के पश्चात् भारी गिरावट आएगी वह सच नहीं हुई ।

नई उत्पादित वस्तुओं तथा तरीकों के विकास के लिए सच्चे प्रयत्नों पर भारी खर्च की आवश्यकता पड़ती है । मैकग्रा-हिल द्वारा प्रकाशित 'व्यापार का नौवा वार्षिक पर्यवेक्षण' पुस्तिका के अनुसार अकेले १९५६ में अनुसंधान तथा विकास के कार्यों पर पाँच अरब डालर से अधिक खर्च किए गये । अनुमान है १९५७ में इस मद में ६३ अरब डालर व्यय हुए । यह खर्च चार हजार औद्योगिक प्रयोगशालाओं में काम करने वाले लगभग २००,००० वैज्ञानिकों पर हुआ । समस्त अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर लगभग दो तिहाई खर्च निजी उद्योगों द्वारा किया जाता है तथा शेष राशि का अधिकांश भाग सरकार से प्राप्त होता है ।

उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर बहुत बल दिया जाता है । कुल मिलाकर १५,००० में अधिक कम्पनियाँ बड़ी वैज्ञानिक योजनाओं में सलग्न हैं, इसमें विशुद्ध खोज सम्बन्धी कार्य भी शामिल है । १९५० से लेकर अब तक अमेरिकी उद्योगों ने अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर इतना व्यय किया है कि पिछले १७० वर्षों में भी इतना नहीं किया गया ।

अणु शक्ति, विमान निर्माण, प्रेक्षपणास्त्र, रसायन, कपड़ा, सकलन, बिजली तथा पेट्रोल उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । डेक्रेन या नाइलोन से लेकर रेडियो सक्रिय आइसोटोप तक बिलकुल नए प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन इसे बात का प्रमाण है कि अमेरिकी व्यापारियों ने अनुसंधान तथा विकास कार्यों में कितनी सफलता प्राप्त की है ।

व्यापार और शिक्षा

उद्योगों में आजकल प्रबन्धकों के पद पर अत्यन्त शिक्षित व्यक्ति

रखे जाते हैं। मैनेजर बननेवाले सभी व्यक्तियों के लिए कालेज की डिग्री 'आवश्यक' शर्त है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय का 'ग्रेजुएट स्कूल आव बिजनेस', हार्वर्ड का 'स्कूल आव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' तथा पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय का 'हार्टन स्कूल आव फाइनेन्स एण्ड कामर्स' इस बात के ज्वलत उदाहरण हैं कि उद्योगों की जटिलता तथा प्रतियोगितावादी अर्थ-व्यवस्था में प्रतिभा और ज्ञान की आवश्यकता के कारण शिक्षा में कितना विकास हुआ है।

भावी व्यापार प्रबन्धकों की शिक्षा केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है। हार्वर्ड के 'स्कूल आव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' ने यह अनुभव करके कि व्यापार के अन्तर्गत केवल बाजारों की स्थिति या उनके रूप को समझने का ही काम नहीं रह गया है, बल्कि उसके अतिरिक्त और भी बातों को जानने की जरूरत है, १९४५ से अपना पाठ्यक्रम बदला और भावी व्यापार प्रबन्धकों को वित्त, व्यापार तथा हिसाब-किताब की शिक्षा के अतिरिक्त विश्व की सामयिक समस्याओं तथा स्थिति का भी ज्ञान कराना प्रारम्भ किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने अब इस व्यापक पाठ्यक्रम को अपना लिया है।

शिक्षित व्यक्तियों की महत्ता को समझने के बाद व्यापारियों ने उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं को निरन्तर आर्थिक सहायता दी है। अनुमान है कि अकेले १९५६ के वर्ष में निजी अमेरिकी उद्योगों ने १० करोड़ डालर कालिजों तथा विश्वविद्यालयों को दिए। उच्च शिक्षा के लिए व्यापारियों का आर्थिक योग १९५० से दुगुने से अधिक हो गया है। व्यक्तिगत व्यापारियों या घनिक परिवारों द्वारा स्थापित संस्थाएँ शिक्षा के प्रसार कार्य में और सहायता करती हैं। १९५६ में एक संस्था 'फोर्ड फाउंडेशन' ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को ६० करोड़ २० लाख डालरों का अनुदान दिया।

स्वतंत्र व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था में विज्ञापन

१९५६ में अमेरिकी व्यापारियों ने ४५ हजार व्यक्तियों को १०

अरब डालर खर्च करने का भार सौपा। उन्हें इस बात की छूट दी गयी कि वे इस धन को जिस प्रकार चाहे खर्च करे। उनसे जो अपेक्षा की गयी थी वह केवल यह थी कि वे इन व्यापारियों के उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं के लिए अधिक ग्राहक बनायें।

ये ४५ हजार व्यक्ति विज्ञापन एजेंसियों के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अमेरिकी उद्योग तथा कृषि उत्पादनों के प्रसार का भार उठाया है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक लाभों के बिना ही ये समझदार व्यापार प्रबन्धक इन एजेंसियों को हर साल बड़ी राशियाँ दे देते हों। फिर भी विज्ञापन उद्योग की कभी-कभी कटु आलोचना होती है। उस पर आरोप लगाया जाता है कि वह जनता को भूटे सुनहले सपने दिखाकर अधिक पैसे खर्च कराता है और उसे भौतिकतावादी बनाता है। विज्ञापन आन्दोलनों को अगर अनैतिक नहीं तो प्रायः बेहूदा तथा रस-विहीन कहकर आलोचना की जाती है।

यह सत्य है कि अमेरिकी विज्ञापनकर्ता कभी-कभी भौतिक भावनाओं को उभारते हैं और उनके आन्दोलन सांस्कृतिक स्तर से नीचे होते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञापन एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगों के माल का बाजार बढ़ाना है, देश के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाना नहीं। सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने का काम शिक्षा व धर्म का है। वैसे जैसे-जैसे लोगों का यह स्तर ऊँचा उठता जाए विज्ञापनों का स्तर भी उसी प्रकार ऊँचा उठना चाहिए। सस्ते विज्ञापनों का जनता केवल मजाक बनाती है और क्योंकि वे प्रभावहीन होते हैं, उस माल की खपत नहीं होती। पिछले कुछ सालों में विज्ञापनों का स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में निश्चित रूप से कदम उठाए गए हैं।

अमेरिकी विज्ञापनों का तीव्र आलोचक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि और कोई भी तरीका जनता की मांगों को इतने व्यापक रूप से नहीं बढ़ाता। विज्ञापन उद्योग नए माल का प्रचार कर

देता है और बाजार में अच्छी मांग पैदा कर प्राविधिक प्रगति को आगे बढ़ाता है।

विज्ञापन केवल प्रतियोगिता से संयोगवश उत्पन्न हुई वस्तु नहीं है, यह स्वयं प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त अधिक और अच्छी वस्तुओं की लालसा उत्पन्न करने के कारण यह व्यापक उत्पादन का एक प्रमुख कारण है। इसके समर्थकों का कहना है कि व्यापक उत्पादन को प्रोत्साहन देकर विज्ञापन उद्योग माल की किस्म में सुधार तथा कीमतों को कम रखने में योग देता है। यदि जनता का वह दबाव, जो विकसित उच्च विज्ञापन द्वारा व्यक्त होता है, न हो तो 'किचन मिक्सर' जैसी चीज जो आज ६ पौंड वजन की है और जिसका मूल्य कुल १६ डालर है, क्रमशः १५० पौंड का तथा १२८ डालर की कीमत का हो रहा। यह भी कहा जाता है कि अगर विज्ञापन न हो तो प्रचलित ६२६ पत्रिकाओं, १२०० दैनिक समाचार-पत्रों, ६००० साप्ताहिकों, २,६४७ रेडियो स्टेशनों तथा ४६५ टेलीविजन स्टेशनों का, जो ३ करोड़ ८० लाख घरो की सेवा करते हैं, अस्तित्व ही प्रायः लुप्त हो जाय।

अगर कोई माल विज्ञापन के अनुरूप नहीं उतरता तो जनता उसे खरीदने से इनकार कर देगी। कोई भी विज्ञापनकर्ता जनता की इस बड़ी शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ईमानदारी के साथ विज्ञापन कोई असामान्य बात नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अमेरिकी उपभोक्ता विज्ञापनों पर उन्हें ठीक माल बताने वाला समझ विश्वास करने लगे हैं। वे विज्ञापनकर्ताओं से यह आशा करते हैं कि अनुसंधान के परिणामस्वरूप उत्पादित नई वस्तुओं को वे जनता के सामने लायेंगे।

संक्षेप में ऐसी त्रुटियों के रहते हुए भी, जो टाली नहीं जा सकतीं, विज्ञापन उद्योग अमेरिका में माँग बढ़ाने तथा व्यापक उत्पादन के लिए वातावरण बनाने में एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रवृत्ति और उद्देश्य

प्रतियोगितावादी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों की आवश्यकता के कारण व्यापार में ऊँची जगहे उन लोगों के लिए हो गई है जो भागी उत्तरदायित्व को उठाने में समर्थ हैं। हर साल व्यापारियों के प्रतिनिधि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रतिभाशाली स्नातकों के लिए पूछताछ करते हैं। मामूली-सा कारोबार प्रारम्भ करके आज व्यक्ति व्यापार के शिखर पर पहुँच गए हैं, उनके मार्ग में किसी प्रकार की कठोर वर्ग या पारिवारिक बाधाएँ नहीं थी। ऐसे व्यक्तियों के नामों से, जिन्होंने मामूली सा व्यापार प्रारम्भ किया और व्यापारिक क्षेत्र में विश्वास तथा नेतृत्व के ऊँचे शिखर पर पहुँच गए, एक बड़ा ग्रन्थ बन जाएगा। शिखर तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, अनेक व्यक्ति लुढ़क जाते हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि अथवा राष्ट्रीयता के कारण कोई असफल नहीं होता।

प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों की निरन्तर खोज व्यापारी सद्भावना पैदा करने के लिए नहीं करते अपितु अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में यह अत्यन्त आवश्यक है। जो उद्योग प्रतिभा की उपेक्षा करते हैं उन्हें भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनके मुकाबले के दूसरे उद्योग प्रगति कर जाते हैं। अमेरिकी जैसी प्रतियोगितावादी अर्थ-व्यवस्था में पक्षपात, कट्टरता तथा अदक्षता को कोई स्थान नहीं है।

यह सवाल प्रायः पूछा जाता है कि अमेरिकी उद्योगों का वास्तव में कौन नियंत्रण करता है ? यह सत्य है कि कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन पर शक्तिशाली व्यक्तिगत धनिक व्यापारियों का नियंत्रण है। यह भी सच है कि एक छोटे पूँजी नियोजक का उस उद्योग की प्रतिदिन या दीर्घकालीन नीतियों पर कोई भी सीधा नियंत्रण नहीं होता जिसके शेयर उसके पास हैं। लेकिन यह एकदम पड़नेवाला प्रभाव कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ शक्तिशाली व्यापारी वाल स्ट्रीट के अपने कार्यालयों से

नियंत्रण करते हैं, छलपूर्ण है। निकट से देखने पर पता चलता है कि स्थिति सर्वथा भिन्न है।

एक छोटे पूंजी नियोजक के लिए एक बड़ी व्यापारिक फर्म के नित्य के कार्यों तथा नीतियों पर सीधा नियंत्रण कर सकना व्यावहारिक कारणों से असंभव है। न तो उसके पास विस्तृत जानकारी होती है और न आवश्यक अनुभव। इन कामों को करने के लिए अत्यन्त प्रशिक्षित व्यक्ति अत्यन्त ऊँचे वेतनों पर नियुक्त किए जाते हैं। अगर हर पूंजी नियोजक अपनी इच्छा के अनुसार कम्पनी के कामों में दखल देने लगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर भी एक पूंजी नियोजक इन कुटिल अर्थ-व्यवसायियों के हाथ का कोई निर्बल प्यादा नहीं होता। लाख व्यक्तिगत पूंजी नियोजक अन्ततः प्रभावशाली नियंत्रण करते हैं। एक उद्योग के शेयरों को खरीदने में या उनसे छुटकारा पाने में वे हर रोज प्रबन्धकों में विश्वास अथवा अविश्वास का मत व्यक्त करते हैं। यह वास्तव में पर्याप्त नियंत्रण है। किसी भी एक व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि वह एक कार्पोरेशन में उसकी आवश्यकता के अनुसार पूंजी लगा दे। कार्पोरेशन को अपने लिए आवश्यक पूंजी के निमित्त जनता के व्यापक नियोजन पर निर्भर रहना चाहिए। अगर किसी उद्योग के रिकार्ड में कुप्रबन्ध, अदक्षता, अस्थिर प्रगति या निरन्तर विकास के अभाव का उल्लेख होता है तो जनता तथा पूंजी लगाने वाली संस्थाएँ उस उद्योग में पूंजी लगाने के पहले अच्छी तरह विचार कर लेंगी। इस वास्तविक नियंत्रण की कोई भी व्यापार प्रबन्धक उपेक्षा नहीं कर सकता।

निजी उद्योग के पीछे मूल प्रवृत्ति मुनाफा कमाने की होती है और जब तक व्यक्ति अपना निजी व्यापार करता है तब तक वह अपने लिए नफा कमाने के प्रयत्न में लगा रहता है। लेकिन बड़ी-बड़ी कार्पोरेशनों में मुनाफा की यह प्रवृत्ति कैसे काम करती है जहाँ बड़े पैमाने पर अमेरिकी उत्पादन तथा वितरण होता है।

इन कार्पोरेशनों के मालिक व्यापक और लाखों व्ययित होते हैं जो देश के सभी भागों में बसे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फर्मों में प्रबन्धकों का कोई शेयर न हो या फिर थोड़ी सख्या में हो। तब प्रबन्धक किसके लिए मुनाफा कमाने का प्रयत्न करते हैं? नाममात्र में वे मालिकों के लिए मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यह केवल एक प्रवृत्ति है, जो अधिक प्रबल नहीं है। अधिकांश अमेरिकी व्यापार प्रबन्धक यह मानते हैं कि वे केवल हिस्सेदारों के प्रति ही उत्तरदायी नहीं हैं अपितु कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है। वे तीनों वर्गों के विरोधी रुखों में संतुलन रखने का प्रयत्न करते हैं। कालान्तर में सुव्यवस्थित उद्योग हिस्सेदारों के लिए लाभ कमाते हैं, कर्मचारियों को अच्छा वेतन तथा नौकरी की स्थिरता प्रदान करते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए सस्ते दामों पर बढ़िया माल बनाते हैं। व्यापार प्रबन्धकों को इन तीनों वर्गों का आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना होता है क्योंकि वे इन तीनों की सद्भावना तथा सहयोग पर निर्भर करते हैं। फिर भी प्रतिदिन वे कारोबार में तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों में प्रबन्धकों का मुख्य ध्यान अपने उद्योग की आय तथा उसके विकास से संबंधित होता है। उनकी नौकरी, उनका जीवन इसकी सफलता या असफलता पर निर्भर करता है।

कार्पोरेशन में विभिन्न विभागों के प्रबन्धकों के बीच प्रतियोगिता तथा स्पर्धा रहती है। उत्पादन विभाग का वाइस प्रेजिडेंट इंजीनियरिंग विकास के लिए अधिक धन की माँग कर सकता है, विक्रय विभाग टेलीविजन पर प्रचार कर माल की खपत बढ़ाने के लिए विज्ञापन का बजट बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकता है, अनुसंधान विभाग का प्रधान और उन्नत सामान के लिए कह सकता है, इत्यादि। सचालक-मंडल से अपनी अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें अपने कामों का परिणाम दिखाना पड़ेगा, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की है तथा भविष्य में उनकी क्या योजना है? एक विभाग की सफलता या

विफलता का अर्थ उस विभाग के प्रधान की व्यक्तिगत सफलता या विफलता है।

×

×

×

अधिकांश अमेरिकी व्यापारियों का एक नैतिक स्तर होता है और वे उसके अनुसार कार्य करते हैं। वैसे अमेरिका में कुछ बातों पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि वे सारे समाज के लिए हानिकारक हैं। बहुत सी गुप्त समझौतों के जरिए अलग कर दी गई हैं। कई व्यापारों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस की नहीं जाती, जैसा कि एक बार एक व्यापार प्रबन्धक ने मुझे बताया। व्यापार प्रबन्धक एक लम्बी अवधि में मुनाफे में नियमित, धीरे-धीरे तथा स्थिर वृद्धि के लिए प्रयास करता है। वह ऐसी ऊँची छलांगें लगाने की कोशिश नहीं करता जो कायम न रखी जा सकें और कालान्तर में हानिकारक सिद्ध हों।

स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था में लुटेरी प्रवृत्तियों का जनता द्वारा विरोध निश्चित है जिससे अस्वस्थकर प्रवृत्तियों पर रोक के लिए कानून बनाए जाने की संभावना रहती है। ऐसा होता रहा है और भविष्य में भी तब तक होता रहेगा जब तक स्वतंत्रता रहेगी।

संगठित मजदूर

मानवीय कारबार में व्यवस्था या तो कानून की बाध्यता के कारण स्थापित होती है या फिर उन परस्पर सघर्षात्मक शक्तियों के कारण जो अन्ततः सामान्य समझौता करवाती हैं। एकाधिकारवादी औद्योगिक व्यवस्था में प्रायः समस्त आर्थिक सम्बन्धों का एक राजनैतिक प्रवर के आदेशों पर कठोरता के साथ नियमन किया जाता है। इसकी तुलना में लोकतंत्री व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रेरणा तथा समतोलन शक्तियों को कार्य के लिए पूरा अवसर मिलता है। अमेरिका में इन शक्तियों में से एक शक्ति श्रमिक-आन्दोलन है।

मजदूर यूनियनों के प्रमुख उद्देश्य

अमेरिकी मजदूर यूनियनों का मुख्य कार्य अपने सदस्यों और देश के उपभोक्ताओं को राष्ट्र के उत्पादन का अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त कराना है। मजदूर उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त क्रय-शक्ति प्राप्त करके ये यूनियन सरकार के सहयोग से व्यापक खपत का बाजार बनाए रखने में सफल होती हैं।

अमेरिकी मजदूर यूनियनों की गतिविधियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। समस्त श्रमजीवी अमेरिकियों में से एक चौथाई से अधिक इनमें शामिल है। संसार के अन्य भागों में राजनैतिक दृष्टिकोण से चलने वाले श्रम-आन्दोलनों की तुलना में अमेरिकी मजदूर यूनियनों ने केवल एक बड़े उद्देश्य पर अपनी शक्ति केन्द्रित की है : वर्तमान स्वतन्त्र व्यवसाय की व्यवस्था के अन्तर्गत अपने-सदस्यों के लिए ऊँची मजदूरी तथा काम करने की अच्छी अवस्थाएँ प्राप्त करना। वे साम्प्रतिक व्यवस्था को

बदले बिना ही अधिक हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश करती रही है । परिणामतः आज अमेरिकी मजदूर के जीवन यापन का स्तर संसार में सबसे ऊँचा है ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिकी मजदूर यूनियनों ने उचित कानूनी व्यवस्था के लिए जोर दिया है लेकिन प्रबन्धकों के साथ सीधी बातचीत पर उन्होंने और भी अधिक भरोसा किया है । अपनी माँग पूरी कराने के लिए सामूहिक वार्ता द्वारा सम्झौता व वार्ता उनका एक प्रमुख तरीका बन गया है ।

पिछले बीस वर्षों में अमेरिकी मजदूरों की शक्ति बहुत बढ़ी है । ऐसे बहुत से आदमी हैं जो यह समझते हैं कि कुछ यूनियन नेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । इस बात के प्रमाण दिए गए हैं कि कुछ यूनियनों में अपराधी तत्व घुस गए हैं । वे केवल सदस्यता तक सीमित नहीं अपितु उनके नेतृत्व पर भी कब्जा कर बैठे हैं । फिर भी, जनता की आवाज पर श्रमिक आन्दोलन स्वयं इन अवांछनीय तत्वों को दूर करने के लिए लोकतन्त्री तरीको पर चल रहा है ।

अमेरिका में श्रमिक आन्दोलन का विकास

अमेरिकी मजदूर आन्दोलन को आज जितनी शक्ति प्राप्त है उतनी पहले कभी नहीं थी । यह सच है कि अमेरिका के औपनिवेशिक जीवन काल में एक प्रकार के कुछ मजदूर संगठन थे । लेकिन गृह-युद्ध के पश्चात् ही उद्योगों का विस्तार होने पर अमेरिकी मजदूरों ने राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए प्रयत्न किया । इस दिशा में पहला उल्लेखनीय कदम १८६९ में उठाया गया जब 'नाइट्स आव लेबर' (श्रम-सरदार) की स्थापना हुई । 'नाइट्स' ने विभिन्न मजदूर यूनियनों को इकट्ठा कर एक संघ बनाया । इसकी स्थापना के पीछे राजनैतिक उद्देश्य था तथा इस पर मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रभाव था । मजदूरों के लिए काम करने की शर्तों में सुधार की माँगें पूरी करवाने के लिए 'नाइट्स' ने अपने संघर्ष

की चरम सीमा के समय हिंसात्मक कार्यों से पूर्ण हड़ताले करवाई । १८८६ में 'अमेरिकन फ़ैडरेशन आव लेबर' (अमेरिकी मजदूर संघ) की स्थापना के बाद उक्त संघ का प्रभाव कम हो गया । अमेरिकी मजदूर संघ ने 'नाइट्स' मजदूर-संघ से विपरीत नीति अपनाई । उसने राजनीति में हस्तक्षेप का विरोध किया तथा मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही श्रम समस्याओं को सुलझाने के कार्य को अच्छा समझा ।

पहले की मजदूर यूनियनों का काम आसान नहीं था । बातचीत के लिए अपने सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त कराने के लिए उन्हें मालिकों के बड़े विरोध, मजदूरों की उपेक्षा तथा जनता के अविश्वास का सामना करना पड़ा । प्रथम विश्वयुद्ध तक मजदूर यूनियनों की सदस्यता धीरे-धीरे तथा अनियमित रूप से बढ़ी । युद्धकालीन आवश्यकताओं के कारण मजदूरों को लाभ पहुँचा । सरकारी अधिकारियों ने मजदूर नेताओं को श्रमिकों के प्रवक्ता के रूप में मान्यता प्रदान की । इससे मजदूर यूनियनों की प्रतिष्ठा बढ़ी और १९२० तक मजदूर संघों की सदस्य संख्या ५० लाख तक हो गई ।

लेकिन बाद में १९२०-२६ की अवधि में इन मजदूर यूनियनों का प्रभाव गिरा और सदस्य संख्या ३५ लाख तक रह गई । अनेक मालिकों ने यूनियनवाद के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया । उन्होंने यूनियन में शामिल होनेवाले मजदूरों को न केवल नौकरी से निकाल दिया अपितु उनके नाम भी 'काली सूची' में दर्ज कर लिए अर्थात् उनके नाम दूसरे मालिकों को सूचित कर दिए गए और उन्होंने ऐसे आदमियों को काम देने से इनकार कर दिया ।

हिंसात्मक हड़तालों से भरपूर लम्बे संघर्ष ने अन्ततः अमेरिकी जनता को यह भली भाँति समझा दिया कि एक रचनात्मक श्रम-नीति निश्चित करना सबसे अधिक आवश्यक काम है । इस दिशा में १९२६ में पहला कदम उठाया गया जब रेलवे मजदूर कानून बना । इसके द्वारा रेलवे

मजदूर यूनियनो को सामूहिक रूप से संगठन और वार्ता का अधिकार दिया गया। उसके अनुसार मध्यस्थो की भी नियुक्ति की गई जो रेलवे मजदूरो तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले श्रम—विवादों को सुलझा कर समझौता कराते थे।

एक और उल्लेखनीय कदम नारिस ला र्वारडिया कानून १९३२ था जिसके अनुसार श्रम-विवादों में अदालती आदेशों के प्रयोग सीमित कर दिए गए तथा मालिकों द्वारा की जानेवाली वह कार्रवाई गैरकानूनी करार दी गई जिसके द्वारा वे किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखने से पूर्व इस समझौते पर हस्ताक्षर करा लेते थे कि वह कर्मचारी किसी मजदूर यूनियन में शामिल नहीं होगा। १९३३ के नेशनल इण्डस्ट्रियल रिकवरी एक्ट (राष्ट्रीय औद्योगिक उत्थान कानून) तथा १९३५ के 'नेशनल लेबर रिलेशन्स एक्ट (राष्ट्रीय मजदूर सम्बन्ध कानून) ने तो निर्विवाद रूप से यह पुष्ट कर दिया कि कर्मचारियों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए 'सामूहिक रूप से अपने आपको संगठित करने तथा वार्ता करने' का अधिकार है। १९३५ के कानून ने जो वैगनर कानून के नाम से जाना जाता था—मजदूर यूनियनों तथा व्यापार प्रबन्धकों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता व सौदेबाजी को संघीय नीति का उद्देश्य बनाया। इसने मालिकों की कुछ अनुचित कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला और उन्हें गैरकानूनी करार दिया। इसने कानून के पालन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय मजदूर सम्बन्ध बोर्ड की भी स्थापना की।

इस प्रकार कानून के प्रश्रय के कारण मजदूर यूनियनों की सदस्य संख्या १९३५ की ३५ लाख से बढ़कर १९४० में ६० लाख हो गई। एक बार फिर लोकतन्त्री व्यवस्था ने उन तरीकों तथा शक्तों को दूर करने के लिए आवश्यक साधन प्रदान किए जिन्हें अधिकांश अमेरिकी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हानिकर समझते थे।

अनेक मालिकों ने मजदूर यूनियनों के तेजी से होनेवाले संगठनों का विरोध किया। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया अधिक से अधिक

मजदूर यूनियनों को मान्यता मिलती गई। व्यापार करनेवाली नई पीढ़ी इस व्यवस्था की कार्य-पद्धति तथा संगठित मजदूरों के महत्व को अधिक अच्छी तरह समझती है।

अमेरिकी मजदूर संघ (ए० एफ० एल०) इस प्रकार की यूनियनों का संगठन या जो कार्य के अनुसार बनी थी, जैसे—बढई, ईटें बनाने वाले, नलों की मरम्मत करने वाले आदि—१९३०-३६ के मध्य में उद्योगों के निरन्तर विकास के साथ, औद्योगिक मजदूरों के संगठन के सम्बन्ध में मतभेद पैदा हुआ। अमेरिकी मजदूर संघ चाहता था कि औद्योगिक मजदूर भी पहले से ही स्थापित इस संघ में शामिल हो जाएँ। दूसरी ओर बहुतों का यह कहना था कि मजदूर यूनियनों का संगठन उद्योगों के अनुसार किया जाय, जैसे एक यूनियन मोटर कारखाने की हो, एक इस्पात कारखाने के मजदूरों की और इसी तरह की दूसरी यूनियनें हो। परिणामतः अमेरिकी मजदूर संघ से कुछ यूनियनें अलग हो गईं और औद्योगिक संगठनों की कांग्रेस की स्थापना हुई। अगले बीस वर्षों में दोनों ही संघों (यूनियनों) की सदस्य संख्या और शक्ति में वृद्धि हुई। अन्त में १९५५ में ये दोनों मजदूर संघ भी आपस में मिल गए और एक विशाल संगठन की स्थापना हुई जिसकी सदस्य संख्या एक करोड़ साठ लाख से अधिक थी।

दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान में मजदूरों की कमी तथा श्रमिक आन्दोलन को सरकारी समर्थन मिलने से मजदूर संगठन की शक्ति और बढ़ी। तभी उद्योगों में हड़तालें हुईं जब कि राष्ट्रीय उत्थान के लिए औद्योगिक प्रगति को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। इनमें से कुछ विवाद मजदूर यूनियनों के बीच अधिकार सम्बन्धी झगड़ों के कारण पैदा हुए। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होने पर अमेरिकी कांग्रेस ने १९४७ में टाफ्ट-हार्टले कानून पास किया। इसके द्वारा वैगनर कानून में संशोधन कर मजदूर यूनियनों की शक्ति पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगा दिए गए। इस कानून की अनेक बार उसे अनुद्धार कहकर आलोचना की गई

लेकिन हाल के वर्षों में टाफ्ट-हार्टले कानून से मजदूर यूनियनों के इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं पड़ी कि वे अपने लिए लाभदायक समझौते कराने में सफल हों। निस्संदेह युद्धोपरान्त काल में मजदूरों के लिए जो लाभ प्राप्त किए गए वे पहले के लाभो से कहीं अधिक थे।

इस समय अमेरिकी मजदूर संघ और औद्योगिक सगठन कांग्रेस के नेता जोर-शोर से अपने दल की 'सफाई' में लगे हैं। वे अपराधी तथा स्वार्थी तत्त्वों को आन्दोलन से निकाल देना चाहते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि संगठित मजदूरों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि श्रम आन्दोलनो में अपने आपको न केवल बाहरी नियन्त्रण से अपितु अन्दरूनी श्रष्टाचार से भी स्वतन्त्र रखने की कितनी योग्यता है।

श्रमिकों द्वारा संतुलन

हम इस बात पर बल दे चुके हैं कि अमेरिकी व्यवस्था के अन्तर्गत सगठित मजदूर यूनियन का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए अधिक आय प्राप्त कराना है। लेकिन मजदूरों के लिए अधिक क्रय-शक्ति प्राप्त कराने के साथ-साथ मजदूर यूनियनों व्यापक खपत बाजार को भी बनाए रखने में सहयोग देकर व्यवस्था को संतुलन रखने में सहायता देती हैं।

अगर एक व्यापारी मुनाफे के अपने मूल उद्देश्यों को दीर्घकालीन प्रगति के विचार से संयमित करता है तो मजदूरों के लिए 'अधिक आय' के अपने प्रमुख लक्ष्य पर मजदूर यूनियन भी इस ख्याल से अंकुश लगाती हैं कि वेतनों में अधिक वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति की स्थिति हो सकती है जिससे सारा लाभ ही समाप्त हो जाएगा। फिर भी न तो व्यापार के प्रबन्धक और न मजदूर नेता ही सन्त हैं, दोनों ही कभी-कभी ऐसे काम कर बैठते हैं जो राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं।

मजदूर नेता जब अधिक वेतन की मांग पर जोर देते हैं तब वे व्यापारी वर्ग के विरोध और जन-भावना से संघर्ष करते हैं। कई विवाद जब बहुत उग्र रूप धारण कर लेते हैं तब वे सरकारी हस्तक्षेप की स्थिति

पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार की संभावना यूनियन नेताओं के ह्वा में कुछ नरमी लाती है जो वैसे सामान्य हित की उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी मजदूर नेताओं ने अनेक बार यह दिखा दिया है कि उनमें न केवल अपनी यूनियनों के प्रति उत्तरदायित्व की जबरदस्त भावना है अपितु राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी वे अच्छी तरह समझते हैं। यह तथ्य कि झूठे और स्वार्थी मजदूर नेता भी प्रसिद्धि पा सकते हैं, केवल यही सिद्ध करना है कि यह एक असामान्य बात है, नियम नहीं।

अपने सदस्यों के लिए नकद आय में वृद्धि कराने के साथ-साथ मजदूर यूनियनों ने ऐसे सामाजिक कानूनों के निर्माण पर भी बल दिया है जिनके द्वारा एक मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटों की सीमा, सुरक्षा नियम आदि कार्यों की व्यवस्था की गयी है। इस तथ्य को समझते हुए कि मजदूर संघों के सदस्यों के हित वाकी समाज के साथ सबद्ध हैं। मजदूर यूनियनों ने स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भी सामाजिक कल्याण के कार्यों का समर्थन किया है।

न तो मजदूर यूनियन और न उसके सदस्यों ने ही कोई संयुक्त राजनैतिक मोर्चा बनाया है। सभी प्रकार के राजनैतिक आन्दोलनों में विभिन्न यूनियनों अलग-अलग उम्मीदवारों का समर्थन करती पाई जा सकती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भी अधिक मतभेदपूर्ण हो सकता है। लेकिन प्रायः सभी मजदूर उन उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जिनकी मजदूर यूनियनों के प्रति 'सहानुभूति' होती है। फिर भी अगर कोई मजदूर यूनियन किसी उम्मीदवार को राजनैतिक समर्थन प्रदान करती है तो इससे उसका चुनाव जीतना निश्चित नहीं हो जाता। मजदूर यूनियन के सदस्य केवल यूनियन की सदस्यता से ही सबद्ध नहीं, वे माँ-बाप, कर-दाता, धर्म-कर्म करने वाले, खेलों के प्रति उत्साही तथा क्लबों के सदस्य भी हैं। और एक चुनाव में ये दूसरी 'बाते' यूनियन की

सदस्यता की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है।

अधिक वेतन तथा अन्य लाभों के लिए माँग प्रायः कार्यकुशलता तथा आर्थिक प्रगति के लिए प्रेरणादायक होती है। व्यापारी लोग इसे उचित नहीं समझते कि मजदूरों की मजदूरी कम करके उत्पादन-व्यय कम किया जाय। मजदूर यूनियनों की देखरेख में ऐसा कर सकना लगभग असंभव है। इस प्रकार यह रास्ता बन्द होने पर, व्यापारी उत्पादन-व्यय कम करने के लिए नए और अच्छे उपाय खोजते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में मजदूर राष्ट्रीय आय का अधिक भाग लेकर अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार व्यापारिक तथा मजदूरों के उद्देश्यों के संयोजन एवं समतोलन से अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारियों का उद्देश्य यह है कि मुनाफा अधिक हो और मजदूरों का यह कि उन्हें मजदूरी अधिक मिले। प्रबन्धक प्रायः ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों पर अधिक व्यय का भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाय। लेकिन इस प्रकार की धोखाधड़ी की भी एक सीमा होती है क्योंकि इससे फर्म के माल की व्यापार में खपत होनी बन्द हो जाएगी।

मजदूर यूनियनों के सभी कार्यों से उत्पादन तथा कार्यक्षमता को बढ़ावा नहीं मिलता। मजदूर रखने और उन्हें बरखास्त करने पर यूनियनों का नियंत्रण होने, वरिष्ठता के क्रम के अनुसार तरक्की, उत्पादन पर सीधा प्रतिबन्ध (उदाहरणतः यह प्रतिबन्ध कि एक ईंटें बनाने वाला एक स्थान पर एक दिन में निश्चित संख्या में ही ईंटें तैयार करेगा) और पहली मजदूर यूनियनों द्वारा किये गए यांत्रिक प्रगति के विरोध के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन यांत्रिक प्रगति और विशेषकर स्वयंचालित मशीनों के प्रति आजकल के मजदूर नेताओं का रुख अत्यन्त सराहनीय है।

आज अमेरिकी मजदूर नेताओं की बड़ी समस्या यह है कि किस प्रकार मजदूरों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाए बिना यांत्रिक

प्रगति को आगे बढ़ाया जाय। नियमित और स्थिर आय पर बल देकर मजदूर यूनियनों उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति की रक्षा कर रही हैं और उद्योग अनुसंधान कार्यों द्वारा गोजगार के नए अवसर ढूँढने में लगे हैं। व्यापक खपत बाजार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देकर मजदूर यूनियने अमेरिकी आर्थिक ढाँचे का एक दृढ़ आधार बन गयी हैं।

मजदूर यूनियन की प्रवृत्तियाँ

केवल वेतन में वृद्धि समृद्धि की गारंटी नहीं है। व्यवहार में वेतनों में वृद्धि का अर्थ है मुद्रा का अधिक प्रचलन। इसके साथ अगर माल की सप्लाई न बढ़ायी जाय तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है अर्थात् बाजार में 'माल' तो कम होता है और उसकी खरीद के लिए पैसा 'बहुत'।

इस प्रकार वेतनों में वृद्धि के साथ उत्पादन न बढ़ने का परिणाम मूल्यों में वृद्धि या मजदूरों की छटनी हो सकता है। मजदूरों की माँग होने से श्रद्धा एक उद्योग अपने माल का विक्रय मूल्य बढ़ाने को बाध्य हो सकता है। नियमित कीमतों में वृद्धि होने पर कुछ चीजों को छोड़कर बाकियों की विक्री कम हो जाती है। माल की विक्री कम होने से उत्पादन भी गिरता है और इसका परिणाम मजदूरों को काम से हटाना होता है। कालान्तर में ये मजदूर उन उद्योगों में काम पा जाते हैं जिनके माल की माँग बढ़ रही होती है। लेकिन उस दौरान में अनेक परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है।

अगर एक बड़े उद्योग में वेतन वृद्धि के साथ अन्य उद्योगों में भी उसी प्रकार वेतन वृद्धि होती है तो उत्पादन में गिरावट तथा बेकारी का खतरा टल सकता है, क्योंकि सभी की आय बढ़ने से चीजों की माँग बढ़ेगी और उससे उत्पादन बढ़ेगा। फिर भी वेतन वृद्धि के साथ जब उचित रूप से उत्पादन नहीं बढ़ता तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, इससे मजदूरों को ही लाभ की बजाय हानि हो सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में मजदूर नेताओं ने अपना ध्यान दूसरे लाभ प्राप्त करने की दिशा में लगाया है। ये लाभ सवेतन छुट्टी, मुनाफे में हिस्सेदारी की योजना, मनोरंजन की सुविधाएँ, स्वास्थ्य एवं अस्पतालों की सुविधा संबंधी हैं। लेकिन यह स्थिति इतनी गिरी हुई नहीं है। १९५६ तक मजदूर संघ पेंशनों तथा कल्याण कोषों की राशि २५ अरब डालर तक हो गयी थी। १९५७ में ८ अरब डालर की राशि और जुड़ने की आशा थी, जो पेंशन योजनाओं तथा जीवन बीमा कार्यक्रमों, बीमारी की तनख्वाहों, तथा अस्पताल व चिकित्सा सबधी लाभों के लिए बराबर रूप से विभाजित थी। अधिकांश उद्योगों की योजनाओं में तीन चौथाई धन मालिक और एक चौथाई कर्मचारी देते हैं। इन योजनाओं से साढ़े सात करोड़ से अधिक व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं, जिनमें मजदूरों के परिवार तथा उन पर निर्भर प्राणी शामिल हैं।

इस प्रकार के पेंशन व कल्याण कोष इतने दृढ़ हो गए हैं और अच्छे समझे जा रहे हैं कि पूंजी नियोजन के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जा रहा है। मजदूर यूनियनों, प्रबन्धकों तथा जनता द्वारा ध्यान से निर्वाचित ट्रस्टियों की देखरेख में इन कोषों से उद्योगों को नवीकरण और अच्छे व्यवसाय में धन लगाकर कार्य-विस्तार में सहायता मिलती है। नियमित रूप से सीक्युरिटियाँ खरीदकर वे स्थायित्व में भी अपना योग देते हैं।

हाल के कुछ वर्षों में बहुत सी यूनियनों ने नौकरी की 'गारन्टी' अथवा आय की सुरक्षा की 'गारन्टी' को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया है। १९५५ में 'यूनाइटेड आटोमोबाइल' (संयुक्त मोटर कर्मचारी संघ) के मजदूरों को इस उद्देश्य में आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई और उन्हें 'वार्षिक वेतन की गारन्टी' की सुविधा मिली। इस योजना के अन्तर्गत मोटर निर्माता अपने मजदूरों को इस बात की गारन्टी देते हैं कि जब भी उन्हें काम से अलग रखा जाएगा, साल के किसी भी समय में उनके द्वारा अर्जित आय का ६५ प्रतिशत भाग दिया जाएगा। उद्योग

में इस प्रकार के 'छुट्टी' के दिन प्रायः आते रहते हैं, जबकि कारखाने में नए माडल की कारें तैयार करने के लिए दूसरी मशीनें लगानी पड़ती हैं। लेकिन चूँकि ऐसी अवधि कुछ सप्ताहों से अधिक की नहीं होती मोटर कारखानों के मजदूर अब इस बात से आश्वस्त हैं कि उन्हें सारे साल उचित आय होती रहेगी। कुछ मजदूर यूनियनने जीवन निर्वाह व्यय के सूचक अंक के आधार पर वेतन संबंधी करार करती हैं, इस सूचक अंक में वृद्धि होने या गिरावट होने से वेतनों में भी उसी के अनुसार वृद्धि या गिरावट होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को मुद्रास्फीति पैदा करने वाली बताकर उसकी आलोचना की गयी है।

वार्षिक वेतन की गारंटी, पेंशन कोष, सामान्यतः ऊँची मजदूरी पूँजीवाद के अन्तर्गत 'श्रम-मूल्य' के मार्क्स सिद्धान्त से मेल नहीं खाते। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था में ये बातें सार्थक हैं, जहाँ व्यापक उत्पादन के लिए व्यापक श्रम शक्ति अनिवार्य है।

अन्य देशों की मजदूर यूनियनों की भाँति अमेरिकी मजदूर यूनियनने हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं करती। अमेरिका में हड़ताल आर्थिक कारणों को लेकर होती है जबकि यूनियन तथा प्रबन्धकों के बीच वार्ता द्वारा कोई ऐसा हल नहीं निकल पाता जो दोनों को स्वीकार हो। लेकिन सामूहिक वार्ता भंग होने का उदाहरण कम ही मिलेगा। अमेरिका में हर साल एक लाख से अधिक श्रम करारों पर हस्ताक्षर होते हैं। इनमें से ६६ प्रतिशत शांतिपूर्ण वार्ता के परिणामस्वरूप किए गए होते हैं।

इस प्रकार अमेरिकी मजदूर यूनियनों अर्थ-व्यवस्था की अविभाज्य अंग हैं और अर्थ-व्यवस्था को सतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योग देती हैं। कानून के संरक्षण में उन्होंने शक्ति तथा धन दोनों की प्राप्ति की है, जिसका वे, कुछ बातों को छोड़, प्रायः सदुपयोग करती हैं। वे राजनीतिक गुटबन्दी में न फँसकर आर्थिक समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं। काम की शर्तें तय करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप

पर निर्भर रहने की अपेक्षा वे सामूहिक रूप से स्वतंत्र वार्ता को अधिक अच्छा समझती है। निजी कर्मचारियों की तकलीफों को दुकानों के प्रशिक्षित 'कारिन्दे' उन करारों के नियमों के अनुसार दूर करते हैं जो फर्म के साथ किये जाते हैं। हड़ताल एक राजनैतिक हथियार नहीं है, जिसका प्रायः और खुलकर प्रयोग होता हो, अपितु हड़ताल तभी की जाती है जब सामूहिक रूप से वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है और पच भी फैसला करने में असफल होते हैं।

विशेषकर पिछले बीस वर्षों में मजदूरों तथा प्रबन्धकों का एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बहुत बदला है। मालिकों की कुछ ही दशाब्दियों पूर्व की यह इच्छा कि 'यूनियन किसी प्रकार नष्ट कर दी जाएँ' तथा मजदूरों का मालिकों को 'मानवों का निर्दयी शोषक' कहकर पुकारना अब अतीत की बातें हो चुकी हैं। पुरानी उक्तियाँ कभी-कभी सुनाई पड़ सकती हैं लेकिन अब उनमें वह कटुता नहीं जो पहले थी। बातचीत के दौरान में क्रुद्ध होकर जो इन पुरानी बातों को कहते थे अब उनमें विश्वास नहीं करते। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था 'पूँजीपतियों के शोषण' के समय से अब बहुत आगे निकल आयी है और जनता भी आर्थिक सिद्धान्तों को काफी समझने लगी है।

स्थायित्व की खोज

यह अब सिद्ध हो चुका है कि एक सफल अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन न केवल 'अधिकता' से होना चाहिए अपितु 'निरन्तर स्थिरता' के साथ होते रहना चाहिए। फिर भी दोनों बातें हमेशा एक साथ नहीं होती। प्रचुरता और प्रगति की स्थिति की अपेक्षा गरीबी और निश्चलता की स्थिति में स्थायित्व प्राप्त करना अधिक आसान है। प्रारम्भिक अर्थ-व्यवस्था शताब्दियों में भी थोड़ी बदल पाती है और उसके सामने जबर-दस्त आर्थिक उथल-पुथल की समस्याएँ नहीं आती। जिन्दगी का प्रवाह धीरे-धीरे चलता रहता है। लेकिन अत्यधिक विकसित और तेजी से बढ़नेवाली अर्थ-व्यवस्थाओं में यह समस्या सामने रहती है कि बिना किसी प्रकार की गंभीर आर्थिक उथल-पुथल के और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाए बिना किस प्रकार समृद्धि तथा प्रगति को बनाए रखा जा सकता है।

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व

आर्थिक अस्थिरताओं के कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को पहले बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। १९३१-३९ की अवधि की भीषण मन्दी का चित्र सामने है। उस वक्त को याद करके बहुत से व्यक्ति यह सवाल करते हैं कि क्या अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था बिना किसी प्रकार की गंभीर आर्थिक उथल-पुथल के प्रचुर रूप से और निरन्तर उत्पादन करती रह सकती है।

इसका अन्तिम उत्तर शायद कभी भी न दिया जा सके। लेकिन इसी प्रकार के अन्य सवालों के निश्चित और दृढ़ उत्तर के लिए उन

कार्वाइयों का अध्ययन करना चाहिए जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए और उसे आर्थिक आघातों से बचाने के लिए पिछले २५ वर्षों में की गई है ।

अमेरिकी सरकार का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि समृद्धि की स्थिति में वह अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर आर्थिक उथल-पुथल से बचाए तथा उसकी रक्षा करे ।

आर्थिक प्रगति प्रायः नए विचारों के क्रियान्वित होने तथा नए आर्थिक अवसरों के निकलने के परिणामस्वरूप होती है । लेकिन श्रेष्ठ खोजों, जैसे बिजली का उपयोग, प्लास्टिक का विकास, अणु-विकरण, आदि का कोई निश्चित समय नहीं होता । वे कभी भी हो सकती हैं । अतः उनके कारण जो प्रगति होती है उसमें एक स्थिर प्रवाह संभव नहीं ।

और न एक राष्ट्र को उत्पादन तथा खपत को कठोर संतुलन में रखा जा सकता है । प्रगति और आर्थिक विकास के दौरान में साधारण परिवर्तनों का होना सामान्य बात है । हाँ, भीषण मन्दी अथवा अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति न तो सामान्य है, और न आवश्यक । इन स्थितियों के कारण स्वतन्त्र व्यापक उत्पादनवाली अर्थ-व्यवस्था का सामान्य काम-काज अस्त-व्यस्त हो जाता है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् कम-से-कम दो बार ऐसा समय आया जब मामूली-सी गिरावट गम्भीर मन्दी का रूप ले सकती थी लेकिन सरकार के आर्थिक कदमों के कारण ऐसा नहीं हो सका । बहुत से अर्थ-शास्त्रियों का विश्वास है कि अदृष्ट संकटों को छोड़कर, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में अब स्थायित्व के मूल तत्त्व विद्यमान हैं । फिर भी हमें मानवीयकारण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि स्वतन्त्रता के आधार पर बनी अर्थ-व्यवस्था की सफलता या विफलता मनुष्य की विचारशक्ति की क्षमता पर निर्भर करनी है ।

आर्थिक अस्थिरता के कारण

अब हम संक्षेप में उन कारणों पर विचार करेंगे जिनके कारण एक

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता आती है। अर्थ-व्यवस्था के संचालन कार्य को सरल भाषा में हम यों व्यक्त कर सकते हैं कि अर्थ-व्यवस्था धन का एक प्रवाह है जिसके अन्दर मनुष्यों को उनके काम के लिए पैसा दिया जाता है और उससे वे अपनी इच्छित वस्तुएँ खरीदते हैं। उत्पादन तथा वितरण के स्थानों पर श्रम का भी एक निरन्तर प्रवाह बना रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादित वस्तुएँ तथा सेवाएँ वापस जनता को उपलब्ध हो सकती हैं। दैनिक जीवन में भी एक किसान अपनी सहायता के लिए मूल्य चुकाता है, फैक्टरी का मैनेजर मैकेनिक को पैसा देता है, विमान सर्विस वायुयान के चालक को पैसा देती है, कार्पोरेशन बौद्धो पर व्याज देती है और इसी प्रकार यह चक्र चलता जाता है। अपनी सेवाओं के बदले लोगों को जो धन मिलता है, वे उसे आगे विभिन्न कामों में खर्च करते हैं। खाने के लिए पसारी को, गैस के लिए गैस कम्पनी को, चिकित्सा के लिए डाक्टर को, स्वच्छता तथा पुलिस की सुरक्षा के लिए नगर प्रशासन को और डाक, सड़क तथा जेट लड़ाका विमानों तक के लिए वे सघीय सरकार को पैसा चुकाते हैं।

इस प्रकार दो धाराएँ निरन्तर दो विरोधी दिशाओं में बह रही हैं। एक धारा सामान तथा सेवाओं की है, जो उपभोक्ताओं की इच्छित वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए लोगों के प्रयासों के 'पुल' का काम करती है। दूसरी धारा धन के प्रवाह की है, लोगों को उनके काम के बदले जो धन मिलता है उसे वे सामान खरीदने तथा सेवाएँ प्राप्त करने में दूसरों को दे देते हैं। अगर दोनों ही धाराएँ समान रूप से स्थिर और ऊँचे स्तर पर बहती रहे तो अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व रहेगा तथा स्थिति सतोषजनक रहेगी। आर्थिक परिवर्तन साधारण होंगे तथा वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों में अथवा व्यवसाय और आय में उतार-चढ़ाव विशेष नहीं होंगे।

लेकिन इन दोनों ही धाराओं को संतुलन में रखने के लिए कई समस्याएँ बीच में आती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की सप्लाई में सदा

परिवर्तन होता रहता है। कुछ चीजें किसी खास मौसम में ही बिकती हैं फिर भी उनका उत्पादन सारे साल होता रहता है। नया माल बाजार में आता है जिसका दूसरे उद्योगों के उत्पादन व व्यवसाय पर असर पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों के कारण माल के उत्पादन तथा वितरण में अन्तर पड़ता है। सैन्य आवश्यकताओं के कारण श्रम तथा सामान को शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में लगाना पड़ता है। बाढ़, सूखा या हड़तालों के कारण इन दोनों ही धाराओं के शान्त प्रवाह में गड़बड़ पैदा हो जाती है।

परिवर्तन के ये कारण प्रायः सभी आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में एक जैसे हैं। लेकिन स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तनों का एक अतिरिक्त कारण है। चुनाव की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। एक उपभोक्ता को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह जो वस्तु चाहे खरीद सकता है और जितनी मात्रा में खरीदना चाहे अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार खरीद सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबन्धकों को सुविधाओं के विस्तार, नए किस्म के माल का उत्पादन, नई मशीनें लगाने या कम्पनी के मुनाफे को पुनः व्यवसाय में लगाने की बजाय हिस्सेदारों को अधिक लाभांश वितरित करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इस प्रकार के लाखों व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक रूप से इन दोनों ही स्थितियों (धाराओं) में भारी परिवर्तन कर सकते हैं जिसका असर अन्ततः आय तथा व्यवसाय के स्तर पर पड़ता है।

एकाधिकारवादी औद्योगिक राष्ट्र में आर्थिक चुनाव की स्वतन्त्रता नहीं होती। सब निर्णय एक ऐसे राजनीतिक प्रवर द्वारा किए जाते हैं जिसका राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रहता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसमें स्वतन्त्रता के हनन का तरीका प्रमुख है। वास्तव में यह ऐसे समाज का एक और उदाहरण है कि जहाँ व्यक्ति को एक सर्वसत्ताधारी राज्य की इच्छा का दास बनना पड़ता है।

इसके विपरीत एक लोकतन्त्री समाज में इस बात को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है कि व्यक्तिगत चुनाव की स्वतन्त्रता बनी रहे।

सरकार का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध के बिना ही स्थायित्व प्राप्त किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिकी जनता ने सरकार को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः धन की मात्रा और प्रवाह को नियमित करना है।

स्थायित्व की सुरक्षा के साधन

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में धन की वास्तविक मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है : धन की मात्रा (अर्थात् प्रचलन में कितने डालर हैं) तथा धन के प्रचलन की गति अर्थात् धन एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में कितनी तेजी से जाता है।

अगर धन के प्रवाह को माल और सेवाओं की सप्लाई के साथ सतुलन में रखना है तो या तो डालरों (धन) की कुल मात्रा पर या मुद्रा के चलन की गति पर या दोनों पर नियन्त्रण रखना होगा।

अमेरिका में लोग जिस हिसाब से अपना धन व्यय करते हैं उस पर उस कानून का प्रभाव रहता है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के मध्यम आय के परिवारों के व्यापक विकास का समर्थन है जिनमें खपत की अधिक प्रवृत्ति है। यह प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है तथा सरकार व्यक्तियों के निर्णयों पर नियन्त्रण नहीं करती। लेकिन सरकार को ऐसे कई अधिकार प्राप्त हैं जिनके द्वारा वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा की 'सप्लाई' नियमित कर सकती है।

१९४६ के रोजगारी कानून के अन्तर्गत अमेरिकी सरकार आर्थिक स्थायित्व की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस कानून का सार यह है कि सरकार स्वतन्त्र औद्योगिक प्रतियोगिता की व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग, श्रम तथा कृषि को अधिकतम रोजगार तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने और भारी मन्दी तथा मूल्यों में घातक घट-बढ़ को रोकने में सहयोग देगी। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विकास में यह कानून एक दृढ़ आधार बन गया है। युद्धोपरान्त काल में विश्व की अस्थिर स्थिति के बावजूद

इसी के सिद्धान्तों के कारण गम्भीर आर्थिक गड़बड़ी होने से बच गई।

सरकार सामान का राशन करने, मूल्य निर्धारित करने तथा माल व श्रम बाँटने जैसे कठोर कदम उठा सकती है। लेकिन एक स्वतन्त्र सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के कदम सकटकाल में ही उठाए जाते हैं। यह सकटकाल युद्ध तथा आर्थिक आपत्ति का हो सकता है। अमेरिकी सरकार का मुख्यतः अप्रत्यक्ष व्यवस्था नियमों में विश्वास है। उसके पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा वह आय तथा रोजगार में स्थिर वृद्धि कर सकती है और सतुलन के स्थानों पर होनेवाली घट-बढ़ को दूर कर सकती है।

मुद्रा सम्बन्धी नीतियाँ

सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं उनमें एक 'मुद्रा सम्बन्धी नीति' है। इस नीति का सम्बन्ध मुख्यतः बैंक व्यवस्था से होता है और इसको क्रियान्वित करने का काम 'फ़ैडरल रिज़र्व सिस्टम' के आधीन होता है। मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण के लिए रिज़र्व सिस्टम द्वारा जो उपाय काम में लाए जाते हैं उनमें एक है कथित 'आरक्षण-आवश्यकताएँ'। लगभग सात हजार प्राइवेट बैंक 'फ़ैडरल रिज़र्व सिस्टम' के सदस्य हैं। इन सदस्य बैंकों को आरक्षित कोष में अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा 'फ़ैडरल रिज़र्व बैंक' की बारह शाखाओं में से किसी एक शाखा में जमा कराना पड़ता है। इस कोष की राशियाँ फ़ैडरल रिज़र्व सिस्टम के डाइरेक्टरो के बोर्ड द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। फ़ैडरल रिज़र्व आरक्षित कोष की राशि को घटाता है तो बैंक अधिक स्वतन्त्रता के साथ ऋण दे सकते हैं और पूँजी लगा सकते हैं। उधार की दर गिरने से बाज़ार के रुख में 'नरमी' आ जाती है, अर्थात् ब्याज की दर गिर जाती है। लेकिन जब 'फ़ैडरल रिज़र्व' इन राशियों को बढ़ाता है तो स्थिति इसके विपरीत हो जाती है।

पिछले अनुभवों के आधार पर अमेरिकी बैंक 'फ़ैडरल रिज़र्व' की

कार्रवाइयो के प्रति अत्यन्त सतर्क व जागरूक रहते हैं। रिज़र्व राशियों में जरा-सी भी वृद्धि को वे खतरे का संकेत समझते हैं। इस प्रकार आरक्षित राशि में वृद्धि का प्रभाव मुद्रा सप्लाई पर तो सीधा पड़ता ही है, बैंक व्यवसायियों पर मनोवैज्ञानिक असर भी होता है जिसे मामूली नहीं समझा जा सकता।

फ़ैडरल रिज़र्व को एक और जो अधिकार प्राप्त है वह है पुनः बट्टा काटने के समय व्याज दर को ठीक करना। एक सदस्य बैंक, रिज़र्व बैंक में हूँडी (कामर्शियल पेपर) जमा कराकर या कानूनी प्रमाण देकर कि उसका ऋण चढ़ा हुआ है, जिस पर रिज़र्व बैंक पुनः बट्टा काटेगा, अपने बैंक के नकद कोष या निवेश (डिपॉजिट) में वृद्धि कर सकता है। अगर फ़ैडरल रिज़र्व ऋणों को तथा व्यय को प्रोत्साहन देना चाहता है तो पुनः बट्टा काटने की दर कम कर दी जाती है, अगर वह ऋणों को कम करना उचित समझता है तो वह बट्टे की दर बढ़ा देता है।

फ़ैडरल रिज़र्व के पास एक और उपाय यह है कि वह 'खुले बाजार में खरीदोफरोस्त' कर सकता है। बैंक इच्छानुसार खुले बाजार में सदस्य बैंकों को सरकारी सीक्युरिटियाँ बेच सकता है या खरीद सकता है। जब फ़ैडरल रिज़र्व खरीदता है मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है, जब वह बेचता है तो पूँजी पुनः रिज़र्व के पास आ जाती है और बाजार में चलन कम हो जाता है। इसके बाद जब तक गवर्नरों का बोर्ड उचित नहीं समझता वह इस स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। पुनः बट्टे की दर को ठीक करके तथा खुले बाजार में खरीदोफरोस्त द्वारा फ़ैडरल रिज़र्व मुद्रा की सप्लाई पर एक नियमित नियन्त्रण रखता है। इन उपायों का सीधा आर्थिक प्रभाव तो पड़ता ही है इसके अतिरिक्त इनमें राष्ट्र के लिए फ़ैडरल रिज़र्व की प्रवृत्तियों तथा आर्थिक स्थितियों के प्रति उसके रुख का संकेत भी मिलता है।

‘पुनः बट्टा काटने’ की कार्रवाई तथा ‘खुले बाजार में’ कार्रवाई में भारी अन्तर है। ‘खुले बाजार’ में खरीदोफरोस्त में खूबसात पुरी तरह

फैडरल रिज़र्व के हाथ में रहती है। दूसरे शब्दों में फैडरल रिज़र्व यह फैसला करता है कि बाज़ार में सरकारी सीक्युरिटियों की खरीदोफ़रोख्त देश की संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभदायक है या नहीं।

इन उपायों, जो प्रायः ऋण तथा मुद्रा सप्लाई को प्रभावित करते हैं, के अतिरिक्त तीन और अधिक चुनीदा उपाय हैं। वे हैं शेयर बाज़ार ऋण, उपभोक्ता ऋण तथा जायदाद संबंधी ऋण।

यह प्रायः माना जाता है कि 'मार्जिन विषयक आवश्यकताओं' अर्थात् सीक्युरिटियों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक नगद धन के अनुपात को नियमित करने से शेयर बाज़ार में अधिक ऋण का खतरा कम हो जाता है, तथा बाज़ार का उतार-चढ़ाव सुरक्षित सीमाओं के भीतर बना रहता है।

सरकार के पास एक और उपाय संकटकाल में उपभोक्ता ऋण पर अस्थायी रोक लगाने का है। उपभोक्ता ऋण को उचित रूप से संयमित करके उपभोक्ताओं की माँग को सप्लाई की स्थिति के अनुरूप किया जा सकता है। दूसरी ओर जब अधिक खपत आवश्यक जान पड़े तब प्रतिबंध हटा देने से उपभोक्ता माँग बढ़ाई जा सकती है।

इसी प्रकार के उपाय अपनी जायदादों, विशेषकर रहने के मकानों, पर ऋणों को नियमित करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ ऋणों को नियमित करने का अधिकार १९५० में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति को दिया गया था जब अत्यधिक मुद्रास्फीति तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं ने ऐसा ज़रूरी कर दिया था। अब ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

वित्तीय नीतियाँ

'सुदृढ़ वित्त' संबंधी पुराना सिद्धान्त यह था कि सरकार बांछनीय योजनाओं को समृद्धि की अवस्था में ही क्रियान्वित कर सकती है। लेकिन अब यह सिद्धान्त रद्द हो चुका है। कोई भी आधुनिक अर्थशास्त्री यह

सुझाव नहीं देगा कि आर्थिक मन्दी के दौरान में 'मितव्ययिता' की नीति पर चला जाय। इसके विपरीत आधुनिक आर्थिक विचारधारा यह है कि कर तथा व्यय नीतियों अर्थात् वित्तीय नीतियों में ऐसे उपयोगी उपायों की व्यवस्था रहनी चाहिए जिनके द्वारा आर्थिक उतार-चढ़ावों को दूर किया जा सके।

आर्थिक विचारधारा में यह परिवर्तन अभी हाल में ही हुआ है। तीन दशाब्दी पूर्व प्रायः ऐसा विश्वास था कि मन्दी का सामना करने के लिए सरकार मुद्रा एवं वित्तीय ढाँचे को विश्रुखलित किए बिना व्यापक कार्रवाई नहीं कर सकती।

इस प्रकार की आर्थिक विचारधारा के वातावरण में वित्तीय नीति अत्यन्त सकुचित तथा सीमित होती थी। जब अमेरिका में १९३०-३९ की भीषण मन्दी आयी तो अमेरिका उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी देश ने अपनी लोकतन्त्री व्यवस्था के फलस्वरूप पुरानी गलतियों से लाभ उठाया और तुरन्त ही मन्दी का सामना करने के लिए दृढ़ कदम उठाए गए और कानून बने।

सम्प्रति अमेरिकी सरकार के पास ऐसे वित्तीय उपाय हैं, आर्थिक सिद्धान्त हैं तथा प्रशासन-तंत्र है जिनका वह उचित उपयोग कर सकती है। ये उपाय पूर्णतः त्रुटिरहित नहीं हैं, उन्हें निरन्तर उपयुक्त कानूनों द्वारा दृढ़ एवं शक्तिशाली किया जा रहा है। लोकतंत्र का लाभ यह है कि वह खून-खर्चर या आत्म-विनाश के बिना ही समय की चुनौती का सामना कर सकता है।

अमेरिकी सरकार के पास इस समय कौन से वित्तीय उपाय हैं? कार्य की दृष्टि से उन्हें दो विभागों में बाँटा जा सकता है। कई उपाय ऐसे होते हैं जो सदैव स्वयं स्थायित्व प्रदान करनेवाले के रूप में कार्यरत रहते हैं, दूसरे वे होते हैं जिन्हें सरकार विशेष परिस्थितियों के अनुसार काम में लाती है। पहली श्रेणी में बेकारी की हालत में सहायता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, फार्म सहायता, संघीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण

बीमा तथा उर्ध्वमान आयकर आते हैं। दूसरी श्रेणी में कांग्रेस के व अधिकार आते हैं जिनके जरिए वह करो में कमी या बढोतरी कर सकती है या सार्वजनिक व्यय घटा-बढ़ा सकती है।

स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था में आय के तीन स्रोत हैं—व्यापारिक नियोजन, उपभोक्ता-व्यय तथा सरकारी खर्च। वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अधिक दबाव के बिना केवल तीसरे पर ही पूर्णतः सरकारी नियंत्रण हो सकता है। आय के अन्य दोनों साधनों पर सरकार अपना प्रभाव डाल सकती है, लेकिन यह प्रभाव मुद्रा नीति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इसलिए वित्तीय नीति का बहुत महत्त्व है विशेषकर आज के जमाने में जब सरकारी योजनाओं का विस्तार हो रहा है।

स्वयं स्थायित्व लानेवाले उपायो के क्रियान्वयन से सरकार को ऐसे उपायो को काम में लाने के लिए विचार का समय मिल जाता है जो आय तथा रोजगार के स्तरों में विशृंखलता को दूर करने के लिए आवश्यक होते हैं। विशेष रूप से व्यापार में कमी तथा बेरोजगारी में वृद्धि के समय सामाजिक सुरक्षा तथा बेकारी के दौरान में सहायता जैसे स्वयं स्थायित्व लानेवाले उपाय चुपचाप कार्यरत रहकर अनेक उपभोक्ताओं को क्रय-शक्ति प्रदान करते रहते हैं। अगर फार्म उत्पादनो की कीमतें गिरती हैं तो किसानों को सहायता दी जाती है जिससे उनकी क्रय-शक्ति बनी रहती है, और आर्थिक उन्नति के समय जैसे-जैसे आय बढ़ती है कर भी स्वयं बढ़ जाते हैं।

स्वयं स्थायित्व लानेवाले उपाय जबकि शान्त रूप से चुपचाप अपना प्रभाव डालते हैं, सरकार अधिक कठोर कानूनी कदम उठा सकती है। अगर देश की आर्थिक स्थिति गिरती हुई दिखाई देती है तो कांग्रेस अर्थ-व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कर कम कर सकती है तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए खर्च स्वीकार कर सकती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में स्वयं स्थायित्व प्रदान करनेवाले उपाय नियंत्रणकारी प्रभाव डालते हैं और सरकार कर बढ़ा देती है तथा ऐसे खर्च में कटौती कर

देती है जिनसे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है ।

कोई भी मुद्रा अथवा वित्तीय उपाय स्वयं ही आर्थिक उतार-चढ़ाव नहीं रोक सकता, लेकिन उनके सयुक्त तथा संगठित प्रयोग द्वारा आर्थिक अव्यवस्थाओं को दूर कर सकता है । मुद्रा सवधी उपाय अधिक शीघ्रता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं क्योंकि उन्हें क्रियान्वित करने का काम एक ही संस्था फ़ेडरल रिज़र्व के सुपुर्द है । स्वयं स्थायित्व प्रदान करनेवाले उपाय भी आय तथा रोजगार के बढ़ते या गिरते स्तर के अनुरूप स्वयं तेजी से काम करते हैं ।

सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र, सरकार के लिए सहायक

उपयुक्त वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी नीतियों का चुनाव किसी समूह के भरोसे नहीं छोड़ा जाता । १९४६ के रोजगारी कानून के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकारों की एक परिषद् बनायी गयी । यह परिषद् आर्थिक विकासो तथा प्रवृत्तियों के संबंध में सामयिक तथा अधिकृत सूचना एकत्रित करती है । 'अधिकतम रोजगार, उत्पादन, तथा क्रय-शक्ति बनाए रखने के लिए यह संघीय सरकार के कार्यक्रमों तथा उसकी गतिविधियों का मूल्यांकन करती है, यह राष्ट्रीय आर्थिक नीति तैयार करती है तथा राष्ट्रपति को सिफारिश करती है । इस नीति का उद्देश्य आर्थिक उतार-चढ़ावों को बचाना अथवा उसके प्रभावों को कम करना होता है । और अन्त में यह परिषद् अमेरिकी कांग्रेस के नाम आर्थिक सदेश तैयार करने में राष्ट्रपति की सहायता करती है । इस वार्षिक रिपोर्ट से इस बात का स्पष्ट रूप सामने आ जाता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति है और वह किस ओर जा रही है । शेष ससार के ऊपर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का जबरदस्त प्रभाव होने के कारण हमारे समय का यह संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख होता है ।

विश्वस्त सूचनाओं की परिगणना द्वारा अमेरिकी सरकार को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का एक संपूर्ण विस्तृत चित्र प्राप्त हो जाता है ।

१९४६ के रोजगारी कानून में व्यवस्थापक सभा के लिए भविष्य-वाणियों तथा प्रगति के मूल्यांकन की भी व्यवस्था है। प्रेजीडेण्ट की आर्थिक रिपोर्ट पर इस कानून के अन्तर्गत एक संयुक्त समिति की स्थापना की गयी। इस समिति में सात सदस्य सेनेट के तथा सात सदस्य प्रतिनिधि सभा के थे। यह समिति प्रेजीडेण्ट की आर्थिक रिपोर्ट से सम्बन्धित मामलों पर निरन्तर विचार करती है तथा सेनेट और प्रतिनिधि सभा के सामने अपनी जाँच के परिणाम और सिफारिशें पेश करती है।

×

×

×

अमेरिकी सरकार को सम्प्रति ऐसे अनेक अधिकार प्राप्त हैं जिनके द्वारा वह आर्थिक उतार-चढ़ावों पर नियंत्रण कर सकती है और आय तथा रोजगार के ऊँचे स्तर कायम रख सकती है।

एक साधारण व्यक्ति को ये सब कानून तथा उपाय अत्यन्त जटिल दिखाई देंगे—और वे हैं भी। लेकिन उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि वे आर्थिक स्थायित्व की प्राप्ति के लिए अत्यन्त निष्ठापूर्ण तथा सफल प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वैयक्तिक कार्य-स्वतंत्रता का हनन नहीं करते।

ये साधन तथा उपाय एकाएक ही नहीं खोज निकाले गए, अपितु वर्षों के प्रयासों तथा भूलों से प्राप्त अनुभव के परिणाम ही हैं। यह सलाह देना अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि 'दूसरे देश उनकी नकल करें।' एक देश की स्थिति दूसरे देश से बहुत भिन्न होती है। फिर भी, ये उपाय विचारणीय हैं। वे इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि एक लोकतंत्री व्यवस्था में अधिकांश सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा का हनन किए बिना मिल सकता है।

परिशिष्ट

इस क्रांतिकारी परिवर्तन के युग में भी सामान्य व्यक्ति की बुनियादी अभिलाषाएँ प्रायः हर देश में एक जैसी हैं। ससार के लाखों-करोड़ों व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा भौतिक सम्पन्नता चाहते हैं। इस प्रकार लक्ष्य तो समान हैं लेकिन उनकी प्राप्ति के मार्ग अलग-अलग होने के कारण भ्रान्ति फैली हुई है। व्यक्ति प्रायः ऐसे तरीकों का समर्थन या उपयोग करते हैं जो वास्तव में उनके लक्ष्यों व उनकी आशाओं को विफल कर देते हैं। इस भ्रान्ति के कारण संघर्ष व शत्रुता पैदा होने से बुनियादी उद्देश्यों की प्राप्ति में और बाधा उत्पन्न हो गयी है। परिणामतः धृष्टा, निराशा तथा किर्तव्यविमूढता ही हमारे हाथ लगी है। अगर झूठी सूचनाओं और पूर्वनिर्धारित ढंग से तथ्यों की तोड़-मरोड़ के इस गहन अन्धकार में प्रकाश डाला जाय तो दो सिद्धान्त मानवता का समर्थन और अनुरक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से स्पर्द्धा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनमें एक यह है कि व्यक्ति पर सर्वशक्तिमान् राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरे में इस बात पर बल दिया गया है कि लोकतंत्री आधार पर स्वीकृत एक कानूनी व्यवस्था में मनुष्य अपना जीवन स्वयं चलाने तथा सामान्य कल्याण व समृद्धि के कार्यों में अपना योग देने में समर्थ है।

सामने आनेवाली समस्याओं को भली प्रकार समझने के लिए किए जानेवाले अनुसंधान कार्यों में थोड़ा योग देकर मैने एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों एवं उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जो व्यक्ति को उसकी भौतिक संपन्नता के आश्वासन के साथ प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता का समर्थन करती है। यह अर्थ-व्यवस्था शोषण का करारा जवाब है। अगर इससे 'अनेक' को लाभ न पहुँचता तो यह

व्यवस्था कायम ही नहीं रह सकती थी। व्यापक उत्पादन व्यापक खपत के बिना नहीं चल सकता, और यह व्यापक क्रय-शक्ति पर आधारित है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें लोग स्वतंत्रता के साथ न केवल उत्पादक के रूप में भाग लेते हैं अपितु अपनी मेहनत का फल भी भोगते हैं।

मनुष्य की दो बड़ी अभिलाषाओं—स्वतंत्रता तथा भौतिक संपन्नता—को न केवल सिद्धान्त में बल्कि व्यवहार में पूरा करने के कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पुराने पूँजीवाद तथा सोवियत एकाधिकार-वादी उद्योगवाद पर महान् प्रगति है।

फिर भी एक सवाल उठ सकता है, कि विशाल एशिया की करोड़ों लोगो या निकट पूर्व की राजधानी में सड़को पर पश्चिम-विरोधी नारे लगानेवाले उत्तेजित युवको अथवा बीसवीं सदी की उलझनों के प्रति यकायक जागरूक होने से भौचक्के रहनेवाले लाखों अफ्रीकियों के लिए इस सबका क्या व्यावहारिक अर्थ हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि आज का समार अत्यन्त जटिल है और दिन प्रति दिन जटिलतर होता जा रहा है। मनुष्य पहले जमाने की कवि-कल्पित सरलता की ओर अब नहीं लौट सकता। इसके विपरीत सभी देशों में तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है। लोगों के सामने जो समस्या है वह ग्रामीण सरलता अथवा आधुनिक जटिलता में से एक को चुनने की नहीं है। औद्योगिकीकरण तथा जटिलता निश्चित है। चुनाव लोकतंत्र अथवा एकतंत्र में से करना है।

लोकतंत्री व्यवस्था के विरोधी यह दलील देंगे कि अल्पविकसित क्षेत्रों के अधीर राष्ट्रों के लिए इस व्यवस्था में बहुत समय लगेगा। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि बीसवीं सदी का विज्ञान अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए लोकतंत्री मार्ग अपनाने के काम को कम कठिन कर सकता है। नये उभरते राष्ट्र विज्ञान और लोकतंत्री आर्थिक सिद्धान्तों के संयोग से अपनी जनता की दबी हुई अधीरता के लिए मार्ग खोज सकते हैं। इन सिद्धान्तों से राष्ट्र अज्ञान, गरीबी तथा गतिहीनता के कुचक्र को तोड़ उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उन्नत लोकतन्त्री राष्ट्र अल्पविकसित राष्ट्रों के साथ किस प्रकार सहयोग करते हैं । औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ने के लिए संघर्षरत राष्ट्रों के प्रति औद्योगिक राष्ट्रों का उत्तरदायित्व वर्णनातीत और उनका केवल यह उत्तरदायित्व ही नहीं कि वे अल्पविकसित राष्ट्रों की सहायता करें अपितु यह तो उनके स्वार्थ का भी तकाजा है । उद्जन बमों तथा प्रक्षेप-णास्त्रों का युद्ध शायद कभी न हो, लेकिन लोकतंत्र तथा एकतंत्र के बीच तीव्र संघर्ष निरन्तर चल रहा है । यहाँ तक कि यह लड़ाई अर्थ-व्यवस्थाओं के रूप में भी चल रही है । यह संघर्ष शायद ही कभी चमत्कारपूर्ण हो, फिर भी इसका परिणाम भविष्य के लिए संसार का निश्चय करेगा ।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह है कि यह अत्यन्त लचीली है । यह विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप अपने को ढाल लेती है । राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार यह सिकुड़ सकती है या विस्तृत हो सकती है । १८६१ में अब्राहम लिंकन ने विनोद में लिखा था :

“सरकार का यथार्थ में कार्य यह है कि वह एक जन-समुदाय के लिए उन सब कार्यों को करे, जो उन्हें करने चाहिए लेकिन जिन्हे वे कर नहीं सकते, या अपने लिए पृथक् रूप से, या वैयक्तिक रूप से उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते ।”

सरकार के इस सिद्धान्त को अधिकांश अमेरिकी सिद्धान्त रूप से और व्यवहार में समझ गए हैं । इसके अन्तर्गत विशाल निजी उद्योग, जैसे जनरल मोटर्स और उतने ही बड़े सरकारी उद्योग जैसे टैनेसी घाटी अधिकरण, या ओक रिज, टैनेसी तथा हैनफोर्ड, वाशिंगटन में स्थित अणु-कारखाने आ जाते हैं । औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पदार्पण करनेवाले राष्ट्र इस सिद्धान्त को अपने देश की परिस्थिति और समस्याओं के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं । विभिन्न देशों में सरकारी उत्तरदायित्व

में पर्याप्त अन्तर हो सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जनता एकतन्त्र शासन की तकलीफों तथा अप्रतिष्ठा से बच जाती है।

इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेने का यह अर्थ कदापि नहीं कि ससार अमेरिकी रंग में रंग जाएगा।

आज के एकतन्त्री सिद्धान्त ससार की आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों को एक विशिष्ट मण्डल के हाथ में पूर्ण सत्ता सौंपकर दूर करने का वचन देते हैं। अनुभव से पता चला है कि ऐसी व्यवस्था में मानवीय स्वतन्त्रता तथा अनेक मानवीय जीवनों का बलिदान हो जाता है। यहाँ तक कि उस विशिष्ट मण्डल के सदस्य भी स्वयं सुरक्षित नहीं होते। इसके अतिरिक्त एकतन्त्र शासन द्वारा बड़े पैमाने पर जो कुर्बानियाँ कराई जाती हैं, आवश्यक नहीं कि उनके अनुरूप ही बड़ी मात्रा में जनता को भौतिक लाभ प्राप्त हो। दूसरी ओर अमेरिकी व्यवस्था के अनुभव से पता चला है कि एक स्वतंत्र समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है तथा वास्तविक प्रगति की जा सकती है।

लोकतन्त्री औद्योगिकीकरण की अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक आजमाया हुआ तरीका है, जो व्यावहारिक क्षेत्र में प्रमाणित हो चुका है तथा अधिकाधिक जनता के लिए उच्च जीवन-स्तर प्रदान करनेवाला है।

इस पुस्तक में पाठक के सामने अमेरिकी अर्थ व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों तथा लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। पाठक अब अपना निर्णय स्वयं करें।